साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 9 अंक 36 प्रति सोमवार इंदौर, 20 से 26 अप्रैल 2015 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

पूंजीपतियों की रखैल भुखेरेजन पार्टी का पहला बजट 15-16

गरीबों और मध्यमवर्गीय के शोषण का बजट- कैसे अच्छे दिन

बजट आंकड़ों की बाजीगरी में अपनों का पोषण और निरीहों के शोषण की व्यवस्था

स्मार्ट सिटी, मेट्रो, बुलेट ट्रेन के नाम पर हजम करेंगे हजारों करोड़, पूंजीपतियों और कार्पोरेट की पहुंचाएगे फायदा

चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्या बना, सत्ता को वापसी जागीर समझ, पूंजीपतियों के पोषण और निरीहों के शोषण में जुट गया बजट में 15-16 में मध्यमवर्गीय और गरीबों के लिए विशुक्त छलता हुआ सिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा निराशा सेवकों को हुई जहां आयकर में सीधी कोई छूट नहीं दी गई। वैसे भी भारत में बजट झूठे आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा होती हैं, वास्तविकता से परे, इस बजट में जो छलावे किए गए हैं। वो शायद भारतीय स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा ही है, जो केवल पूंजीपतियों के भविष्य में मजबूती प्रदान करेगा, जो स्वाभाविक रूप से निर्धनों और मध्यमवर्गीय के शोषण के काम आएगा, सेवाकर के दायरें और देरों को बढ़ाकर जिसका सीधा भार गरीबों और निम्न से लेकर उच्च मध्यमवर्गीय से ही वसूला जाएगा।

इस बजट में निर्धनों और बुजुर्गों के साथ भी भारी मजाक किया गया हैं। रु. 2000 प्रतिवर्ष की पेंशन, जिसमें रु. 1000/- केन्द्र व शासन सरकार को भुगतान करना है। रु. 2000 प्रति वर्ष में क्या बुजुर्ग वर्ष भर जीवित रह लेगा, जो केवल सरकारी सहायता के नाम

बुजुर्गों पर कलंक सिद्ध होगी, क्योंकि रु. 2000 की औपचारिकताओं में उससे रु. 4000 की वसूली सरकारी कर्मचारी ही कर लेगें।

ग्रामीण विकास और रोजगार के नाम रु. 346993 करोड़ जो प्रावधान किया गया है, जो सीधा जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के माध्यम से 60 प्रश सीधा ही हजम कर लिया जाता है, ग्रामीणों के हाथ में मात्र 25 प्रश लोगों को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। भारत में मोदी स्मार्ट सिटी के नाम पर वास्तविकता मे जिस चकाचौंध में स्वयं और जनता को दिवास्पन दिखा रहा है, उसका दूसरा पहलू केवल नगरीय सरंचना के नाम क्रांकीट जंगल खड़ा कर, जनता को प्राकृतिक वातावरण से दूर कर ग्रामों और नगरों की उलझनों को बढ़ाकर जनमानस में असंतोष पैदा ही करेगा, दूसरी और ग्रामोद्योग और ग्राम विकास जो इस राष्ट्र की वास्तविकता आवश्यकता थी, इन सबके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लघु उद्योगों के विकास की बात उसके लिए प्रावधान भी नहीं किए गए हैं। जबकि यथार्थ में लघु उद्योगों के विकास से रोजगार भी ज्यादा मिलते और कम लागत पर उत्पादन भी ज्यादा मिलता, बड़ी योजनाओं में कमीशन भी अरबों रु. में मिलता हैं। इसी बजट में जो 50 लाख नौकरियां देने की जो बात कही गई है वो केवल कार्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देकर,उनसे रोजगार देने की अपेक्षा है।

(शेष पेज 11 पर)

आधार कार्ड के नाम, जनधन के रु. 7488 करोड़ की बर्बादी केवल जालसाजी के लिए

आधार कार्ड या आमजन की बर्बादी व मृत्युनामा

सरकारी गिद्धों की नोंच से पूर्व की ठगी, बैंक खातों को खाली करना, अपराधियों की पौ बारह, आमजन मरे बेचारा

भारत का पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की सरकारों में सबसे बड़ा जालसाज, डकैत, धूर्त वकील है, जिसने जनता को राजीव की सरकार से वित्त मंत्री रहते हुए, हाऊसिंग फाइनेंस, प्लांटेशन कृषि कं. के नाम 40000 कं. मे माध्यम से रु. 40 लाख करोड़ लुटवाया, हर्षद मेहता कांड में शेयर बाजार के माध्यम से अंबानी, टाटा, आईटीसी, जैसी कं. को लूट के गुर देकर वहां भी 1988-92-95 के बीच करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ लेकर डुबो दिया गया। हजारों सार्वजनिक कं. के निर्गम किए गए, उप कं. के अते-पते ही नहीं है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कं. का ये और इसकी बीबी वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवाओं के नाम अरबों रु. कमा बड़ी-बड़ी बैंकों से लाखों करोड़ 5 रु. वित्तीय सहायता दिलवाकर डूबत ऋण की भरपाई जनता के पैसे से बैंकों की भरपाई करवाई गई, रिजर्व बैंक से लेकर सारी सरकारी बैंकों बीमा कं. में दक्षिण भारतीयों को जो इसके मिलने-जुलने वाले थे, मोटा धन लेकर बैठाया गया, जिन्होंने अरबों रु. की जालसाजियां की, बीमा कं. में चिकित्सा बीमा में तृतीय पक्ष प्रशासक की लगभग 20 से ज्यादा कं. जो दलाली कर अस्पतालों से सेटिंग कर बिना वास्तविक हितग्राही की क्षति पूर्ति के ही अरबों रुपए चारों सरकारी रु. के चिटफंउ घोटालें में भी इसकी पत्नी का नाम आया था, जनता ही हर बार लूट पिट कर चुप हो जाती है,

(शेष पेज 10 पर)

म.प्र. बजट 15-16 लूट की पूरी छूट की व्यवस्था

ऋण लेकर घी पी रहे - कहां जा रहा राजस्व, बढ़ाये कर

सड़कों, बिजली, शिक्षा, परिवहन से तो पहले ही जनता को लूट रहे, बजट में व्यवस्था हजम करने के लिये

म.प्र. में भाजपा के शिवराज को तीसरी बार सत्ता क्या मिली, गणों के साथ चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार का तांडव शुरु डंके की चोट पर किया जाने लगा, शिवराज की सरकार के वर्तमान वित्तमंत्री बुंदेलखंडी बनिया जयंत मलैय्या ने प्रस्तुत किया। हर आवंटन में 25 से 40% की लूट की व्यवस्था की गई, दूसरी तरफ शिवराज ने बाजार से जनता के नाम रु. डेढ़ लाख करोड़ का कर्ज लेकर घी

पीने लगा है, आखिर जब पूर्व वित्तमंत्री राघवजी, जिसका इस धूर्त शिवराज षड्यंत्रों से पूरी बर्बादी की क्योंकि वह मुख्यमंत्री बनने की कतार में था, ने तो 9 वर्ष के शासनकाल में न तो भुगतान रोके न फर्ज लिया और न ही ओवर ड्राफ्ट से प्रदेश की जनता को वेतन बांटा, परन्तु जयंत मलैया के वित्तमंत्री बनते ही इस उद्योगपति ने अपने फायदे के लिए चारों तरफ लूट-पाट के लिए तांडव मचाना शुरू कर दिया,

(शेष पेज 5 पर)

आखिर कमीशनखोरी में मोदी, मनमोहन से आगे

क्यों खरीद रहे समय बाधित परमाणु ऊर्जा संयंत्र

देश में 15 से ज्यादा स्थानों पर 7.6% थोरियम की खदाने, जल, पतन, सौर ऊर्जा सुरक्षित, सस्ते, दीर्घकालिक विकल्प हैं, हमारी धरती पर

राष्ट्र में मोदी की सरकार वही सब कर रही है, जिसका वह विपक्ष में रहकर विरोध करती थी, चाहे वह विदेशी निवेश, बैंकिग, बीमा, रक्षा, विद्युत, फुटकर व्यवसाय, सड़कों, रेलें, बहुमुखी औद्योगिक, शहरीय अधोसंरचना हो, इस प्रकार यह चायवाला, झाड़ूबाज प्रधानमंत्री देश को कांग्रेस से ज्यादा तेजगति से विदेशी गुलामी की राह पर राष्ट्र को मात्र अपने मोटे कमीशन के चक्कर में धकेलने में लगा हैं, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण उसने हर कदम पर दिया है। इस गिद्ध ने जनता को कदम-कदम पर नोंचने की व्यवस्था कर दी हैं।

जिस परमाणु समझौते का भाजपा विपक्ष में रहकर घोर विरोध करती थी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के तत्कालीन मनमोहन सरकार को माना करती थी, उसी पर मोदी ने आखिर अमेरिकी शर्तों के साथ हस्ताक्षर कर ही दिये, जबकि आस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, रूस से जो भी परमाणु समझौते हुए, उन सबने अपने समय बाधिक व पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के बाद नष्ट किये जाने योग्य, जो कि पूर्णतः रेडियोधर्मी हो चुके थे। उन्हीं को रंगाई-पुताई कर भारत में स्थापित किया जायेगा, अर्थात जिस कचरे को नष्ट करने में उन्हें भारी समस्या थी, वही सबकुछ उन्होंने इसे सौंपने में ही भलाई समझी, जिसमें मोटा कमीशन इन्हें देकर अपना माल भी बेचा और रेडियोधर्मिता से धधकते प्लांटों से मुक्ति भी मिल गई।

यही कारण था कि दुर्घटना होने पर कोई भी विक्रेता और विदेशी बीमा कंपनियां इससे उत्पन्न क्षति की पूर्ति के तैयार नहीं थी और सारे परमाणु समझौते इसी बात को लेकर अटके थे और मोदी ने इस शर्त को ही हटाकर राष्ट्र की धरती पर कचरा रेडियोधर्मी प्लांटों से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिये मैदान साफ कर दिया।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों यथा बारहमासी नदियों वर्ष के 8 माह कड़क धूप, 10 से 40 कि.मी. की गति से बहने वाली हवाओं से ही हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करा सकते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले परमाणु संयंत्र खरीदो फिर संवर्धित यूरेनियम खरीदो, जिसके लिये अरबों रु. की विदेशी मुद्रा भुगतान करो। जबकि भारत में 16 से ज्यादा स्थानों पर 7.6% थोरियम अयस्कों के दुनिया के सबसे बड़े भंडार हिमालय से लेकर केरल के सुमद्री तटों की रेती में भरे पड़े हैं।

यदि हमने अपने यहां प्लांट और भट्ठिां तैयार करके थोरियम का उपयोग करते तो न केवल विदेशी मुद्रा वरन यूरेनियम आयात की विदेशों पर निर्भरता समाप्त हो जाती, परन्तु मुखेरों को मोटा कमीशन तो विदेशों से ही मिलेगा। विदेश घूमने का बहाना मिलेगा, बेचारा चायवाला, फिर रु. 10 लाख का सूट कैसे पहनेगा, देश की जनता पर करों का बोध कैसे लादेगा।

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मध्यमवर्गीय

पृथ्वी पर मानव सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कीय सोच का प्राणी है, प्रकृति ने सभी प्राणियों को मस्तिष्क और सोचने, समझने की क्षमताएं दी है। सभी प्राणी प्रकृतिक प्रदत्त क्षमताओं के अनुसार धरती पर जन्म से लेकर मृत्यु तक इस पृथ्वी के रंगमंच पर अपनी भूमिका का संवहन करता है। संचालन कर्ता तो केवल स्वयं प्रकृति हैं, जिसे मनुष्य की मात्रा में, समझदारी, समझ, शास्त्रों, वेदों, पुराणों के अनुसार परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, अरिहंत कहा जाता है, पुकारा जाता है।

निसंदेह पृथ्वी पर प्रकृति ने सभी प्राणियों, मनुष्यों से लेकर जीव-जंतुओं, वनस्पति,जल, थल और नमचरों ,दृष्य और अहृण्य सभी की भूमिकाओं स्पष्ट निश्चित हैं। सभी अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए उने सिद्धांतों का पालन करते हुए पृथ्वी पर जीवन यात्रा पूरी करते हैं। मनुष्यों के साथ ही अन्य सभी जीवों, जानवरों में सभी को प्रकृति के अनुकूल रहकर ही जीवन यापन सभी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर ही करते हैं।

पृथ्वी पर मनुष्य एक तरफ सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, तो दूसरी और उसी बुद्धिमत्ता के कारण घोर स्वार्थी, मक्कार और शैतान प्राणी हैं, जिसका मूल उद्देश्य अपने सुख, समृद्धि, शक्ति का अधिकतम संग्रह, जिसमें न केवल धन, संपत्ति आदि के भ्रम को पूरा करने के लिए धूर्तता पूर्ण छल, कपट, झूठ आदि के सहारे अपनी ही मानव जाति के अधिकारों का हनन में जीवन पर्यंत व्यस्त रहता है, जबकि वह जानता है कि यह सब मिथ्या है, फिर भी दूसरों के शोषण से बाज नहीं आता, और अपनी स्वार्थ लिप्सा को पूर्ण करने वह अपनी बुद्धि का छल कपट में प्रयोग कर वाचालता से शक्ति, धन, संपत्ति के संग्रह से मनुष्यों को भ्रमिक कर हांकता है, जिसे हम नेता कहते हैं, जो जितना बड़ा वाचाल तो उतना बड़ा वाचाल वह उतना बड़ा नेता, वर्तमान में सबसे बड़ा वाचाल हमारा प्रधानमंत्री मोदी है, जिसने अपनी वाचालियत से भारत की सत्ता हथियां ली, वाचालियत से सत्ता हथियाना और शासन चलाना दो अलग-अलग ध्रुव है।

पूरे विश्व में मनुष्यों में अमीर, गरीब के नीचे जो मध्यमवर्गीय है, यथार्थ में वही लोग है, जो दुनिया के देशों में इन वाचाल नेताओं की वाचलियत, छल, कपट के सबसे बड़े शिकार होते हैं। जो अपनी मेहनत कर अपने बच्चों को पालते हुए उन्हें अधिकतम शिक्षित करते हैं। समाज के नियमों, कानूनों का पालन करते हैं। सरकार के नियमानुसार कर चुकाते हैं। पानी, बिजली, धन, संपत्ति कर बच्चों की शिक्षा शुल्क से लेकर नेताओं, गुंडों, डकैतों का भी मुश्किलों में जीवन यापन करते हुए शुल्क चुकाते हैं। सिर झुकाकर चलते हुए जीवन यापन करते हैं। क्योंकि बड़ा मानता नहीं, छोटा जानता नहीं, पिस्ता हर जगह मध्यमवर्गीय है। जो सरकारें, नगर निगम, स्कूल, विद्युत कं., केबल, फोन कं., बीमा, बैंक कं., परिवहन, रेलवे, शॉपिंग मॉल, टॉकीज आदि सब चलाता है, जिसके दम परन केवल सरकारें बनती व चलती है। वरन् उसके दम पर ही बाजार, प्रशासन और कानून व्यवस्थाएं चलती है।

इसी मध्यमवर्गीय के दम पर, इस बार भाजपा की सरकार और उसका वाचाल नेता मोदी प्रधानमंत्री बन बैठा, जब इसी को राहत और सुविधाएं देने की बात बजट में की गई तो इस वर्तमान भाजपा के वित्तमंत्री अरुण जेटली जो पेशे से वकील है, ने न केवल बाबाजी का ठुल्लू दिखाया वरन् उनका अपमान भी किया गया, कि मध्यमवर्गीय को स्वयं अपने दम पर चलना चाहिए, तो उनको मध्यमवर्गीय जनता की तरफ से हमारा जवाब है, कि हम तो हमारे दम पर चलने के ही आदि है। पर आप क्यों हमारे दम पर चल रहे हैं। दूसरी कि हम से ही वसूले गए धन से गरीबों का तो ठीक अमीरों की झोली भरने की आड़ में, अपना मोटा कमीशन क्यों हजम कर रहे हैं। क्यों बैंकों को राहत पैकेज जिसमें हमारा धन है। देकर, अमीरों द्वारा लिया गया कर्ज की भरपाई कर रहे हैं। धूर्तों तुम्हारी नेतागिरी की आड़ में लूट और डकैती, तो तुम बिजली, पानी,सड़के, डीजल, गैस,संचार सेवाएं, परिवहन सेवाओं आदि के माध्यमों से प्रतिदिन लाखों-करोड़ में होती है। डालकर जो सत्ता सुख भोग रहे हो, वो मध्यम वर्गीय के दम पर ही हैं,और वहीं मध्यमवर्गीय जो सारी परेशानियां स्वयं झेलकर भी तुम्हारी कानूनी और गैरकानूनी बत्तमीजियों चुपचाप आंख भींचकर, शांति से जीवन यापन करता हुआ, तुम जैसे हरामखोर जालसाजों की दुकानदारियों को चला रहा है। रक्त पिपासु दानवों, तुम उन मुद्रा राक्षसों की कठपुतली बन उनके लिए, इन मध्यमवर्गीयों की मेहनत का रक्तपान कर ही दम से फूल रहे हो, अन्यथा तुम चाय का ठेला लगाकर, जीवन यापन कर रहे होते। नीति व अर्थशास्त्री चाणक्य ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही सत्ता रूपी वैश्या के पूंजीपतियों के इशारे पर नृत्य करने की बात कही थी, तो फिर वर्तमान में सत्ताधीश पूंजीपतियों के इशारों पर नाचकर आम मध्यमवर्गीय का शोषण कर रहे है, तो नया तो कुछ भी नहीं। है वाचाल सत्ताधीशों, सत्ता पाकर दंभी हो जाना स्वाभाविक है, पर तुम्हारी सत्ता को चलाने वाला यही मध्यमवर्गीय यदि तुम्हारे सामने, तुम्हारे शोषण के प्रतिकार में खड़ा हो गया तो सत्ता तो दूर अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा, प्रकृति अवसर सबको ही देती है।

लोक बनाम लूट तंत्र में कानून अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण के लिए होते हैं

सरकारों ने सूचना अधिकार का हर स्तर पर किया बलात्कार

मुद्रा राक्षसों की कटपुतली महाधूर्त को मोदी प्रेम से लेकर सरपंच तक सबका सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत जानकारी देने में तन-मन रखलित होने लगता है। जन-धन से सत्ता चलाने वाले सत्ताधीश सत्ता को बाप की जागीर समझते हैं,

जनता का हक है कि वो जाने उसके वसूले गए करों के धन, का राष्ट्रपति भवन से लेकर न्यायालयों, सेना, सशस्त्र बल, सीबीआई केन्द्र व राज्य सरकारों के हर विभागों से लेकर गांवों की पंचायतों के साथ ही शासन धन का उपयोग करने वाली सभी अशासकीय संस्थाओं अधि. की धारा 2 ज के अनुसार जानकारियां बिना कारण जाने उपलब्ध करवाएं, इसके विपरीत केन्द्र के वैक्लपिक सार्वजनिक कष्ट निराकरण मंत्रालय से लेकर, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, राज्यों के सभी उच्च न्यायालयों व केन्द्रीय सूचना आयोग से लेकर राज्यों के सूचना आयोगों तक ने सभी तक इस कानून की मूल भावना का गला घोंट कर, मनमानी व्याख्या कर, पूरे राष्ट्र में भ्रष्टाचार बढ़ाने जालसाजों को बचाने और आवेदकों को परेशान कर सूचनाएं न देने की मुहिम छेड़ रखी है, जबकि भ्रष्टाचार के विरूद्ध भाषण देने में बड़े से बड़ा जालसाज और भ्रष्ट भी रामायण सुनाने को तैयार रहता है। भारत की धरती पर सभ्यता में इहिास में सहस्त्रों वर्षों से देवताओं और दानवों की भरमार रही है, और आम आदमी उनका निवाला बन रहा है। वर्तमान में भी सत्ताधीशों और मुद्रा राक्षसों रूपी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बीच में आम आदमी ही पिस रहा है। दोनों ही उसका रक्तपान कर अपने आप को महान समझ रहे हैं। जबकि दोनों ही आम आदमी की मेहनत से किए अन्न-धन के उपार्जन का भोग अनादिकाल से वर्तमान तक और भविष्य में भी करते रहेंगे, अर्थात आम जनता सदा से ही पिसती रही, सत्ताएं उसका शोषण करती रही हैं, करती रहेगी।

लोकतंत्र यथार्थ में लूट तंत्र का पर्याय न केवल भारत में वरन पृथ्वी पर बसे, विकसित, विकसित हो रहे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की यही कहानी है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, चाहे व अमेरिका, ब्रिटेन, चीन भारत सभी का हाल है, सभी चुने हुए येन-केन प्रकरण चुनाव जीतकर जनता को लूटने में पूंजीपतियों से लुटवाकर खुद कमाई करते हैं। खुलकर भ्रष्टाचार करना इनका परम ध्येय होता है, जनता अनादिकाल से सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की नूरा कुश्ती की कठपुतली बन शोषित होती रही, जिसे लोकतंत्र की अवधारणा जनता से जनता के चुने गए प्रतिनिधि, जनता से वसूले गए करों के उपयोग का पाई-पाई हिसाब देंगे।

जिससे विधान लागू होने के 55 वर्ष बाद लागू किया गया, जिस समय लागू किया गया था, उस समय न्यायालयों से लेकर, केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों से सभी राज्यों के कार्यालयों ने मंत्रालयों से लेकर पंचायतों तक सभी में भारी दहशत थी, परंतु जैसे-जैसे समय गुजरता गया स्वयं अपनी सच्चाइयां सामने आते देख बौखलाने लगे, फिर कानून मंत्रालय से लेकर, व्यक्तिगत व जन कष्ट निवारण मंत्रालय तक में बैठे धूर्त मक्कारों इंडियन एव्यूसिंग सर्विस लॉबी से लेकर नीचे तक अर्थात राज्यों के मुख्य सचिव मंत्रालयों के प्रधान सचिवों तक जो कि स्वयं हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष हजम कर जाते हैं।

इसका यथार्थ टीनू जोशी और अरविन्द जोशी है। क्योंकि जो पैसा इनका पकड़ा गया, दावे के साथ 5 प्रश भी नहीं है, उसने मिलकर मनचाहे तरीके से जानकारी देने से बचने के लिए खूब मनचाहे तरीके से न केवल संशोधन किए वरन् अपने तरीके से ही कानून की व्याख्या भी की, धारा 2 न की व्याख्या को स्पष्ट होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश के न केवल सभी उच्च न्यायालयों के साथ केन्द्रीय सूचना आयुक्तों के साथ राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों को तकने भी मन माने ढंग से कर सभी विभागों के मंत्रालयों से लेकर निचले स्तर तक जानकारी न देने के बहाने के रूप में आवेदक को ही तृतीय पक्ष ठहराकर जाकनारी देने से मना कर दिया गया।

दूसरी ओर फिर न केवल केन्द्रीय सूचना आयोग से लेकर राज्यों के सूचना आयोगों तक में प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खास चुन-चुन कर ऐसे भ्रष्ट, किस्में, ऐतिहासिक जालसाज अधिकारियों व अन्य को बैठाया ताकि वो सरकारी अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक की तरफदारी करें, आवेदकों 3 से 5 वर्ष तक लटकाकर रखें ताकि आवेदक के पक्ष में फैसला देना मजबूरी बन भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क जानकारी दिलवाकर, जो कि 3 से 5 वर्ष बाद उसके किसी काम की नहीं रही होगी, अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लें। हां इसके विपरीत सरकारी अधिकारियों को सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त से लेकर अन्य सभी आयुक्त, आवेदक को धारा 19 (8) में क्षतिपूर्ति और 19 (6) स में दंड की धमकी देकर आसानी से रु. 10 से 25000 झटककर अवश्य लें जैसा कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान सभी आयुक्त न केवल मप्र में वरन केन्द्रीय सूचना आयुक्त से लेकर सभी राज्यों के सूचना आयोगों में खुलकर वसूली कर रहे हैं। 90 प्रश आवेदकों की सूचना आयोग में जाने पर निराशा ही हाथ लगती हैं, क्योंकि एक तरफ 2 से 5 वर्ष तक सुनवाई ही नहीं होती दूसरी तरफ आवेदक राज्यों की राजधानी जाने तक रु. 2-5 हजार बर्बाद करें, फिर सूचना आयोग में बैठे धूर्त और मक्कारों की फौज क्षतिपूर्ति और दंड तो दूर जानकारी के आदेश कर भी देता हैं, तो भी संबंधित विभाग पत्र नहीं मिला, देखते हैं। भेज देंगे कहकर भी महीनों तक टरकाते रहते हैं।

जबकि केन्द्रीय सूचना आयोग से लेकर, राज्यों के सूचना आयोगों में बैठे 95 प्रश धूर्तायुक्तों को न तो पूरा कानून का ज्ञान होता है, न न्यास के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। यहां तक कि मूल कानून की व्याख्या भी अपने तरीके से कर, सरकारी अधिकारियों की उन्हें ही अपने निर्णयों से ऐसे पारदर्शिता विरोधी जानकारी न देने, बिलकुल भी मेहनत न करनी पड़े, जैसे हथियार सौंप दिए हैं, ताकि वो साफ बच निकलें इसमें सबसे ज्यादा इन हमराखोर आयुक्तोंकं ने मजाक उड़ाया धारा 2 नं., तृतीय पक्ष जिसका तात्पर्य जो नागरिक नहीं है, जिसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल हैं, अर्थात जो भारत का नागरिक नहीं है व सभी तृतीय पक्षकार माने जाएंगे पर इस तृतीय पक्ष की परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर न केवल उच्च न्यायालयों तक ने अपनी तरह से परिभाषित किया, जानबूझकर आवेदक को जानकारी देने से वंचित किया गया जिससे जालसाज अधिकारियों के हौंसले ही बुलंद हुए और कानून की पारदर्शिता की मंशा का गला घोंटा गया जबकि धारा 2 अ स्पष्ट करती हैं, कि वे सभी दस्तावेज जो शासकीय कार्यों से संबंधित, शासन के पास संग्रहित हैं, निर्धारित शुल्क से लेकर दिए जाने चाहिए, परंतु कभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी कहकर, कभी गोपनीयता की दुहाई देकर, कभी व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला देकर आवेदकों को प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही कुछ न्यायालयों ने तो यहां तक निर्णय दिए हैं, कि बिना सार्वजनिक हित सिद्ध किए दस्तावेज नहीं दिए जाए, जबकि सूचना कानून में स्पष्ट लिखा गया है, कि बिना कारण दिए जाए।

यही कारण है कि 50 प्रश आरक्षित वर्ग में कार्यरत फर्जी प्रमाण पत्रों फर्जी मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर आसानी से अरबों रुपए का चूना सरकार को लगाकर हजम कर रहे हैं। परंतु वरिष्ठ अधिकारी से फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहे, न्यायाधीशों से लेकर आई.ए.एस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएसएस व सभी कर्मचारी से मोटी रकम ऐंडकर आवेदकों की जानकारियों से वंचित कर देते हैं। जिसमें व्यावसायिक आरक्षित वर्गों को न केवल नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वरन् असली की पदोन्नतियों में भी उचित लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ जिन्हें कानूनों का पालन करने और करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे ही कानून की न केवल धज्जियां उड़ा रहे हैं।

वरन् दस्तावेजों की फोटो कॉपी शुल्क भी मनमाना यहां तक कि एक पेज की फोटो कॉपी का रु. 600 शुल्क मांगकर जानकारी देने से मनाकर दिया गया इसमें सर्वप्रथम थानों से लेकर, पुलिस मुख्यालय, अधिकांश न्यायालय, जिला अधिवक्ता संघ, राज्य अधिवक्ता संघ और भारतीय अधिवक्ता परिषद हैं, जिन्हें सूचना के अधिकार में जानकारी देना घोर अपमान लगता हैं, 90 प्रश समय पर जवाब ही नहीं दिए जाते हैं, राज्य अधिवक्ता परिषद रु. 10 प्रति कॉपी मांगता है वहां भारतीय अधिवक्ता परिषद ने रु. 600 प्रति कॉपी का पत्र भेजकर 4 माह मांग पत्र लौटा दिया था, अर्थात ये सब भारतीय कानूनों से ऊपर है, सूचना के अधिकार में जानकारी देना इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, जिसके उदाहरण है। क्या भारत का कानून मंत्रालय इनसे पूछताछ कर इनके विरूद्ध कार्रवाई करेगा।

वोटों के भुखोंरों श्वान नेताओं की फौज है, हिन्दुओं की दुश्मन

हिन्दुओं के अंतिम राष्ट्र भारत से मिटा देगी हिन्दुओं को सरकारी नीतियां

हिन्दुओं के सबसे बड़े शत्रु हिन्दू हैं, भाजपा भी कर रही है हिन्दुओं का शोषण

भारत में जनसंख्या के आंकड़ें आखिर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ के 2011 के सार्वजनिक कर दिए, जिसकी सच्चाई पर कांग्रेस ने 30 वर्ष से पर्दा डाल रखा था, स्वयं केंद्रीय सरकार के जातिगत जनगणना समंकों ने जो यथार्थ प्रकट किया है, वह सिद्ध करता है कि सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, उसके सारे कानूनों का डंडा केवल हिन्दुओं पर 'कमजोर कड़ी कौन' हिन्दूओं पर ही चला, दो बच्चों का मामला हो या बाल विवाह, सारे कानून केवल हिन्दुओं पर ही लगे, लगाए जाते हैं। जबकि इन नेता मंत्रियों से लेकर सारे भ्रष्ट सरकारी तंत्र में बैठे शूकरों की फौज किसी भी मामले में मुस्लिमों से कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं करती, चाहे वह बाल विवाह हो या दो बच्चों का मामला जबकि पूरे केरल, आंध्रप्रदेश, बंगाल, उप्र , मप्र में न केवल मुस्लिम नाबालिग युवतियों का न केवल विवाह संपन्न होता है, वरन् खाड़ी देशों में भी पहुंचा दी जाती है।

तब कहां मर जाता है, मानवाधिकार आयोग, महिला बाल विकास पुलिस तब तो सारे जालसाज चुप बैठे रहते हैं, दूसरी तरफ यदि किसी सरकारी कर्मचारी के दो बच्चों से ज्यादा पैसे हो गए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि वहीं सरकारी मुस्लिम कर्मचारी 15 बच्चे, 5 बीवियां रखकर भी पैदा करें, तो भी सब चुप रहते हैं। फिर उनकी समाज में भी इसे शान समझा जाता है। वहीं यदि किसी हिन्दू महिला ने 3 बच्चे भी पैदा कर लिए तो गली-मोहल्लों से लेकर उसके अपने परिवार वाले भी उसको ताने मारते हैं। जबकि यथार्थ यह है कि, दो बच्चों का परिवार न केवल मां बाप के लिए वरन पूरेहिन्दू समाज के लिए अभिषाप बन गया है, यदि एक बेटा-बेटी है, तो और दो बेटे या दो बेटी हैं तो और बड़ा अभिषाप है, और जिनके एक है,तो वे और दो बेटे या दो बेटी है, तो वो और बड़ा अभिषाप है, जो न केवल मां-बाप के लिए, बल्कि स्वयं एक बेटा या बेटी के लिए स्वयं भी दो बच्चे स्वयं अपने आप में अगर बेटा है बेटी है, तो सारी अपेक्षाएं अपने बेटे से, सारी जिम्मेदारी बेटे पर, वहां तक तो ठीक है अगर बेटा है तो और बेटी है तो मां-बाप अकेला है या अकेली है के चक्कर में सारा न केवल प्यार उड़ेलते है, वरन सारी अपेक्षाएं भी उसी से करते हैं।

दूसरी ओर उस बेटा-बेटी को हिायत उक्त किस्म का बना देते हैं। जो बाद में न केवल मां-बाप के लिए वरन स्वयं और समाज के लिए भी घातक होता है, फिर स्वयं अकेला बेटा-बेटी छोटी-छोटी परेशानियों से हारकर आत्म हत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। जबकि 4 भाई-बहनों में एक दूसरे को संभालने, सहारे के साथ मां-बाप भी सुरक्षित रहते है। अब वर्तमान में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जब छोटी उम्र में ही अकेलेपन से, अवसाद से छोटी उम्र में ही लड़के-लड़कियां आत्महत्या करने लगे हैं। मां-बाप बच्चों की परवरिश के लिए कमाने चले गए, अकेले अवसाद में घिरे किसी ने फांसी लगा ली, कोई किसी से मर गया, इससे भारत की केन्द्र व राज्य सरकारों की विदेशी बहुराष्ट्रीय कं., इसाई मिशनरियों के इशारे पर नाचकर छोटे परिवार की अवधारणा भले ही परवान चढ़ गई हो परंतु एक बच्चे की इस प्रकार अकाल मृत्यु से परिवार टूटा, मां-बाप अवसाद का शिकार हुआ, तो समाज को नुकसान के साथ राष्ट्र को भी नुकसान हुआ, स्थिति यह बनी कि सरकार की थींपी गई इन बत्तमीजियों से हिन्दुओं की जनसंख्या घट रही है, स्वयं सरकार के अनुसार हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 प्रश प्रतिवर्ष है, वहीं मुर्स्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 10.4 प्रश प्रतिवर्ष, अर्थात अगले 10 वर्ष वर्ष बाद हमारी जनसंख्या 70 करोड़ तो वो 55 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो जाएंगे, फिर जैसे काश्मीर में 19 फर 89 को रात में अचानक हिन्दुओं को खदेड़कर बाहर किया गया।

लाखों हिन्दुओं का कत्लेआम किया गया वहीं कश्मीर और केरल की तरह पूरे भारत में होगा, तब से भाजपा और अन्य पार्टीयां क्या करेंगी, फिर भाजपा जिस हिन्दू एजेंट के दम पर सत्ता में आई थी जिस आतंकवाद के विरूद्ध दहाड़ कर मोदी प्रधान मंत्री बना, अब वही मोदी संविधान की दुहाई देकर हिन्दू संगठनों की सच्चाई को भी धमका-चमका रहा है।

वैसे भी इस देश का इतिहास गवाह है, कि हिन्दू घोर स्वार्थी, मक्कार और बिखरा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ, कि दसियों हजार वर्ष पुराना हिन्दू धर्म, जिसके अवशेष पूरी दुनिया के कोने-कोने में बिखरे हुए हैं। जिसके आध्यात्प ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित से पूरी दुनिया वर्तमान में भी रोशन हो रही हैं। ढाई हजार वर्ष पहले भी एलेंजेंडर, सेल्युकस जैसे आक्रांताओं का इन्हीं हिन्दुओं ने स्वागत किया और वो ईरान, अफगानिस्तान में घुसते हुए दक्षिण भारत तक जा पहुंचे, तो चंद लोगों के साथ घुसे थे, यहीं के हिन्दूओं की सेना बनाई और उन्हीं हिन्दुओं ने अपनी ही जाति के राजाओं के विरूद्ध बगावत कर न केवल उनके वरन् हुणों, शकों, मुगलों, पुर्तगीज और अंग्रेजों को न केवल साथ देकर बड़े-बड़े साम्राज्यों को नष्ट किया और उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, इस देश की हिन्दू नारियों ने अपने पिता, पति, पुत्र के राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया, स्वाभिमान और राष्ट्र भक्ति न तब थी और न अभी है, बेशक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रियों और शुद्रों की जातिवादी व्यवस्था ने इस देश को गुलाम बनाने में घोर आपत्तिजनक भूमिका अदा की, और हर आकांताओं ने भी सहस्त्रों वर्षों से इस अलग-अलग जातियों में बंटी समाज को दास बनाकर घोर शोषण किया, तब विदेशी आकांताओं ने किया और हमारे घोर भ्रष्ट कमीशन खोर भाजपा कांग्रेस के नेता कर रहे है।

वर्तमान में भी इसी हिन्दूवाद का शिगूफा देकर जिन हिन्दू भाजपाइयों ने जनता से वोट लेकर सत्ता हथियाई , उसका उद्देश्य हिन्दूओं का कल्याण, विकास प्रदान करना न प्रदेशों में रहा और न देश में, उल्टे ही कश्मीर में सत्ता के लालच में पीडीपी से गठजोड़ कर सत्ता संभालते ही दुर्दांत आतंकवादियों को जोड़ने का सिलसिला और शुरू हो गया। यहां तक कि मप्र में धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर होने वाली पूजा के यज्ञ के हवन कुंड में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ही पानी डाल दिया था, जबकि यह दुष्कृत कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेसी नेताओं तक नहीं किया, मप्र में मालवा आतंकियों, सिमी का गढ़ बन चुका है।

पुलिस जानती है, परंतु उसे तो अपनी वसूली और भ्रष्टाचार से कमाई में इतनी व्यस्त है, कि उसे इन राष्ट्र द्रोही गतिविधियों से कोई मतलब नहीं रहा। भ्रष्ट शासक, प्रशासक,पुलिस हिन्दुओं की रक्षा कर नहीं सकती, और हिन्दू यदि अपनी रक्षा के लिए आग्नेय अस्त्रों की अनुमति लेना चाहता है, तो पिस्टल यदि रु. 50000 की आती है तो रु. 15000 संबंधित थाने को, रु. 15000 एसडीएम को, एसपी ऑफिस, गृह मंत्रालय की भेंट चढ़ाओं तब मुश्किल से लाइसेंस हाथ आता है, अर्थात धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़कर सत्ता में बैठे शूकरों को जो अपने आप को हिन्दूओं का सरपरस्त बताकर सत्ता को हथियाई पर सत्ता पाते ही हिन्दुओं के दमन में मुगल शासकों से ज्यादा सत्ता की गर्मी दिखाने लगे, हिन्दू दंपत्ति केवल दो बच्चे पैदा करेंगे, तीसरे पर सभी शासकीय सुविधाएं, नौकरी, बाल विवाह, एक पत्नी अर्थात जितना कहर मुगलों ने नहीं ढाया, जितना हमारे शासक हिन्दुओं को नष्ट करने और करवाने के लिए ढा रहे हैं। हिन्दू कटु सत्य बोले तो, फेसबुक, वाट्सएप पर संदेश भी भेजे जाते हैं तो तत्काल गिरफ्तारी, ओवेसी, बुखारी मंच से हिन्दूओं के खिलाफ जहर उगले तो न केवल शासक भी चुप और मीडिया भी।

वैसे भी इस देश का मीडिया दृष्य, श्रव्य, टीवी चैनल, मुद्रित प्रसार माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के मालिकों से लेकर सारे पत्रकार हिन्दू साधु, संतों, नेता जो सच बोलते हैं। तो मक्कार ब्लेक मेलरों की फौज एक साथ, जंगली सियारों की तरह हुआ-हुआ कर बदनाम करती है, उसमें सरकारें भी साथ देती हैं। झूठे प्रकरण बनाकर आशुमल उर्फ आसाराम को षड़यंत्रों का शिकार बनाकर जेलों में सड़ाती है। दूसरी तरफ मुफ्ती मो. सईद जैसे पाकिस्तान परस्तों के साथ मोदी भी गले मिलकर सरकार बनाते हैं।

नमो व अमित शाह का घमंड चूर-चूर, जीत का नशा काफूर, 5 प्रश सींटभी नहीं मिली

अमित शाह ने बेड़ा गर्क किया, दिल्ली में भाजपा का

आप को जिताने पूरा युरोप, मुस्लिम राष्ट्र और पूरी आईएएस लॉबी लगी थी

दिल्ली में भाजपा की इतनी भारी हार ने नरेंद्र मोदी और उसके परम मित्र अमित शाह वर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष की एक तरफा भाजपा को हॉक कर ले जाने का घमंड चूर-चूर कर दिया, लोकसभा चुनाव जो जीत उसने शाम, दाम, दंड, भेद के साथ सामाजिक प्रचार माध्यमों दृष्य, श्रव्य, प्रचार, माध्यमों पर मुद्रित समाचार माध्यमों को खरीदकर पूर्णतः बाजार, आधुनिक तकनीकों के दम पर आकर्षण विज्ञापनों के सहारे हथियाई थी, 9 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस की उन्हीं लूट-खसोट पूर्ण नीतियों, पूंजीपतियों से कमीशन खोरी करते हुए, उनके हितों में कानूनों को बनाने, भूमि अधिग्रहण कानूनों को बदलने के लिए अपनाई, जिसे जनता ने बाखूबी समझा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रो-फ्रूड की कीमतें 65 प्रश तक कम होने के बाद भी भारत में मात्र 20 प्रश तक पेट्रोल की कीमतें कम करने के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर वसूली करने और अनुदान का शिगूफा दिखाया, दूसरी तरफ हर क्षेत्र में देशी उत्पादकों सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकिग, बीमा,रक्षा, विद्युत, सड़कों,संचार आदि में जो सरकार स्वयं विपक्ष में रहकर विरोध कर रही थी, सत्ता में आते ही मोटा कमीशन हजम करने सरकारी साधनों से इन सबको अपने पलक पांवड़े बिछाकर उन्हें निमंत्रण देने लगी।

यही हाल उसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अमेरिका के साथ किया जो विपक्ष में सहकर, जिसका विरोध कर रही थी, सत्ता में आते ही वही आस्ट्रेलिया, अमेरिका से मोटा कमीशन हजम करने के उपयोग के बाद बेकार हो चुके परमाणु भट्टियों को भारत में लगाने के लिए मान-मनोवल करने लगी, अभी भी गतिरोध अमेरिका से उसी हाथ पर है, कि अमेरिका चूंकि समय बाधित संयंत्र बेच रहा है, तो दुर्घटना होना भी निश्चित है, उससे उत्पन्न क्षति पूर्ति के लिए वह तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि क्षति होने पर उस नुकसान की भरपाई भी विक्रेता कं. करें, जबकि वह इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि अमेरिकी कं. अच्छी तरह जानती है कि दुर्घटना हो न हो वैसे भी भारत को दी जाने वाली सारी परमाणु भट्टियां रेडियो एक्टिव हो चुकी है, जिस कारण से उसकी ढुलाई, स्थापना, रखरखाव करने वाले सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, कर्मचारी उस की रेडियो एक्टिविटी से प्रभावित होंगे ही, फिर भी संयंत्र लगाने पर तुले हैं फिर मोदी ने मनमोहन सरकार की कौन सी जनता को परेशान, उसने पैसे की बर्बादी, घोटालों, बहुराष्ट्रीय कं. को भारत में पैर जमाने, देशी व्यापार, व्यवसाय,रोजगार को नष्ट करने, उनके हितों में बने कानूनों को समाप्त करने की अपेक्षा, यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06, श्रमिकों का घोर शोषण करवाने के लिए 16 श्रम कानूनों को समाप्त करने की साजिश भसी मात्र 9 माह में रच डाली, संसद में कानून नहीं पास करवा पाए तो अध्यादेशों का सहारा लेने लगे, इन सब तथ्यों को गहराई तक जनता ने समझा।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने इस देश की सत्ता को हांकने, चलाने और जोतने वाले असली खुदाओं, जो तहसीलों और जिलों से लेकर देश और प्रदेशों के सभी मंत्रालयों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को अपनी सत्ता की शतरंज पर मोहरों की तरह नचाने, चलाने वाले इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों को आते ही साथ जो बुरी तरह से हड़काया था। उससे वो पूरे देश की लॉबी बौखला चुकी थी, जो मोदी और उसकी भाजपा को गहरा, लंबा जवाब देने के इंतजार में थी, उसे दिल्ली के चुनाव में वह अच्छा मौका मिला, और उसने पर्दे के पीछे बैठकर जो खेल खेला, वह सबके सामने है, पर्दे के पीछे के ये असली खिलाड़ी यथार्थ में नेताओं के सामने अपनी इच्छानुसार नाचते-कुदते, हराते, जिताते, सम्मानीय, असम्मानीय बनाते, भद्द पिटवाते है।

ये वही आईएएस गिरोह है, जिसने लोकसभा चुनावों में एक तरफा बहुमत दिलवा दिया, जबकि न केवल ईवीएम मशीनों में जालसाजियों की गई, वरन् ईवीएस में दर्शित परिणामों की कम्प्यूटर्स में बिना हर चूक की गणनाओं की एक्सेल शीट बिना तैयार किए गए इन्हीं शूकरों ने नेताओं से मोटा धन हजम कर जिसे 10000 हजार वेटों से नहीं जीतने की संभावना थी, इन्हीं जालसाजों ने साढ़े चार लाख वोटों से जीतवा दिया तो फिर क्या कारण था, कि इसी जालसाजों की लॉबी ने आपके मानुमति के कुनबे को रिकार्ड जीत दिलवाकर उसने भाजपा को 5 प्रश से कम पर ला पटका, जबकि भाजपा ने भी लगभग रु. 2000 करोड़ से भी ज्यादा का दांव लगाया था, लोकसभा की जीत के मद में चूर नोट खर्च किए भरपूर, नामो निशां मिटा, दिल्ली की गद्दी के कर दिए सपने चकनाचूर, फिर भारत में चुनाव चाहे लोकसभा, विधानसभा या पार्षदों के ही क्यों न हो, जिस तरफ शास. कर्मचारी अधिकारी और आई.ए.एस लॉबी जनता कुछ भी कहे करें, पार्टिया कितने भी तिकड़म लगा लें, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक्स और प्रिंट मीडिया खरीद लें, शराब, शबाब की नदियां बहा दें, जनता को नोटों से नहला दें, चुनावी रंगमंच पर बाजी वही मारेगा, जो इस आईएएस से लेकर नीचे तक चुनावी मतदान केन्द्र कों संचालित करने वाला सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उसको चाहेगा, पर्दे के पीछे नोपथ्य का डोर इन्हीं के हाथों से चलाई जाती है।

जिसके परिणाम से इतिहास भरा पड़ा है। इसके विपरीत अरविंद के हाथों में सत्ता, वैसे ही है गंजे के नाखून ये सब आपस में ही लड़कर जून-जुलाई 15 तक चुनाव के हालात बना देंगे, बेशक बात पुरानी हो गई है, पर राष्ट्रीय मीडिया के क्षितिज पर यह सत्य कोई प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए इसकी प्रासंगिकता है।

साप्ताहिक समय माया

मप्र वाणिज्यकर कदम-कदम जालसाजों की फौज

लूट सके तो लूट भ्रष्टों को पूरी छूट

भ्रष्टों कीफौज, सूचना अधिकार में जानकारी देने में करती है जालसाजी

इंदौर मप्र के वाणिज्यकर के मुख्यालय से लेकर वृत्तों में बैठे अधिकांश अधिकारी कर्मचारी है, तो अधिकांश जालसाज और भ्रष्ट, जिसको जहां जैसा मौका मिलता है, जालसाजी और भ्रष्टाचार करता है, फिर चोर-चोर मौसेरे भाई में तेरी नहीं कहूं तू मेरी मत कहना, जिसका सीधा सा पैमाना है, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने के लिए आवेदन देने से लेकर जानकारी के पन्नों का शुल्क मांगने जालसाजी पूर्ण तरीके से अपील प्रस्तुत करने के बाद पुख्ता तारीखों में जवाब भेजते हैं। यह सब जवाब भी सभी उपायुक्त अब्दुल मजीद से क्र. 3, उपायुक्त गोपाल पोरवाल, सं.क्र. 1, उपा. डीसी करोड़िया जो सारे स्वयं जालसाज और भ्रष्टाचार में गहरे लिप्त रहते हैं, और सभी वृत्तों के वा. कर अधिकारियों, सहा.आयुक्तों से महीना भी हजम करते है। सारे हरामखोर एक तरफा अपील की सुनवाई की नौटंकी कर अधिकांश अपीलें निरस्त कर दी जाती है। जबकि वृत्त क्रमांक 1 में वा. कराधिकारी के रु. ज्योति मेहता को लें तो इस सिरफिरी महिला के किस्से दैनिक अखबारों में सुर्खिया बन चुके हैं, जिसमें इसने अपने अति. वा. कर. अधिनियम सोढा को शाम 7-8 बजे ताले में बंदकर के चली गई थी, काम-धाम कुछ आता-जाता नहीं पर हर काम का पैसा कर सलाहकारों से जरूर वसूलती है।

स्व कर निर्धारण के अधिकांश प्रकरण महीनों से लंबित हैं कि इसे पैसा देना नहीं चाहते नए टिन नं. जारी करने में भी सबकुछ ऑनलाइन होने के बाद भी पहले प्रकरणों को अटकाना फिर वसूली करना इसकी आदत में हैं। जब इस जालसाज को सूचना अधिकार में आवेदन दिया गया तो अपनी जालसाजियों का भंडाफोड़ होते देख, दो पंक्तियों के पत्र में लिख दिया कि जानकारी देय नहीं है, स्टाफ का चपरासी से लेकर अन्य हर कर्मचारी इकसे सिफिरे पन से न केवल परेशान है वरन् सब मजबूरी है नौकरी करना, इसलिए झेलते हैं। संभागायुक्त गोपाल पोरवाल जो स्वयं न केवल भारी जालसाज है, वरन अपनी वसूली के लिए रु. 10 करोड़ से बड़े कर प्रकरणों को स्वयं ही कर निर्धारण के लिए बुलवा लेता है, जबकि रु. 1 से 2 करोड़ तक के लेन-देन वाले प्रकरण वा.कर. अधि. रु. 100 करोड़ तक के प्रकरणों का सहा. आयुक्तों को निपटाना चाहिए और रु. 100 करोड़ से ऊपर के प्रकरणों को उपायुक्त सीधे कर निर्धारण और वसूली देखना चाहिए, वैसे ये हरामखोर पोरवाल शुरू से ही भारी जालसाज रहा है, वर्तमान में रु. 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है, स्वाभाविक है, अपने अधीनस्थों का हक मारकर वसूली करता है। इसलिए सूचना के अधिकारों में की गई अपीलों को एक मुस्त रिस्त कर दिया जाता है, यही हाल संभागायुक्त अब्दुल मजीद सं. क्र. 3 का और 2 के उप आ. डीसी करोड़िया भी करते हैं। वैसे अधिकारी वर्ग में बैठे नई भर्ती जो 04-05 के बाद भर्ती हुई है, अधिकांश काम वैसे भी ज्यादा आता-जाता नहीं पर भ्रष्टाचार के मामले में वसूली र्धारण अवश्य किए जा रहे हैं। जिससे शासन को अरबों रुपए की हानि हो रही है, सबसे बड़े आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस विभाग की आपूर्ति कोई आंतरिक आंकेक्षण की टीम ही नहीं है, जो आंतरिक स्तर पर इन भ्रष्टों और जालसाजों के कार्यो की आंतरिक समीक्षा करें, एमपीएजी की टीम भी इतनी बड़ी और दमदार नहीं होती कि वो हर कार्य की समीक्षा कर सकें, जबकि सी फार्म, 49,51 आदि फर्मों के माध्यम से आईटीआर के माध्यम से ही जालसाजी पूर्ण तरीके से अरबों रु. के राजस्व की हानि पूरे प्रदेश में शासन को झेलनी पड़ती हैं, यहां पर बैठे अधिकारी अपनी कमाई के लिए अलग से अपनी भ्रष्टाचार की वसूली में से वेतन देकर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसी पद पर बैठाकर दो नं. के सारे कार्य इन्हीं के माध्यम से करवा रहे हैं। जैसे तोरणे बड़े बाबू के वृत्त क्रमांक 11 की सहा. आ. रुबी सोनी ने बैठा रखा है। पूरे मप्र में अधिकांश वृत्तों में ऐसे सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही है। ये हाल न केवल इंदौर के वृत्तों के साथ देवास-उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ से लेकर पूरे मप्र के हैं। एंटी इवेजन ब्यूरों में भी ऐसे ही सेवानिवृत्ति प्राप्त वहां के अधिकारी अपनी जेब से वेतन देकर काम ले रहे हैं।

शासन ने खर्चे कम करने के दृष्टिकोण से अधिकांश विभागों में टैक्सी किराए पर लेकर काम कराने की योजना. का भी भरपूर दोहर कर कमाई की जा रही है, साथ ही किराए की टैक्सी जो अधिकांश वृत्तों में वृत्ताधिकारी के घर से आने-जाने के साथ ही उसका उपयोग कर वसूली के लिए भी किया जाता है, परंतु वृत्त क्रमांक 10 की वृत्ताधिकारी सहा. आयुक्त इस सरकारी टैक्सी का उपयोग अपनी निजी सहा. वा. कर अधिकारियों को देने की तो दूर उपायुक्त को भी बहाने बनाकर गाड़ी उपलब्ध नहीं करवाती, इस प्रकार शासन को 1500 से 2500 किमी के वाहन चालन का अवैधानिक खर्च वहन करना पड़ता है, यही कारण है कि जब उच्च अधिकारियों से वाहन की लांग बुक की छायालिपि वाहन ब्रिनों के भुगतान की कॉपी मांगी गई, जिसे देने में इन हरामखोर लोक सूचना और अपीलीय अधिकांश ने निरस्त कर दी, जो स्वमेव सिद्ध कर देता है, कि ये गिद्धों की फौज अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। भ्रष्टों में ऐसा नहीं कि केवल अधिकारी ही भ्रष्ट हैं वरन् इस मंत्री तक पहुंचता है, फिर चाहे वह किराए के भवन में कार्यालय में चलाने में मिलने वाले कमीशन की चाहत ही क्यों न हो, यही कारण है कि जो विभाग रु. 20000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व देता है, जबकि उसके पास अफीम गोदाम की 5 एकड़ से ज्यादा की अरबों रु. की जमीन ठीक इस महानगर के बीच पड़ी है, जिस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, डेंटिंग-पेंटिंग की दुकानों से लेकर होटलों, रिचार्ज व्हाउचर की 50 से ज्यादा दुकाने चलाई जा रही है, पर रु. 10 करोड़ का एक विशाल भवन नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि यहां बैठे हरामखोरों की दाढ़ में रु. 5 लाख से ज्यादा का कमीशन का खून लगा हुआ है, जबकि जिस चेतक चेंबर 14 वृत्त कार्यालय चल रहे हैं। 6 उपायुक्तों, 1 अपर आयुक्त आदि बैठते हैं, इस भवन में दो बार आग लग चुकी हैं, 10 वीं मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्थाएं न केवल स्टाफ को वरन करदाताओं और कर सलाहकारों को भी कष्ट देती हैं। मात्र लाखों के कमीशन में न केवल छोड़ा नहीं जा रहा वरन स्वयं का भवन बनाने से भी रोका जा रहा हैं, जबकि अरबों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, सभी अन्य शासकीय विभागों के, परंतु वाणिज्य कर भवन का जिसके मुख्यालय के साथ ही सबसे ज्यादा 15 वृत्त कार्यालय इंदौर में ही लगाए जाते है। पर हाय भ्रष्टाचार तेरा आसरा।

श्रम मुख्यालय की नाक के नीचे, इ.नं.नि. 6000 सफाई कर्मियों को दे रहा आधा वेतन

श्रमिकों का घोर शोषण-अधिकारी कर रहे पोषण

पूंजीपतियों की रखैल भाजपा खत्म कर रही श्रम कानून, न केवल पूंजीपति, उद्योगपति वरन् शासकीय व क्षेत्रीय अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में भी न्यूनतम का अधा वेतन नहीं दिया जा रहा, सूचना के अधिकार जानकारी मांगने पर अपर आ आर जी पांडेय जानकारी देने नहीं देता है,

गुजराती चाय वाले धूर्त झाड़ू बाज नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को मंहगाई कम करने, भ्रष्टाचार दूर करने और अच्छे दिन के शिगूफे छोड़ कर जिस तरह शाम, दाम, दंड, भेद के साथ प्रचार माध्यमों को खरीद सत्ता हथियाई थी उससे यह तो स्पष्ट हो ही चुका था कि सत्ता में आते ही ये नरेंद्र पूंजीपतियों का दासेन्द्र बन जनता का घोर शोषण करेगा, आते ही उसने जनता, मजदूरों किसानों के शोषण के हर हथकंडों को अपना रहा है, जिसके उदाहरण स्वयं जनता देख रही है, उसके अनुशरण में मप्र का मुख्यमंत्री शिवराज भी लगकर झूठेक आंकड़ों की बाजीगरी से केन्द्र शासन को मूर्ख बनाकर पुरुस्कार लेकर अपने आपको महान समझ रहे हैं। जबकि यहां की जनता को ये गिद्ध और इसका मंत्रिमंडल हर तरह से नोंचने परा तुला है, पूंजीपतियों से मोटा कमीशन डकार, उनके हक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लागू करवाए कानूनों का 95 वर्ष बाद औचित्य हीन बनाकर गरीब मजदूर वर्ग का न केवल घोर शोषण वरन् ये शूकरों की फौज मजदूरों का परिवारा तो दूर स्वयं भी आधे पेट भोजन भी नहीं कर पाएगा।

जब देश और प्रदेश में 85 कानून लागू थे, तब तो न केवल निजी क्षेत्र, संयुक्त उपक्रमों में ठेकेदारी प्रथा के चलते दस वर्ष में लागू रु. 226 की दैनिक मजदूरी अर्थात रु. 6780 की अपेक्षा इसी इंदौर में पीडीपी एल जहां 3 पाली में 6000 से ज्यादा मजदूर काम करते रु. 3-4 हजार का वेतन बिहारी और यूपी के मजदूरों को दिया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर इंदौर नगर निगम भी अपने सफाई कर्मियों को 20 वर्ष बाद भी 6000 से ज्यादा को रु. 4925 के वेतन में से रु. 581 मस्टर भविष्य निधि के काट लेता है, जबकि न्यूनतम दैनिक मजदूरी रु. 251 रु. है। 6 माह से 12 माह में मजदूर कुशल मजदूर की श्रेणी में आ जाता है, इस हिसाब से रु. 300 प्रति दिन मिलना चाहिए पर 20 वर्ष की सेवाओं के बाद भी मिलते हैं। भाजपा 150% औसतन प्रतिदिन जब इंदौर नगर निगम का ये हाल है तो निजी क्षेत्रों में कितना शोषण किया जाता होगा अंदाजा लगाया जा सकता है, जब श्रमायुक्त के मुख्यालय को नगर निगम में न्यूनतम से कम वेतन 20 वर्ष ज्यादा समय से दिया जा रहा है तो पूरे मप्र के निजी क्षेत्रों में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, शारीरिक, मानसिक शोषण की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। महिला सफाई कर्मियों ने दबी जुबान में स्वीकार किया है कि भैय्या इतनी कम मजदूरी के बाद भी छुट्टी कर देने पर मजदूरी काटने से लेकर, जो इनका सुपरवाइजर,ठेकेदार, वार्ड इचार्ज जहां बुलाए वहां जाओ, जैसा कहे वैसा करों, तो वो सब करते हैं। मना करने पर भगा देते हैं। यह शिकायत मिलने पर श्रमायुक्त कार्यालय को बताया गया तो सहा. आयुक्त कार्यालय निजी कं. से लेकर शासन के अधिकांश विभागों में है। मप्र शासन का एक विभाग उद्यानिकी है, वैसे कृषि, और वन विभाग में भी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को अभी भी रु. 60-100 और 150 प्रतिदिन की मजदूरी दी जाकर सारा बीच में ही सहा. संचालक उद्यानिकी एवं वानिकी न केवल इंदौर, देवास, शाजापुर,खंडवा, धार, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच की लगभग 100 से ज्यादा नर्सरियों और उद्यान के 3000 से ज्यादा कर्मचारियों का शोषण कर हजम कर रहे थे, वरन् श्री अजमेरा ने न्यूनतम वेतन तो दूर, 3-3 माह वेतन न मिलने का शिकायत यहां के संचालकों से भोपाल में की तो बहाने बनाकर 20-20 वर्ष की सेवाओं के बाद हटा दिया गया, पर यहां श्रमायुक्त कार्यालय जो भ्रष्टों, जालसाजों और अय्याश अपर आयुक्तों, एल पी पाठक, आरजी पांडेय आदि से वर्षों से सज्जित हैं, कुकर्मों से फुर्सत मिले तो मजदूरों को देखें। यह हाल मजदूरों के शोषण का पूरे मप्र में हैं।

इंदौर जिले का सहा. आयुक्त ऊदे जिसने दो बार उपायुक्त की पदोन्नति इसलिए ठुकराई की वहां भ्रष्टाचार से ज्यादा कमाई नहीं की जा सकती, जबकि यहां अजगर की तरह इस भ्रष्ट की कमाई रु. 1 करोड़ प्रति वर्ष से ज्यादा है, इसके अंतर्गत कार्यरत सभी निरीक्षकों की कमाई का 50 प्रश प्रति निरीक्षक रु. 50 लाख से 1 करोड़ हैं। जिसका पाइप लाइन का पैसा मंत्री, संत्री, मुख्यालय में बंटता ही है, साथ ही साथ भोपाल से आने वाले धूर्त और मक्कार सचिवों की व्यवस्था भी ये ही ऊदे करता है, इसलिए इन धूर्तों के सारे कुकर्मों पर भी ये पर्दा डाल देते हैं। शिकायतें दबा दी जाती है। जब-जब इन हरामखोर जालसाजों की फौज से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जाती है, ये शूकरों की फौज कैसी-कैसी दलीलें देती हैं, निम्न पत्र से ज्ञात हो जाएगी। उपरोक्त पत्र में मुख्यालय से पर जमे अधिकारियों की लॉग बुक की फोटो कॉपी मांगी गई थी, जिसके जवाब में यह पत्र भेजा गया, जबकि अपर आयुक्त आरजी पांडे ने उस शास. गाड़ी से अपनी शास. प्रेमिकाओं को लेकर यहां से वहां घूमता हैं। इस भ्रष्ट ने अपने भ्रष्टाचारों से डरकर जो घर में कटकना कुत्ता पाल रखा हैं उसने रेडियो कॉलोनी के साथ ही अनेकों कर्मचारियों को भी काटा है, जिसके इलाज और इंजेक्शन लगवाने के लिए भी ये गाड़ी सुयश हॉस्पिटल भी काफी आती जाती है। अपने पद के दुरुपयोग कर उस हॉस्पिटल के मालिक को चमका कर सबका वहां मुफ्त इलाज करवाते हैं, ये निकम्मा और अय्याश अपनी प्रेमिकाओं से मिलने कभी सागर, रतलाम शासकीय वाहन से ही यात्रा में शासकीय कार्यों के नाम पर करता है। ये हरामखोर की फौज जनता के पैसे को अपने बाप की जागीर समझ अपने मनमाने मौज मस्ती में उड़ाए, और जनता इसका हिसाब मांगे तो उसे दलीलें देकर जानकारी न देवें क्योंकि उसमें इनके कुकर्मों का रिकार्ड हैं, कैसे दें अपने वाहन के लॉग बुक की कॉपी, जब ये भोपाल में था, तो इसने वहां भी श्रमिक कल्याण निधि में इसकी खास सहा. आयुक्त को कर्मकार मंडल का कल्याण आयुक्त बनाया और करोड़ों की कल्याण निधि में भारी घोटाले किए, जब भोपाल के पत्रकार ने जानकारी मांगी तो उसे बुलाकर मारा-पीटा और झूठी शिकायत जहांगीराबाद थाने में करवाकर रु. 5 लाख थानेदार को देकर गिरफ्तार करवाया गया, जिसमें न केवल इस पांडे के साथ, सचिव, प्र.स. वार्ष्णेय मंत्री अंतर सिंह आर्य, जिसे मंत्री पद दिलवाने में इसी पत्रकार ने भूमिका निभाई थी, और यह वही कर्मकार मंडल है जो निर्माण एजेंसियों ठेकेदारों फर्मों से उनके कुल कारो बार का 1 प्रश सेस निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के नाम पर वसूला जाता है, जबकि 90 प्रश निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को तो दो वक्त की रोटी, सिर पर छत भी ढंग से नहीं मिलती और ये गिद्धों की फौज उनके कल्याण के नाम से पैसा हजम कर जाती है, उसी की जानकारी जिसमें करोड़ों रु. की कॉपियों की खरीद की गई थी, मांगी गई थी श्री भारद्वाज पर उस भ्रष्ट महिला ने जानकारी देने के नाम पर बुलाया और घेर कर उसी कार्यालय के भ्रष्ट कर्मचारियों, श्रम निरीक्षक ने आकक्रम कर मार पीट की, इस बीच वह इस ब्रजेंद्र तिवारी, राजपूत को छू करवाकर मंत्रालय पहुंच चुकी थी, फिर भी एफआईआर से इस महिला ने अपने साथ छेड़छाड़ और बत्तमीजी के आरोप लगाकर उसे छह महीने के लिए अंदर रखने की तैयारी की थी, आखिर रु. 5 लाख कहां से खर्च किए गए।

दूसरी तरफ भ्रष्ट अपर आयुक्त एल. पी. पर सालभर पहले लोकायुक्त का छापा पड़ा था न तो निलंबित किया गया, न चालान पेश किया गया, इतना धन आखिर कहां से आया, फिर जब्ती के बाद भी रु. लाखों खर्च करके लोकायुक्त में कार्रवाई क्यों रोकी गई है, इस पाठक ने भी श्रमिकों के शोषण की व उद्योगपतियों पर कार्रवाई को धीमा, ठंडा करने के नाम पर जमकर वसूली की और धन बांटा, आखिर कैसे ये लॉग बुक की जानकारी, तीसरे को दे रहा है अपर आयुक्त प्रभात दुबे जिनके पास गाड़ी है, ये भी व्यक्तिगत उपयोग में, कार्यालय का वाहन लाते हैं। एक वाहन श्रमायुक्त के गुप्ता के पास हैं, वैसे भी सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को वेतन, सुविधाएं जनता के खून पसीने से निचोड़े गए करों से प्राप्त होती है। गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, मरम्मत, सरकारी खर्च से की जाती है, तो लॉग बुक देने में क्या परेशानी हैं। वास्तविकता में कार्यालयीन स्तर पर ये तीनों भ्रष्ट अपर आयुक्त एक-दूसरे के दुश्मन हैं। पर लॉग बुक की फोटो कॉपी न देने के लिए एक हैं।

इस श्रम विभाग के अंतर्गत मप्र औ. स्व.सु. भी कार्यरत हैं, इसमें संचालक वल्लभ काड़िया हैं। इन्होंने लॉग बुक की फोटो कॉपी दी जिसमें घोर जालसाजी कर बस प्रतिदिन के गाड़ी चलने के किमी चली है का उल्लेख, कब कितने बजे कहां से कहां आए गए का कोई उल्लेख नहीं है। आखिर क्यों सरकारी पैसे को बाप की जागीर और कानूनों को अपनी रखैल समझते हैं अधिकारी। जब मप्र के सभी कार्य विभाग यथा लोकनिवि, जल सं.वि., लो. स्वा.यां. के सभी निचले अधिकारियों की गाड़ियों की लॉग बुक यात्रा कार्यक्रम यात्रा डायरी, वरिष्ठों को भेजी जाकर नियंत्रित की जाती कि उनके कनिष्ठों को मिले वेतन कर्तव्यों के पालन पर निगरानी और नियंत्रण किया जाता, परंतु वरिष्ठ अधिकारी जो कनिष्ठों से मिली पाइप लाइन की रिश्वत के टुकड़ों पर पलते हों, तो कैसे कनिष्ठों पर नियंत्रण करें।

ऋण लेकर घी पी रहे - कहां जा रहा राजस्व, बढ़ाये कर

पेज 1 का शेष

इस बजट में भी विकास के नाम सड़कों पर रु. 33000 करोड़ का आवंटन किया, अब डकैतों का गिरोह में बताये प्रदेश के 5000 कि.मी. से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकांश पर भा.रा.रा.प्रा. का कब्जा है, बाकी लगभग 40,000 कि.मी. सड़कें राज्य के राजमार्गों पर चाहे 9,15,27 फुट की हों, सब पर टोल वसूली ठेकेदारों की डकैती चल रही है या फिर एडीबी, मंडी, निधि से चल रही हैं। ग्रामीण सड़कों पर प्र.मं. सड़क योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण देखरेख उन्नयन विकास और निर्माण में लगा है, इस धूर्त की चलाई मु.मं. ग्रामीण सड़क योजना में ग्रामीण विकास का पैसा ग्रामीण यांत्रिकीय से हजम कर रहा है। पूरे प्रदेश में लो.नि.वि. के पास 10,000 कि.मी. भी सड़कें नहीं हैं। जिनके लिये रु. 33000 करोड़ का बजट रखा गया है, सालभर में रु. 3000 करोड़ भी 51 जिलों लोनिवि संभागों को भी नहीं मिलना, अब ये भी दिग्गी दानव की राह चल शिव राक्षस बन प्रदेश की जनता को तन से मन से और धन से नोंचने में लगा है, अर्थात 75% नोंच खसोंट में हजम करेंगे।

राजस्व के लिये रु. 3398 करोड़ - यह विभाग तो स्वयं राजस्व वसूली करता है, इसके विकास में रु. 3398 करो का क्या होना है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिये रु. 4740 करोड़ - अधिकांश धन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वा. मिशन व अन्य योजनाओं का केन्द्र से आता है, फिर स्वास्थ्य के नाम से डॉक्टरों और वार्ड बॉय से लेकर मंत्री तक के बैंकों के बैलेन्स का ही सुधार होता आया है, फिर प्रदेश भर में फैले 10,000 से ज्यादा नर्सिंग होम्स, निजी अस्पतालों को तो बंद हो जाना चाहिए जो हर नगर, गली मोहल्ले में लूट और डकैती के अड्डों के रूप में चल रहे हैं। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग की दवाओं से लेकर अन्य खरीदी में हर जगह कमीशन बांटना पड़ता है। मुख्यालय से लेकर बाबु और स्टोर कीपर तक को, एक तरफ स्तरहीन दवायें व सामग्री खरीद कर मोटा कमीशन हजम कर सड़ाई जाती है। दूसरी तरफ जनता को लूटने के लिये बाजार में धकेल दिया जाता है।

वन व टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट रु. 2698 करोड़ रु.- वन विभाग में पिछला इतिहास बताता है कि पूरे म.प्र. में केवल इंडियन फारेस्ट (इटिंग) सर्विस अर्थात भारतीय वन भक्षक सेवा अधिकारियों की संख्या ही बढ़ रही है बाकी न वन भूमि, वनों में वृक्षों, वन जीवों से लेकर मैदानी वन रेंजरों से बीट गार्ड व बाबुओं तक सभी की संख्या घट रही हैं, अधिकांश कार्य कागजों पर ही संपन्न किये जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में लाखों करोड़ रु. केन्द्र व राज्य के व्यय होने के बाद भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जितने अधिकारी बढ़ रहे हैं। उतनी लूटपाट, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वनों के विकास, वन्य प्राणियों के विकास यथा शेर, मोर, खरमोर व अन्य दुर्लभ प्राणियों के विकास के नाम पर केवल भा. वन भक्षण सेवा अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक का ही विकास होता रहा है और रहेगा। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर धूर्तों की फौज कैसी-कैसी जालसाजियां करती है, इसे आवेदक ही जानते हैं।

लो.स्वा.यां. 2242 करोड़ - लो. स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में इस बजट का लगभग 40% पैसा अर्थात 900 करोड़ हैंडपंप, मैकेनिक, उपयंत्रियों, सहा. यंत्रियों, कार्यपालन अधीक्षण मुख्य और प्रमुख अभियंता, सचिव, प्रधान सचिव से लेकर मंत्री श्रीमती कुसुम महदेले और मु.मं. शिव व वित्तमंत्री तक बंट जायेगा।

उच्च शिक्षा के लिये रु. 2000 करोड़ - जब पूरे प्रदेश के 70% उच्च शिक्षा निजी क्षेत्रों में बंटने लगी है। सरकारी कालेजों में भी शिक्षण शुल्क भारी भरकम लगने लगा है, तो रु. 2000 करोड़ का खर्च से सरकारी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों मंत्री और मु.मं. तक रु. 1000 करोड़ बंटकर समाप्त हो जायेगा, फिर 90% सरकारी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में 50% अतिथि विद्वानों से ठेका श्रमिकों की भांति काम लिया जाकर निश्चित वेतन ही दिया जा रहा है।

सिंचाई के लिये 1463 करोड़ - सिंचाई योजनाओं के नाम पर राष्ट्रीय स्तर भ्रष्टतम विभाग म.प्र. जल संसाधन में जब से प्र.स.रा.श्या. जुलानिया आये हैं। ढर्रा कुछ सुधरा अवश्य है, परन्तु दूसरी तरफ नई योजनाओं पर जमीनों की कीमतों, वन विभाग की तानाशाही के कारण काम न केवल रुक गया, इसके साथ ही पुरानी योजनाओं में भ्रष्टाचार के चलते जबरदस्ती लंबी खींचकर लागत बढ़ाने और महंगाई में बंदरबांट का खेल भी चलने लगा है। पहले ही अधिकांश योजनाओं की वृहत परियोजना रिपोर्ट ही 25 से 40% अधिक की बनाकर हड़पा जाता है, इसमें भी यथार्थ कार्य मात्र रु. 600 करोड़ का ही होगा बाकी भ्रष्टाचार में डुबोया जायेगा।

महिला बाल विकास रु. 1398 करोड़ - इस विभाग में 90 से 95% तक पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा हैं, 95% आंगनवाड़ियों में 5 से 10% बच्चों और महिलाओं का लाभ नहीं मिलता सारा पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर मंत्री, संत्री, तक ही हजमकर लिया जाता है। बच्चों में भुखमरी और कुपोषण का आलम यथावत पिछड़े व ग्रामीण इलाकों में यथावत हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना में रु. 1398 करोड़- इस योजना में महिला बाल विकास के भ्रष्ट भारी कदम-कदम जालसाजियों को अंजाम दे रहे है। लाखों वास्तविक ग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका भी रु. 600 करोड़ जालसाजियों से हजम होगा जैसा कि पुराना इतिहास रहा है।

महिला बाल विकास रु. 1398 करोड़ - हर वर्ष अरबों रु. के बजट का 90% धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री संत्री तक हजम कर लिया जाता है। शहरों और गांवों की आंगनवाड़ियों के रजिस्टर में लिखे नामों पर आवंटन मिलता है, जो कि 70% तक झूठे होते हैं। 90 से 95% तक महिला बाल विकास केवल कागजों पर खर्च किया जाकर हजम कर लिया जाता है। पिछड़े, गांवों जिसमें बुंदेलखंड, महाकौशल के जिलों के ग्रामीण, निमाड़ और आदिवासी क्षेत्रों के 90% आज भी कुपोषण के शिकार हैं।

पिछड़ा वर्गव अल्पसंख्यक रु. 950 करोड़ - सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन्हें अल्पसंख्यक पुकारा जाता है, उनकी जनसंख्या वृद्धि दर न केवल भारत में 10.4% प्रति वर्ष है, वहीं विश्व में भी यह 8.4% है, वर्तमान में ये अल्पसंख्यक 50 करोड़ है। कई राज्यों में जिसमें कश्मीर, केरल, बंगाल, उप्र. महाराष्ट्र, गुजरात में बहुसंख्यक फिर भी वोटों के मुखेरे जानवरों की नजरों में अल्पसंख्यकों पर रु. 950 करोड़ के खर्च में से मात्र 30% खर्च होगा, बाकी नीचे आते तक कागजों पर ही जीम लिया जाएगा।

स्कूलों में शौचालय रु. 552 करोड़ - सरकारी स्कूलों में केन्द्र सरकार ही काफी पैसा जो सेवा शुल्क 2% शिक्षा सेस के नाम से वसूला जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, इसका 90% पैसा अर्थात रु. 500 करोड़ से कागजों पर ही शौचालय बनाकर हजम किये गये है और इस बजट के 15-16 में हजम कर लिये जायेंगे, बच्चे शौचालय में तो तब जायेंगे जब वो पढ़ने आयेंगे और जब पढ़ाने वाले होंगे, इस धन का अधिकांश पैसा मु.का.अ. जिला पंचायतों से सरपंचों तक हजम किया जायेगा जैसा कि इतिहास है।

स्वच्छ भारत और स्वच्छ स्कूल रु. 552 करोड़ - यह पैसा भी ईमानदारी की गंदगी को दूर और भ्रष्टाचार को सामंजस्य से हजम करने में किया जायेगा। जैसा कि इसका प्रणेता मोदी कर रहा है, पूंजीपतियों के लिये निर्मलता और गंदे गरीबों को भूखा मारकर साफ करने में लगा है।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रु. 450 करोड़ - यहां पर वीवीआईपी के लिये विशेष व्यवस्था होगी, ताकि वो जनता की निगाहों से बचकर यहां अपने तन-मन का तरीके से इलाज करवा सके, वैसे हाउसिंग बोर्ड ने म.प्र. सड़क विकास निगम के इस रु. 450 करोड़ का प्राक्कलन मात्र रु. 250 करोड़ में देकर प्र.स.वि. अग्रवाल के लूट के अरमानों पर पानी फेर दिया है, अब विवेक अग्रवाल इसके प्रबंध संचालक भी है।

कुटी एवं ग्रामीण उद्योग रु. 316 करोड़ - इस मद से भी 90% पैसा कागजों पर हजम किया जायेगा, यथार्थ में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को विकास के लिये शासन को ज्यादा ध्यान देना चाहिये, परन्तु मोदी मुद्रा राक्षस की नीतियों में केवल बड़े उद्योगपतियों का ही कल्याण हैं।

उज्जैन सिंहस्थ रु. 300 करोड़ - सिंहस्थ के नाम पर पिछले 30 वर्षों में रु. 1500 करोड़ से ज्यादा खर्ड कर चुकी है। रु. 300 करोड़ के साथ अनुपूरक मांगों में इस पर धन आवंटन बढ़ाया जायेगा अभी भी रु. 800 करोड़ के काम भ्रष्टों के हाथ में हैं जिन्हें चुन-चुन कर उज्जैन में बैठाया गया है।

खेल गतिविधियां रु. 199 करोड़ - खेल गतिविधियों के नाम पर तो 90% भ्रष्टाचार का खेल पूरे प्रदेश में हो रहा है। खिलाड़ियों को सुविधायें तो दूर बाहर खेलने के लिये ले जाने पर भोजन तक नहीं देते भोपाल के संचालक से लेकर जिलों के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी।

कला संस्कृति और धर्मालय रु. 142 करोड़ - प्रदेश के सभी नामी मंदिरों पर पूर्व से ही सरकारी अधिकारियों का कब्जा हैं- चाहे तो महाकाल मंदिर उज्जैन हो, खजराना गणेश मंदिर इंदौर हो, सबके करोड़ों के चढ़ावे से हिन्दुओं के लिये स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई धार्मिक और सामाजिक कार्य नहीं किये परन्तु वहां बैठे अधिकारियों न अवश्य अधिकांश धार्मिक ट्रस्टों से धन संपतियां अवश्य बटोरी, कला संस्कृति में भी बैठे अधिकारी केवल अपनों ही को उपकृत कर सारा धन झूठे कार्यक्रमों या दुगुने-तिगुनी दरों पर खर्च कर हजम कर जाते हैं।

परिवहन विकास के लिये रु. 140 करोड़ - ये धन नेताओं, अधिकारियों के घूमने-फिरने, परिवहन के लिये अच्छी महंगी गाड़ियां खरीदने में ही खर्च किया जायेगा, जनता के परिवहन निगम को तो नेताओं की, माफियाओं, पुलिस अधिकारियों की बसों से जनता को लूटने के लिये बंद करवा ही दिया गया है।

पर्यटन के लिये रु. 134 करोड़ - पर्यटन के नाम पर म.प्र. पर्यटन का पूरा विभाग अपने होटलों, पर्यटन स्थलों, पर्यटन की बसों के माध्यम से केवल म.प्र. शासन के मंत्रियों, नेताओं और पूरे भारत से केंद्रीय और भाजपाई सरकारों के मंत्रियों और आई.ए.एस. अधिकारियों को ही कुछ बेहतर सेवायें देते हैं। वैसे आमजनों के साथ ये पोश डकैती केन्द्र बने पर्यटन केन्द्र मंत्रियों अधिकारियों के सरकारी खर्च पर सुरक्षित मौज, मस्ती और अय्याशी के अड्डे बन चुके हैं।

बजट वास्तविकता में आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा होती है, साथ ही यह स्पष्ट करती है, कि सरकारी नीतियां, कर की दरें, अगले वर्ष में किस तरह से जनता का शोषण करेंगी, जनता को किस नाम से किस स्तर पर शासकीय कानूनी तरीके से सामने से लूट जायेगा, उसके आधार पर ही पीछे से लूट कर स्तर तय होगा।

म.प्र. का मु.मं. शिवराज का वित्तीय प्रबंधन पूर्व वित्तमंत्री राघव जी भंडारी जो खानदानी भंडार प्रबंधक थे, जाने के साथ पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। 9 वर्ष तक वित्त मंत्री रहते हुए राघवजी ने न तो सामान्यतः सरकार चलाने के लिये न तो कर्ज लिया, न ओवरड्राफ्ट किया, न ही जानबूझकर भुगतान की समस्या को देखते हुए कोषालयों के सर्वर डाउन कर वित्त वर्ष के अंतिम दिन तक भुगतान रोके, वर्तमान वित्त मंत्री जयंत मलैया का इतिहास सागर के बीडी मजदूरों के शोषण से शुरू होकर केवल छल-कपट से मलाई चाटने का रहा है, इस बुंदेलखंडी बनिये का इतिहास रहा है कि पहले माल अंटी करो, चाहे कोई मरे तो मरे, इनके आते ही कहां गया सारा राजस्व, सितम्बर 14 से कर्ज ले-लेकर वेतन बांटना पड़ रहा है। अरबों की सरकार को जनता की देनदारियां देना है, जबकि पौने दो लाख करोड़ का कर्जा सरकार ले ही चुकी है। फर. 15 से बड़े भुगतान करना बंद कर दिये, भुगतान संकट से बचने पूरे मार्च भर कोषालयों के सर्वर डाउन कर दिये, ताकि बदनामी न हो, मोदी की तरह शिवराज भी भरपूर सत्ता का सुख भोगने, विदेश यात्रायें करने अपने न्यूयार्क में बेटे से मिलने जाने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का सड़क पर प्रदर्शन करने की नौटंकी की गई, कर्ज लेकर घी पी रहे है मु.मं., वित्त मंत्री, व अन्य सभी अधिकारी, फिर भी मोटे कमीशन और हिस्सा डकारने नर्मदा, गंभीर लिंक परि., मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट सिटी के जनता को सपने दिखाकर एक तरफ पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है प्रदेश की संपत्तियों और प्राकृतिक स्त्रोतों को, तो दूसरी तरफ इन योजनाओं के नाम से विश्व बैंक एशियन से अरबों के कर्ज लिये जा रहे हैं। पुराने कर्जे की किस्तें नहीं चुक रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, सड़कों व अन्य करों की लूट की दरें म.प्र. में ही सबसे ज्यादा है। अब पूर्णतः दानव बन जनता को नोंचने पर तुला है।

मोदी ने आते ही अच्छे दिन दफन कर दिए आमजन के

गरीबी रेखा से ऊपर वालों की राशन व्यवस्था समाप्त

सालभर तक लोग भारत की जनता को भाजपाई मुद्रा राक्षसों के चहेते मोदी ने जनता को दिवा स्वप्न जिसमें भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन, महंगाई दूर व समाप्त करने, अच्छे दिनों की मीठी ख्याली खिचड़ी खिलाकर वोट झटकते और सत्ता में आते ही, सारे वादों को शिलालेखों में खुदवाकर, आंसुओं के समंदर में दफन कर दिया फिर इसका असली रूप सामने आया, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर की जनता को दिया जाने वाला रु. 5 प्रति किलो का गेहूं, रु. 6 प्रति किलो का चावल जो ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों से मिलता था, समाप्त कर दिया जिसकी कानो कान खबर अधिकारियों ने न केवल जनता को वरन मीडिया को भी नहीं होने दी, वैसे भी मोदी मीडिया रखैल की तरह है चुनाव जीता और भूल गया।

जून 2014 से ही एपीएल और ऊपर के लोगों को दिया जाने की व्यवस्था, बिना किसी घोषणा के समाप्त कर दी मीडिया शृंगार रस पिलाता रहा

इसके साथ ही निम्न मध्यमवर्गीयों को मिलने वाला रु. 9 प्रति किलो का गेहूं और रु. 10 प्रतिकिलो का चावल वाली योजना को जून जुलाई 14 को समाप्त कर दिया गया जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरे देश में राशन मिलता था, उनके राशन कार्डों को राशन दुकानदारों में रद्दी में फेंकने के लिए कह दिया, ये वही राशन कार्ड थे जिनकों निवासी की परिवार की उस स्थान की पहचान दिलाते थे, जो बच्चों को स्कूलों काले जो जिलाधीश कार्यालयों में मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्रों, आय आदि प्रमाण पत्रों को बनाने का आधार होता था, पर अब राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाले को भी राशन कार्ड पर शक्कर, गेहूं, चावल आदि मिलने की अपेक्षा खाद्य से दिए जाने लगा है, अब इस खाद्य पर्ची के मुद्रण जारी करने बांटने और पुनः राशन,दुकान पहुंचाने में भी न केवल पूरे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को बांटने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों तक पहुंचाने में, पर्ची भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसमें भी नए तरह के भ्रष्टाचार हर कदम पर होने लगे हैं। 30 से 40 प्रश ऐसे उपभोक्ताओं को पर्चीयों के वितरण में भारी समस्याओं के चलते उन्हें बाजार से रु. 25 प्रति किलो का आटा खरीदना पड़ रहा है।

प्र.म. मोदी के पास अपनी कोई भविष्य परक दृष्टि नहीं हैं, वह तो बड़े मुद्रा राक्षसों यथा अंबानी,अडानी, टाटा, बिरला और बहुराष्ट्रीय कं. के फायदे के लिए उनके इशारे पर नाच रहा है। आज ये पर्चीयां खाद्य व नागरिक आपूर्ति दे रहा है। कल इसके बांटने और अनाज वितरण का ठेका, रिलायंस फ्रेश की डूबती नाव को बचाने उसको दे दिया, जाएगा, जो 100 पर्चीयां बांटेगा और 1000 का अनुदान और पर्चीयां स्वयं हड़प जाएगा, ये धूर्तों मुखेरे जानवरों की फौज कांग्रेस से ज्यादा मोटी पूंजीपतियों के इशारे पर नाचकर जनता को जनता के नाम पर लूटेगी।

साप्ताहिक समय माया

लो. स्वा. यांत्रिकीय- मंत्री से उपयंत्री तक भ्रष्ट और जालसाज

प्रमुख अभियंता पद की बागडोर, अपराधी के हाथों में कर रहा तांडव

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यालयों में मचे भ्रष्टाचार, जालसाजी और लूट के समाचार आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल ही जाते हैं। बेशक तो कदम-कदम हो रही जालसाजियों, भ्रष्टाचार का यथार्थ में 0.01 प्रश भी नहीं है। फिर भाजपा बनाम मुखेरे जानवरों की पार्टी की सच्चाई तो देश के प्रधानमंत्री मुद्रा राक्षस मोदी की करनी और कथनी से न केवल देश की जनता वरन् विश्व की जनता को मिल ही गया है और अगले 4 वर्ष में और बचा खुंचा मिल जाएगा, जहां तक मिठ बोले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिराज का सवाल है, तो बेचारा तो भ्रष्टाचार में गले से ऊपर तक डूबा हुआ है वही हाल उसके मंत्रियों के भी हैं। इसलिए विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही समय पूर्व समाप्ति का ताना-बाना बुन ही घुसते हैं। फिर जहां तक लो.स्वा. यां. विभाग का सवाल हैं तो ये विभाग तो जनता को जल आपूर्ति के नाम अपनी जेबों और बैंक बैलेंस की राशि को सिंचित करने में ज्यादा व्यस्त रहता हैं, फिर जिस विभाग का प्रमुख अभियंता ही चारों तरफ से ग्रस्त होकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर भाग गया हो, तब से बिना प्रमुख अभियंता के ही विभाग के अंदर मचे घमासान का अंदाजा लगाया जा सकता हैं। जबकि 6 हत्याओं के इस आरोपी डामोर भले ही न्यायालयों से गवाह सबूतों को खरीद, नष्ट कर जालसाजी से बच गया हो, जिसे शासन ने पदोन्नत कर मुख्य अभियंता बना दिया हो, फिर भी वह प्रमुख अभियंता का पदभार मंत्री, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री को बांटकर ही चला रहा हैं, उसने पदभार संभालते ही उसके उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में उसके शासन द्वारा नियुक्त का.यं. चैतन्य रघुवंशी को निपटाने की हर अवैध चाल चली अपात्र होने के बाद भी जांच के आदेश दिए जिस पर न केवल शासन मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी साध रखी है, इसके इशारे पर ही अ.यं. सीके सिंह सागर को पिछले तीन साल से पदोन्नत नहीं किया जा रहा, इस नीच हत्यारे के कुछ शिकारों की तो इसकी जालसाजियों में फंसकर नौकरी भी छीनी जा चुकी हैं, जबकि 6 हत्याओं में इसकी बीवी से लेकर 5 अन्य भी हैं। वैसे यह स्वयं 7 हत्याएं करना बताता हैं। उनमें से अगर न्यायालयों से बच भी निकला तो विभाग में भी एसडीओ के पद पर रहते हुए इसने सैकड़ों कारगुजारियां की फिर का.यं., अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता के रूप में भी इंदौर में रहकर हजारों ल.उ.नि के फर्जी इंडेन्ट जारी कर स्वयं ही करोड़ों डकार गया तो दूसरी तरफ इसके अंतर्गत कार्यरत 15 से ज्यादा का.यं. से भी खुलकर वसूली करता रहा।

वर्तमान में इंदौर में मुख्य अभियंता केके सोनगारिया से उसे ज्यादा वर्ष एक ही स्थान पर हो चुके हैं। इसी जीएस डामोर के नक्शे कदम पर चल रहा हैं। इसको जबकि एक वाहन की पात्रता है पर ये हरामखोर भी तीन-तीन गाड़ियां टैक्सी परमिट की अपने पास रख रखी हैं। इसको जबकि एक वाहन की पात्रता हैं। पर ये हरामखोर भी तीन-तीन गाड़ियां टैक्सी परमिट की अपने पास रख रखी हैं। जिनके लॉग बुक की फोटो कॉपी भी नहीं दी जाती। दो अन्य टैक्सियों के भुगतान में एक उज्जैन से और दूसरी अन्य संभाग से चलाई जा रही हैं। जो एक पत्नी के लिए और बेटी के लिए काम आ रही हैं। 15 से ज्यादा संभागों के इंडेक्ट भी यहां से जारी किए जाते हैं। जिसमें बहुत से इंडेक्ट के सप्लाई आर्डस की कॉपीयां पत्रकारों को भी जाती है। उनका भी कमीशन ये जालसाज हरामखोर यही डकार लेता हैं। शासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों का अटैचमेंट और बदले में वसूली की प्रथा बंदकर रखी है इसके विपरीत 25 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों की पदस्थापना के मूल स्थानों पर कार्य करने की अपेक्षा अन्यत्र कार्य कर रहे हैं। इस जालसाज से सूचना के अधिकार में मांगी जाती है। कभी भी ये आवेदन के अनुसार जानकारी इसीलिए उपलब्ध नहीं करवाई जाती ताकि इनके कुकर्मों का यथार्थ सामने न आ जाए, दूसरी तरफ यहां इंदौर वृत्त का अधीक्षण यंत्री मिश्रा जिनका पुराना इतिहास भी भ्रष्टाचार का रहा है, इसे हरामखोर जालसाज और सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई, जबकि इसके पास 8 का.यं. जो इंदौर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन संभागों में कार्यरत हैं कि आती हैं। पर देने से साफ मुकर गए यहां वर्षों से बैठा मक्कार धूर्त स्टाफ जिसमें गोयल आदि हैं। अं.यं. से लेकर सबको महीना बांटता हैं, फिर किसी संभाग से टैक्सी का बिल भुगतान हो रहा हैं और टैक्सियां अं.यं., मु.अ. के घरों पर चल रही हैं। फिर अधिकांश टैक्सियां जो यहीं के अधिकारियों और कर्मचारियों बिना टैक्सी परमिट के ही विभाग में ऊंची दरों पर लगा रखी हैं। तो कैसे दे जानकारी और लॉग बुक की जानकारियां, इसलिए ये हरामखोरों और जालसाजों का सरगना हर अपील को खारिज कर देता हैं, दूसरी और हर जानकारी देने से साफ मना करवा देता, जैसे विभाग इन धूर्त गिद्धों के बाप की जागीर हो।

यही हाल तृतीय चरण नर्मदा परियोजना कार्यन्वयन इकाई में बैठे धूर्त बघेल, साथ में बैठा राजवाड़े, पूर्व में इसी में कार्यरत संजीव श्रीवास्तव अन्य के भी हैं। जिसमें प्रथम परि.स. प्रभात सांखला से लेकर ता. निगमायुक्त, संभागायुक्त, महापौर, जिलाधीश आदि क्षेत्रीय से लेकर भोपाल में बैठे शहरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव प्र.स. से लेकर मंत्री, मु.म. ने ए.वि.बै. से लिए रु. 650 करोड़ के ऋण से जो पाइप लाइन जलूद से वांचू पाइंट महू होकर इंदौर आई। वितरण प्रणाली और टंकियों निर्माण सबका कार्य 25 से 40 प्रश तक अधिक पर करवाया गया, जबकि एडीबी से ऋण से बनाई गई उन्हीं टंकियों का पैसा जेएन एनआर यू.एम से भी भुगतान कर भी अरबों की राशि उपरोक्त वर्णित धूर्तों ने हजम की, जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार में निगम के कार्यालय में जाने पर मिली, जबकि इस परियोजना के बनने पर इंदौर वासियों को 24 घंटे जलापूर्ति का जो विास्वप्न दिखाया था तो दूर शहर के 90 प्रश नगरीय क्षेत्र में अभी भी 2 दिन में मात्र आध घंटे ही पानी मुश्किल से मिल पा रहा हैं, तो 360 एमएलडी पानी कहां गया सब नई अवैध कॉलेनियों को बाइपास पर राऊ से लेकर मांगलिया, राजेन्द्र नगर, रिंग रोड की कालोनियों, फैक्ट्रियों को जलापूर्ति के नाम पर भी 600 से ज्यादा कालोनियों से भी लगभग वितरण लाइन बिछाने में और जलापूर्ति के नाम से भी रु. 200 करोड़ वसूले गए, अर्थात रु. 400 करोड़ से ज्यादा इस योजना में हजम किया गया, यही कारण था कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, उन्हें जवाब दिए उपायुक्त नगर निगम को सुनना थी, 4-6 महीने तक सुनवाई नहीं की गई, श्वानों की फौज नोंच खसोट कर स्थानांतरण कर चलती बनेगी, जबकि 90 प्रश पाइप लाइन सीधे खड़े खोदकर दबा दी गई, बिना रेती, गिट्टी बिछाएं।

दूसरी और अधीक्षण यंत्री जलापूर्ति राजवाड़े जिसने अपने कार्यपालन यंत्री के कार्यकाल में तो घोटाले और भ्रष्टाचार किए ही, अभी भी संभाग क्रं. 1 मंडलेश्वर और क्र. 2 इंदौरा में भ्रष्टाचार को संरक्षण देकर अपना हिस्सा बटोर रहा है, फर्जी कामों की जो लाखों रु. से करोड़ों में होते हैं, 1 व 2 को स्वीकृतियां देकर मोटा कमीशन हजम कर रहा हैं। झूठे या दोगुनी लागत की पाइप लाइन सुधार साथ मिलकर कार्य लो.स्वा.यां. से करवाकर मोटे बिल बनाकर ठेकेदारों के माध्यम से वसूली में जुटा हैं।

कां. यं. ग्रामीण संतोष श्रीवास्तव ऐतिहासिक भ्रष्ट रहे हैं। वर्तमान में भी सूचना के अधिकार में आदेश होने के बाद भी जानकारी की तो दूर मिलना भी पसंद नहीं करते, फर्जी चेक डेमो के बनाने और रखरखाव में खुलकर भ्रष्टाचार कर पैसा हजम किया जा रहा है, जानकारी मांगने पर स्टाफ की कमी का रोना रोकर दो वर्ष से जानकारी नहीं दी जा रही।

का.यं. खुराना धार के भ्रष्टाचार के कांड के पहले भी छप चुके हैं। समयमाया में जो बंगला यशवंत क्लब पर हथिया रखा था, छपने के बाद ही छोड़ा है, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, जानकारी देने के लिए जो हर जालसाज अधिकारी अपनाता हैं, ये भी वही अपनाते हैं। इसके भी ठेकेदार राजीव शर्मा के 2 टंकी निर्माण के ठेके रद्द किए गए थे, जोखिम और लागत के आधार पर इसके बाद भी इस हरामखोर ने उसे भुगतान किए, जिसमें रु. 4.50 लाख की वसूली बाकी थी। दूसरी ओर एक सहा. यंत्री आर के शर्मा के भाई होने के बाद भी राजीव शर्मा को ठेके दिए गए, जबकि रिश्तेदारों की ठेकेदारी पर शासकीय प्रतिबंध है, यहां भी पूरे मप्र के लो.स्वा. यांत्रिकीय संभागों की तरह निर्माण में भ्रष्टाचार 90 प्रश तक हुआ और ठेके कांग्रेसी नेता जोशी को दे दिए गए, चेक डेमो के निर्माण में भ्रष्टाचार देवास, शाजापुर, रतलाम, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, उज्जैन, आगर, बुरहानपुर सभी स्थानों पर 90 प्रश तक पैसा हड़पा गया।

उज्जैन के यांत्रिकी खंड में भी मशीनों के सुधार, तेल, डीजल, आदि में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जानकारी मांगी गई, एक बार कोरियर से पत्र भेजा गया,वहां बैठा ड्राफ्टमेन शैलेन्द्र सिंग, जो सारे फर्जी कारोबार, बिलों के भुगतान आदि की दलाली देखता है। पहले पत्रकारिता लेने के लिए दबाव डाला गया, जब स्वीकार करने की अपेक्षा भोपाल में अपील कर दी गई, तो वहां बैठे प्रभारी मुख्य अभियंता खरे ने सारे प्रमाण पत्रों को नकारते हुए, पत्र प्राप्ति को गलत ठहराकर अपील रद्द कर नस्तीबद्ध कर दी, दूसरी बार सीधे आवेदन दिया।

4 बिन्दूओं की जानकारी के लिए रु. 11 से ज्यादा मांगे गए, उसमें 3 बिंदु के रु. 356 जमा करने को कहा गया तो वहां बैठे जालसाज अनुरेखक शैलेन्द्र सिंग और कां.यं. (यांत्रि) न धन राशि जमा करने से मना कर दिया। मु.अ. खरे से कहा तो साफ मुकर गया कि मैं नहीं कहूंगा। आप अपने स्तर पर निपटो, अब बेचारे यही का.यं. ही तो महीना पहुंचाते हैं। कैसे कहे कुछ, लघु उद्योग निगम के इंडेक्ट से भी कमीशन हजम करता है, कैसे कहे कि अपनी जालसाजी का रिकार्ड दे, दो उज्जैन के साधारण खंड का.अ. उदिया बहुत श्याना और बारीक है, हरामखोर से जानकारी मांगी गई तो सीधा रु. 60000- 65000, जमा करने के लिए लिखता था, इस बार इस धूर्त ने रु. 2 की फोटोकॉपी के सीधे रु. 5 मांगे, यह जालसाज निविदा समिति जिसमें 4 अधिकारी होते हैं। स्वयं अकेले ही निविदा में खोलकर 4 अन्य के कार्यों को धन डकारने और हेरफेर की नियत से खुद ही कर लेता है। देवास का प्रभारी रहते हुए हराम खोर ने हस्ते प्राप्तियों की फोटो कॉपी के 15 माह के व्हाउचरों जो संख्या में 83691 के रु. 167382 मांगे, अर्थात सारे स्टाफ के बल हैंड स्लिप्ट ही बनाई। जबकि शासन ने लो. स्वा.यां. में है। अक्टू 14 से हैंड रिसीप्ट के भुगतान पर ही रोक लगा दी। लूट का के इस कारोबार ही प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी इस भ्रष्ट ने 4173 पत्रों के रु. 8346 की मांग की। उज्जैन के सिंहस्थ संभाग में भी सिंहस्थ के निर्माण कार्यों में खुलकर ऊंची दरों पर काम करवाकर वसूली का तांडव चल रहा हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर प्रमुख सचिव से लेकर नीचे का.अ. तक सबके सब अपने काले कारनामे छुपाने के लिए सारे जालसाज अनेकों हथकंडे अपना कर ही सिद्धकर देते हैं, कि वे कितने भ्रष्ट और जालसाज है।

इंदौर नगर निगम में दलालों और भ्रष्टों का जमावड़ा

इंदौर के 5000 सफाईकर्मियों को मात्र रु. 4500/- वेतन

हजारों कर्मचारियों को ठेके पर रख क़िया जा रहा वर्षों से घोर शोषण नियमितिकरण केवल दिवास्वप्न, जबकि हर वर्ष रु. 200 करोड़ हजम किये जाते हैं, नगर निगम इंदौर में फर्जी बिलों, जिसमें निर्माण, रखरखाव, खरीदी, स्वागत, बिजली, पानी सफाई के नाम पर

भाजपा का पिछले 15 सालों से नगर निगम इंदौर पर कब्जा है, सभी पार्षद जिन्होंने पार्षदी से पूर्व स्कूटर में पेट्रोल भराने में सोचना पड़ता था अब अरबों रु. संपत्ति के मालिक है। यही हाल निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी मलाईदार पदों पर कुंडली जमाये बैठे हैं। अरबपति है। यथार्थ यह है कि निगम विशुद्ध भ्रष्टाचार, लूट और जालसाजियों का अड्डा है, जिसमें पार्षद बनने के लिए भी चुनाव प्रचार में करोड़ों रु. का दांव खेला, शराब, शबाब और कबाब की सेवाओं से लेकर नगद धन भी पानी की तरह बहाया गया, आखिर कहां से आया यह धन, दूसरी तरफ कानूनी बत्तमीजियों से न केवल जनता से लूट की जा रही हैं, वरन् सफाई व अन्य दैनिक वेतन भोगियों को जिलाधीश मजदूरी तर रु. 251/- प्रतिदिन का भी 5000 से ज्यादा सफाईकर्मियों व अन्य को वेतन नहीं दिया जा रहा, उनकी कंप्यूटराइज्ड भुगतान पर्ची में रु. 4200/- व रु. 250/- सामग्री भत्ते के रूप में भुगतान किया जा रहा है, अर्थात 10-20 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत सफाईकर्मी जो कि कुशल श्रमिकों की श्रेणी में हैं, को नियमित वेतन भत्ते तो दूर, न्यूनतम दैनिक मजदूरी भी नहीं दी जा रही जबकि म.प्र. के श्रम विभाग का आयुक्त कार्यालय भी इंदौर में ही है, परन्तु उन्हें पिछले 50 वर्षों से इंदौर नगर निगम इन हजारों कर्मचारियों का यह शोषण नहीं दिख रहा, नगर निगम के भ्रष्टाचार के कई मुद्दों की समाज के कर्मठ कानूनी योद्धा क्षिर कोडवानी वर्षों से उठाकर विभिन्न न्यायालयों के मंच पर उठाते रहे हैं पर उन्होंने भी इन सफाई कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया, बेशक यह हाल सैकड़ों जल आपूर्ति में लगे दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को भी है, जिन्हें 20-30 वर्ष से ज्यादा यहां सेवा देते हो गये। ऐसे ही कर्मचारी अन्य 25 से ज्यादा विभागों, आंचलिक कार्यालयों में भी हैं। जिन्हें न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहाहै, आश्चर्य तो इस बात का है सारे श्रमिक संघों के पदाधिकारी भी इस मुद्दे पर मौन साधे बैठे हैं। यदि ठेकेदारों के श्रमिक भी है, तो भी सभी को न्यूनतम मजदूरी पाने का हक है, इसके विपरीत नगर निगम पूरे शहर की जनता से सफाई का कर अलग से वसूलती हैं, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर 6-6 माह तक जवाब नहीं मिलते। अपीलकी सुनवाइयां भी महीनों गुजरने के बाद भी किसी को फुर्सत नहीं रहती। हर विभाग में सूचना के लिये बाबुओं को सूचना अधिकार के जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपीले भी निगम आयुक्त सुनने की अपेक्षा दूसरे-तीसरे दर्जे के छोटे अधिकारी जिसमें और सह. और उपायुक्त ही निपटा देते हैं मामले को।

20-30 वर्ष तक उपयंत्रीयों, बाबुओं तक को पदोन्नतियां नहीं

सभी कार्य विभागों की धुरी, को धुर बना रहे प्र.अ.से प्र. सचिव

महाजालसाज, भ्रष्ट, डकैत, भा.प्र.से., पु. से, वन सेवा को ही नियमित पदोन्नतियां, सारे लाभ, बाकी शासन के सभी विभागों के अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर्स से लेकर नीचे बाबू चपरासी तक सब जानवर, जैसे हांके चलो जो मिले वो स्वीकारों

मप्र शासन में बैठे धूर्त, मक्कार, महाजालसाज, इंडियन एव्यूसिंहग, सर्विस अधिकारी जो यथार्थ में इस प्रदेश के असली खुदा हैं। जो मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों, पंचों, सरपंचों तक को अपने इशारे पर नचाते ही हैं। भले ही वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, इसके साथ ये ही खुदा शासन के सभी विभागों में बैठे रा.प्र.सेवा के अधिकारियों, इंजीनियरों और डॉक्टरों, कृषि वैज्ञानिकों से लेकर तहसीलदार, पटवारी, सभी विभागों के शिक्षकों और बाबुओं को तो न केवल नचाते हैं। वरन् उनका घोर शोषण भी करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य के अधिकांश विभागों में भले ही अधिकारी-कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ दिा जाता हो परंतु अनेकों विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों निरीक्षकों 20-30-35 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इन हरामखोर जालसाज और भ्रष्ट आईएएस की तानाशाही के चलते पूरे सेवाकाल में एक भी पदोन्नति इन श्वानों ने नहीं देने दी, जबकि हर विभाग में हर स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति, समिति की वर्ष में दो बार बैठके किए जाने के बाद पदोन्नतियां दी जानी चाहिए थी, इन धूर्तों को हर तीन वर्ष में शासन अनिवार्य रूप वि.प.स. की बैठक कर पदोन्नतियां वर्ष गुजर जाने के बाद भी पदोन्नति केबारे में ये शूकरों की फौज ने कभी सुध नहीं ली, जिससे पूरा शासकीय सेवक वर्ग भारी कुंठा में बेमन से कार्य करता है। दूसरी तरफ 1990 से सभी कार्य विभागों में जिसमें लो.नि.वि., लो. स्वा. यां., जल संसाधन विभाग, न.घा.वि.प्रा.,ग्रा.पा.से. नगर निगमों, पालिकाओं, एकेवीएस, विकास प्राधिकरणों तक में न तो उपयंत्री ही हर निर्माण कार्य की धुरी होता है, प्राथमिक स्तर पर सारे निर्माणों सुधार कार्यों से लेकर इन सभी विभागों के उपयत्रिंयों को हर कार्य में झोंक दिया जाता है। 20-30 वर्ष की सेवाओं के बाद भी इन्हें पदोन्नतियां न देकर शासन इन्हें धुर बना रहा हैं, पूर्व में 40 प्रश विभागीय पदोन्नतियां में इनका कोटा था, इसके विपरीत डिग्रीधारी इंजीनियरों जो कि विभाग के प्रमुख अभियंता पद पर रहते आए उन्होंने इनकी पदोन्नतियों की जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, जबकि हर विभाग की निर्माणों,सुधारों,साइटों पर इन्हीं उपयंत्रीयों का उपयोग किया जाता है, सर्वे, इस्टीमेट, नाप पुस्तिका, भरने देखरेख करने, कार्य संपन्न करने के हर कार्य की ये धूरी होते हैं। जब इन डिप्लोमा और डिग्रीधारी उपयंत्रीयों ने आंदोलन की राह पकड़ी तो जालसाजों जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान सचिवों, सचिवों, मुख्य अभियंताओं तक ने इनके आंदोलन को कुचलने कें कहीं कभी कमी नहीं छोड़ी, जबकि इनके अनुभवों और ज्ञान का सदुपयोग करते हुए इनकी पदोन्नतियां, परीक्षाओं से हर तीन वर्ष में और विभागीय स्तर पर हर 50 वर्ष में कर दी जानी चाहिए थी, इसके विपरीत 20-30 वर्ष में भी पदोन्नतियां तो दूर कई इसी पद से ही सेवानिवृत्त लेकर चले गए, आखिर शासन स्तर पर बैठकर ये इंडियन एव्यूसिंग सर्विस लॉबी से लेकर कार्य विभागों के वरिष्ठ अभियंतागण अपनी निम्न मानसिकता और नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के चलते एक तरफ इन सभी विभागों के 10000 ज्यादा डिप्लोमाधारी या उपयंत्रियों का भविष्य बर्बादकरते हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश की सड़कों, भवनों, कालोनियों, बांधों, नहरों, में इनके अनुभवों का व्यापक सदुपयोग नहीं कर पाते।

वहीं हाल पदोन्नतियों में आबकारी, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, वन आदिम, अनुसूचित, पिछड़ा जाति कल्याण विभाग, न्यायिक, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, ग्रामीण विकास, पंचायतों, जनपदों, जिला पंचायतों, जिलाधीश कार्यालयों, वाणिज्यकर विभाग, महिला बाल विकास, परिवहन आदि विभागों में अधिकारियों, शिक्षकों से लेकर बाबुओं तक का है, वास्तविकता में मानव अधिकारों का उल्लंघन भी हैं, और कर्मचारी अधिकारियों के लिए मानसिक प्रताड़ना का कारण भी जो कुंठा को जन्म देता है, दूसरी तरफ समय बीतने के साथ हर विभाग में 1990 की तुलना में कार्य भी चौगुना हो गया। कम्प्यूटर तकनीकी आ गई, परंतु मंत्रियों के नाम पर 1990 से अभी तक 95 प्रश विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती, विश्व व्यापार संगठन जो अमेरिकी धूर्तों को विश्व की जनता को नोंचने,दूसरे राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर मोटे लाभ कमाने के दृष्टिकोण से बनाकर, विश्व के उन्नति के शिखर तक बढ़ने वाले देशों के लिए बनाया गया था ताकि कम सेकम सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने मोटे लाभ की नीति पुख्ता की जा सकें के कारण भर्तियां ही नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप कई विभागों जैसे श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, खनिज आदि में आवश्यकता से 25 प्रश भी निरीक्षक, अधिकारी और कर्मचारी नहीं है, ये विभाग किसी प्रकार केवल औपचारिकताओं और विभागीय खानापूर्ति कर केवल दिखावे को चल रहे हैं। जबकि 1990 की तुलना में जनसंख्या के हिसाब से 4 गुना बढ़ चुका हैं, पिछले 10 वर्षों से सरकार में ठेकेदारी प्रथा बढ़ी हैं, अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कम्प्यूटर आपरेटर्स, निरीक्षकों आदि को संविदा नियुक्ति पर वर्ष दो वर्ष के लिए काम चलाने के लिए रख रही है, स्वा. विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वा. मिशन में सभी डॉक्टर्स लेखापाल से लेकर बाबु चपरासी तक संविदा नियुक्ति पर रखे जा रहे है, जिनकी भर्ती से लेकर, समय विस्तार, वेतन, भुगतान व अन्य सभी कार्यों में जिलाधीशों से लेकर मु.चि.अ. व अन्य सदस्य न केवल खुलकर वसूली करते हैं। महिलाओं का खुल कर यौन शोषण के बाद ही नौकरियां दी जाती हैं। चूंकि संविदा पर कार्यरत हैं, तो जो भी अधिकारी, नेता जहां जब बुलाए जाना पड़ता हैं और सब इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। वरन अगले दिन से संविदा समाप्त, से बत्तमीजियां लूट और शोषण पंचायतों, शिक्षा, लो.नि.वि., लो.स्वा.या., जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, वाणिज्यकर, नगर निगमों, पालिकाओं, कृषि जिलाधीश संभागीय कार्यालयों में आदि में पूरे प्रदेश के हर विभाग में चल रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सबसे बड़ी इसी योग्यता के दम पर संविदा नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्हीं की संविदा बढ़ाई जा रही है, जो सिर झुकाकर सबकुछ स्वीकार कर रही हैं। दूसरी और कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रूप में प्रदेश के 100 से ज्यादा मप्र शासन के विभागों, मंडलों, निगमों, सहकारिता आदि में कार्यरत 10 हजार से ज्यादा कम्प्यूटर्स आपरेटर्स, जिन्होंने 5 से 8 वर्ष से ज्यादा समय से सेवाएं दे रहे हैं। उनको क्यों नहीं उच्च लिपिक का वेतनमान देकर स्थाई किया जाता, इन आपरेटर्स को कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम के वेतन पर जोता तो जा रहा है, पर संविदा नियुक्ति वैसे शासन को तत्काल न केवल लिपिक वर्ग में वरन खाद्य एवं औषधि, खनन, शिक्षा, महिला बाल विकास श्रम औ.स्व. व सुरक्षा आदि में निरीक्षकों, उपयंत्रियों, सहा. यंत्रियों, नर्सों, शिक्षकों, सिपाही जेल और पुलिस आबकारी आदि में लगभग 3 लाख से ज्यादा तत्काल भर्तीयां करनी चाहिए, ताकि शासकीय कार्यों को तरीके से संपन्न किया जा सकें, अन्यथा 90 प्रश शास. विभागों में बढ़ते परिवेश में कार्य की समस्या और बढ़ेगी, अधिकांश विभागो में जिसमें लो. स्वा. यां, लो.नि.वि., जल संसाधन, ग्रा.यां.से. न घाविप्रा, वाणिज्यकर, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, अधिकांश विभागों में बढ़ता कार्य, घटता स्टाफ के चलते अधिकारी और कर्मचारी ऐच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर जा रहे हैं। जिससे कार्य की समस्या हर विभाग में और विकराल होती जा रही हैं या फिर सेवानिवृत्त अधिकारियों को विस्तार दिया जा रहा हैं।

संविदा नियुक्तियों में छोटे पदों पर तो कर्मचारियों को हर कदम घोर शोषण किया जा रहा हैं,पर बड़े पदों पर पर नियुक्त अधिकारी घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेहतर हैं कि उन्हें हर 3 वर्ष में परीक्षाओं के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को पदोन्नतियां देकर अधिकारी संवर्ग तक पहुंचाकर बेहतर कार्य किया जाए।

जहां भारत में 125 करोड़ की आबादी है, यहां कर कार्य को ठेका कर्मचारियों,या बाहर से ठेके पर करवाना, केवल कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और जालसाजियों में जनता का धन बर्बाद करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्या लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व नहीं है कि उन्हें रोजगार देकर देश का समुचित विकास किया जाए, पिछले 15 वर्षों में निजीकरण से विद्युत कंपनियों परिवहन, दूर संचार, राजमार्गों, आदि में भ्रष्टाचार और लूट के तांडव के अतिरिक्त क्या हो रहा हैं, विद्युत मंडल को विद्युत कं. में बदलने के बाद हर जगह त्राहि-त्राहि मचीह हुई है, वही हाल परिवहन और सड़कों में भी हुआ हर निजी क्षेत्र की कं. न्यूनतम लागत पर अधिकतम लूट मचा रखी हैं। दुर्घटनाएं, परेशानियां और अपराधों का तांडव हो रहा है, पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को नोंचने और चींथ व चींथवाने से बाज नहीं आ रहे, दूसरी और कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी के साथ घोर शोषण भी किया जा रहा हैं।

मप्र कृषक कल्याण व कृषि विकास बनाम कर्म. अधिकारियों का स्वकल्याण विकास

भ्रष्टाचार छुपाने, बैठाए बाहरी कर्मचारी

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने परे, जानकारी न देने, रचते है षड़यंत्र

गुजराती मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही कम से कम इस देश में किसानों के लिए इसके रहते हवा हो चुके हें। बाकी पूरे देश के मौसम ने बरसात के कारण किसानों को बर्बाद करके रख दिया, बेमौसम की इस बरसात की बर्बादी से हताश होकर पूरे देश में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली और कुद हृदयाघात से मर गए, उल्ट ही ही मोदी उसका वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मप्र के तोमर व अन्य ने सार्वजनिक मंचों से स्पष्ट कह दिया कि किसान अपनी नियति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ये श्वानों की फौज केवल उनकी उपज से लाभ कमाकर केवल अपनी मौज-मस्ती औरविदेश यात्राओं में जन-धन बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है।

इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में मुद्रा राक्षसों यथा अंबानी, अडानी, टाटा के हितों को संवारने न केवल किसानों के भूमि अधिग्रहण जैसे न केवल कानून बनाएगी वरन् उनके खाद बीज कीटनाशक, कृषि उपकरणों पर भी अनुदान में कटौती करते हुए बंद भी कर सकती है, जो कि अभी किसानों को लाभ का धंधा बनाने की बातें करते हैं।

वर्तमान में अकेले मप्र में ही कृषि के लिए केन्द्र व राज्य सरकार का लगभग रु. 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रहता है,जिसका लगभग रु. 10000 करोड़ मंत्रालय में बैठे प्र.स. सचिव, कृषि मंत्री, संचालक और मुख्यालय में बैठे परमार, त्यागी जैसे गिद्ध हजम कर जाते हैं। स्वाभावित है, ऊपर से जिलों में आने वाले नजर के लिए भी उपसंचालकों को भी मोटा कमीशन देना पड़ता है, स्वाभाविक है जिलों में बैठे उपसंचालक भी इस बजट का 10 से 15 प्रश हजम कर जाते हैं। बेशक इसमें सहा. संचालकों से लेकर बाबुओं और चपरासियों को भी फर्जी यात्रा भत्तों के बहाने बिलों के बहाने कुछ टुकड़े मिलते है, इसलिए सब चुप रहते हैं। हर वित्तीय वर्ष में एक जिला कृषि अधिकारी या उपसंचालक रु. 5 से 10 करोड़ हजम कर जाता है, ये हालात न केवल इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर आदि सामान्य जिलों के हैं वहीं आदिवासी जिलों जैसे धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा,खरगोन में रु. 10 से 15 करोड़ डकारने की है, बेशक यहां पर नियुक्ति के लिए रु. 25 से 50 लाख और जमे रहने के लिए रु. 15 से से 25 लाख भी देने पड़ते हैं, साधारण तौर पर सामान्य जिलों के लिए यह राशि रु. 10 से 20 लाख जैसी चाहत वैसी राशि देनी पड़ती है, जो कि अनुदान खरीदी के साथ कई योजनाएं कागजों पर पूरी कर करोड़ों की राशि हजम कर ली जाती है, इसके साथ खाद बीज, कीटनाशक विक्रेता अनुज्ञप्ति, नई और नवीनीकरण में भी दुकान के साइज के आधार पर रु. 15 से 25000 तक होती हैं, ये हाल पूरे मप्र के हर जिले के हैं।

आत्मा में भी जो किसानों को प्रशिक्षण और कृषि प्रबंधन के संबध में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, किसनों की यात्रा और प्रशिक्षण में 50 प्रश तक हजम कर जाते । यहां भी किसान रथ, किसान मेला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बेशक किसानों को लाभ मिला। इंदौर में उप सं. मीना ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए खास कामों के लिए अपने यहां के सहा. संचालकों को बाजू कर ग्रा.कृ.वि.अ. सेंगर को देपालपुर से, बाबु केएस शर्मा को रखा है, जबकि इनका वेतन संबंधित कृषि विकास खंडो से ही निकल रहा है, हालात तो ये है। भुगतान समस्या को देखते हुए 31 मार्च को बंद होने वाली रोकड़ 18 अप्रैल तक खुली रही और पुरानी तारीखों में भुगतान किया जाता रहा, खरीफ और रबी फसलों के सारे दलहन, तिलहन और अनाज बीज की सारी खरीदी स्वयं की, सूक्ष्म, सिंचाई के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के सारे कार्य संबंधित अधिकारियों को न देकर, स्वयं सारा माल हजम किए।

से.स. अग्रवाल इंदौर का संयुक्त संचालकत है चूंकि इन भ्रष्टों से सीधा महीना वसूलता है, इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी समय पर न दिए जाने व पत्र के समय बाधित और अपील लगाने के बाद पत्रोत्तर देने के विपरीत भी इस हरामखोर अग्रवाल ने अपील को खारिज कर दिया वहीं हाल उज्जैन के संयुक्त संचालक डीके पांडेय का भी था, जबकि संयुक्त संचालकों को संभागों में इनकी जालसाजियों को रोकने, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बैठाया परंतु ये धूर्त महीना खाकर अपना हाथ बचाकर जिलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर आंखे भींचे रहते हैं। फर.-मार्च अप्रैल में हुई किसानों की बर्बादी पर इन्हें किसानों को शीघ्र मुआवजे की पहल करनी चाहिए थी, परंतु वहां भी कमीशन खोरी के इंतजार में सरकसारी तरीके से ही कार्य संपन्न किया जा रहा है।

साप्ताहिक समय माया

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण

मु.मं., मंत्री, प्र.स. सदस्य से लेकर उपयंत्री, बाबु तक सब जुटे है लूट में

जनहितों से कोई मतलब नहीं, टर्न की परि. में भी महंगाई का लाभ देकर वसूली

मप्र की जीवन दायिनी नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों और उनकी नहरों के निर्माणों की आड़ में उच्च नर्मदा आंचत से लेकर निचली नर्मदा परियोजनाओं और सनावद स्थित इंदिरा सागर नहरों में कदम-कदम पर इसके निर्माण के प्रारंभ से लेकर अभी तक हर कार्य में कदम-कदम भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा हैं। फ्रि मुख्यालय में बैठे उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य, मु.म. शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री, सभी सदस्य पुर्नवास जो रजनीश वैश्य के पास है, सदस्य एसबी सिंह (पर्या. व वन) सदस्य एसके पंवार, सदस्य जे.एन. शिवहरे (अभि.) आयुक्त रेणु पंत (पुर्नवास एवं क्षेत्र) संचा प्रकाश बांगड़े और संचा. डीके दुबे से लेकर चारों मु.आ. कार्यालयों तथा रा.अ. बाई सागर बांध, नहरे जबलपुर, निचली संभागीय कार्या. में चारों तरफ भ्रष्टाचार का भारी तांडव हो रहा है और सभी लूट में लगे हैं।

जिसका छोटा सा उदाहरण है मुख्यालय के कार्यों का भुगतान करने का कार्य का.अ. अनिल दुबे सं.क्र. 23 से ही किया जाता है किराए पर टैक्सी लेने के मामले में अनु.क्रं.22/13-14 में 25 नग नॉन एसी इंडिका और 2 इंडिगो 2 एसी गाड़िया लेने के लिए अनु. राशि रु. 37.24 लाख रखी एक मात्र निविदा कॉपेक्ट सिक्युरिटी सर्विसेज की निविदा 35.9 अधिक पर मोटा कमीशन हजम कर दे दी गई,अर्थात एक मात्रा निविदा कैसे और क्यों आई, फिर 35.3 प्रश अधिक अर्थात रु. 50.61094 लाख में क्यों स्वीकृत अर्थात सीधे रु. 13 लाख हजम किए जबकि 10.12.14 की निविदा सू.क्रं. 15/वाहन/14-15 दिनांक 30.09.14 को अनु. राशि यह तुलनात्मक विवरण स्पष्ट करता है कि कैसी कमाई की जा रही है, वहीं निविदा रु. 15.55 लाख की निविदा इसी एजेंसी 4.57 प्रश कम पर एक वर्ष बाद दी गई, यह तुलनात्मक विवरण स्पष्ट करता है कि कैसी कमाई की जा रही है। वहीं निविदा रु. 15.55 लाख की रु. 14.84 लाख में हस्त प्राप्तियों पर एसई, एसडीओ,बाबु तक सभी किसी न किसी बहाने हजारों का भुगतान प्राप्त करते रहते हैं।

एक उपयंत्री एच.एस. कटारिया जो सहा. यंत्री के प्रभार में दिल्ली पुनासा ओंकारेश्वर विश्राम गृह दिल्ली में भी है। पुनासा में भी है और 18 नं. संभाग के उपसंभाग में भी प्रभारी है। ये है, मुख्यालय में बैठे शूकरों की जालसाजी का नायाब नमूना। इन्हें रु. 10000 का फुटकर खर्च अग्रिम दिया जा सकता है, पर वहा. क्र. 54 से रु. 15000 जिसमें रु. 14981 का खर्च दिखाया गया है, धूर्त ने 8 कमरों के विश्राम भवन में 60 हा के माध्यम से एस कुमार ड्रायक्लिनर दिल्ली को रु. 80746 का भुगतान करवाया, वहीं 61, 62 से रामकृष्णा इंटरप्राइजेस को रु. 46624 का, महेन्द्र सिंह चौहान वार्षिक आर एंड एम के नाम पर मा.पु.क. 117 पृ.क्र. 5 से 11 वहा. क्रमांक 64 से 67 के अंतर्गत रु. 1.79 लाख का भुगतान सित 14 में ल.उद्यनि. दिल्ली को व्हा. क्रमांक 6 से 15 तक में रु. 3,54,250/- का भुगतान किया। 16 से केशर ट्रेडर्स भोपाल रखरखाव के नाम पर रु. 71020 का, रावता इंटरप्राइजेस को विद्युत प्रणाली के रखरखाव के के नाम पर रु. 1,57,108 विशाल स्टेशनरी जो विशेष कृपामात्र है हर महीने वर्षों से हजारों रु. केवल कमीशन बांटकर कमा रहा है। 19 से 26 तक के व्हा. के माध्यम से सित. 14 में भी रु. 88980 का भुगतान महेंद्र सिंह को व्हा.क्र. 27 से 36 में रु. 2,54,172 लक्ष्मी इंटरप्राइजेस भोपाल ये भी नियुक्ति कमीशन बांटकर मुफ्त के बिलों का भुगतान लेने वाला दलाल है। इन भ्रष्ट जालसाजों का व्हा. क्र. 37 से 39 में रु. 340831 का भुगतान छप्पन भोग को व्हा. क्र. 41-42 से रु. 35280 का मैं. जीएस गुप्ता यांत्रिकीय खातों की सफाई नर्मदा भवन सित. में रु. 1,18,538, केशर ट्रेडर्स को व्हा. क्रमांक 50,51 से रु. 2,13,4831 का, व्हा.क्रमांक 52 से एचएच कटारिया को नियम विरूद्ध रु. 15000/- फुटकर खर्च हेतु। 03.10.2014 न्यायालय की अवमानना प्रकरण में शा. अधि. को भुगतान रु. 5500/- व्हा. क्रमांक 1, पहला श्री शीतल शा. अधिवक्ता को सरकारी खाते से भुगतान कैसे और क्यों फिर न्यायालयीन अवमानना में अधिवक्ता शुल्क का भुगतान कैसे जो कि संबंधित अधिकारियों को स्वयं जेब से भुगतना चाहिए था, 24.01.14 को व्हा. क्रमांक 27 से अभिसार भरत विक्रम सिंग को रु. 1,22,925/- का भुगतान, व्हा. क्र. 28 से अपोलो इलेक्ट्रिकल्स भोपाल को रु. 1,14,526 रखरखाव और चालन के लिए, यांत्रिक सफाई के नाम पर जीएस गुप्ता को 27.01.14 को रु. 1,28,900 का भुगतान नर्मदा भवन की सफाई के लिए, फोटो कॉपी के नाम पर धीरज प्रिथयानी को व्हा. क्रं. 43 से रु. 30693 का, व्हा. क्रमांक 44 से मे. संजय डिजाइनर्स व डेकोरेटर्स को रु. 4,26,500/- इंटरप्राइजेस को रु. 1,26,814 का भुगतान बहुरंगी फोटो कॉपी का, 01.02.14 को सार्थक कंस्ट्रक्शन को व्हा. क्रमांक 1 से रु. 13,7,698 का भुगतान, व्हा. क्रमांक 2 से महेंद्र सिंह चौहान को रु. 2,67,217 का भुगतान पुनः व्हा. क्रमांक 9 से इसी को रु. 1,20,971 का, व्हा. क्रमांक 16 से 2,49,336 का भुगतान व्हा. क्रमांक 23 से धीरज प्रिथयानी को रु. 2,45,235 का भुगतान यह कहानी न.घा.वि.प्रा. के हर संभागीय और उपसंभागीय कार्यालयों की है।

सं.क्र. 25 पुनासा ने 10.02.14 को व्हा. क्रमांक 1 से पयोनियर वाटर प्रूफिंग इंदौर को रु. 1,88,500/- व्हा. क्रमांक 2 से रु. 181,658, व्हा. क्रं. 39 से 814812 19.02.14 को च्वाइस पेपर को क्ष.क्र. 2,4,5, से सं स. 43200 का भुगतान, 20.02.14 को आर के टायपिंग व्हा. क्रमांक 19 से 25 तक में रु. 51325 का भुगतान, सुरभि कम्प्यूटर न. नगर का रु. 243201 का भुगतान युके फोटो कॉपी नं. नगर को व्हा. क्रमांक 31से 38 से रु. 68601 का भुगतान, 40 से सुपर फोटोकॉपी से रु. 4974 का, सौरभ जैन को व्हा. क्रमांक 41 से 43 से 70558 का भुगतान व्हा. क्रमांक 44 से वर्मा इंजि. को रु. 1,71,820 का भुगतान, व्हा. क्रमांक 52 से इंजी आईवीआरएस की रु. 27,11,33,375 में से रु. 25,46,34,426 के पूर्व भुगतान के बाद शेष रु. 1,64,969 जमा रु. 11,98,819 बाकी रु. 1,53,00,131 का चेक क्रमांक 501441 से भुगतान सारे पैसे में मीना को रु. 50 लाख मिले, व्हा. क्रमांक 53 से काम प्रालि को रु. 28,89,228 का भुगतान , फर 14 में लगभग रु. 2 करोड़ के भुगतान 90 प्रश भुगतान कर हरामखोर मीना ने रु. 1 करोड़ हजम किए। इंदौर सनावद के सभी संभागों जिसमें 8,9,12 भीकनगांव, लॉवर गाई नहर संभाग, 18,24 नहर संभाग खरगोन वृत्त क्रमांक 8,19,21,24,25, 28 वृत्त क्रमांक 11,14,27 व इंदौर निचली नर्मदा परि. ओंकारेश्वर नगर संभाग धामनोद, 32 बड़वाह, 16 कुक्षी, 20 मंडलेश्वर, 30 मनावर में पायोनियर वाटर प्रूफिंग को हर महीना लाखों रुपए के भुगतान किए गए इस को अग. सित. 11 में रुपए 10,02,810 का भुगतान 2011 में 21 नवम्बर से किया गया। हीरा इलेक्ट्रिकल्स सनावद को रु. 26,684 26 का भुगतान 2011 में किया गया। हीरा इलेक्ट्रिकल्स मशीनरी को रु. 5.67 लाख गौतम इलेक्ट्रिकल्स सनावद, मीडिया फोटो स्टूडियो खरगोन, बिप्पी प्रोफे. लेब इंदौर, को रु. 1,16,400 मे. ए-1 डिजीटेक को रु. 1,02 हजार एपी इंटरप्राइजेस को रु. 1,18,500 संजय फोटो कॉपी रु. 1,50 हजार, विशाल फोटोकॉपी सेंटर को रु. 3 लाख, मै. सुप्रीम साइबर कैफे को रु. 155 हजार, बाहेती फोटोकॉपी को रु. 46180 का भुगतान लिया यह एक वर्ष की एक संभाग की कहानी है उपरोक्त दी गई फर्मों को इंदौर सनावद के उपरोक्त सभी संभागों ने इस प्रकार के करोड़ों रु. के बिल पिछले 15 वर्षों में भुगतान कर हजम किए गए ये नग्ना. भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण की छोटी सी मिसाल है, यदि लोकायुक्त छापा मार कार्रवाई कर कड़ाई से पूछताछ करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय भी समय विस्तार और अवैध रूप से किए जा रहे महंगाई भुगतान की कमीशनखोरी से लपेटे में आ जाएगा। मुमं. शिवराज ने स्वयं कई ऐसे समय विस्तार के कार्यों में नोट शीट पर हस्ताक्षर किए, की टर्न की प्राजेक्ट में न समय विस्तार और न ही महंगाई भुगतान का प्रावधान होता है, पर तो भी इंदिरा सागर की नहरों, रानी अवंती बाई नहरों को पिछले 15 वर्षों से लगातार विस्तार देकर न केवल सभी संभाग वरन सौर मंडल कार्यालय मु. अभि. कार्यालय से पूरा मुख्यालय से लेकर मु.मं. कार्यालय तक सब धन उलींचने में लगे हैं। सारे हरामखोरों जालसाजों को काम से मतलब नहीं। शूकरों की फौज को धन चाहिए। बरगी बांध 1987 में बनकर तैयार हो गया था, परंतु 28 वर्ष में दायीं बाई नहरों का काम पूरा नहीं हो सका वहीं हाल अपर वेदा लोअर गोई बांधों नहरों का भी हुआ।

अब हरामखोर कभी नर्मदा क्षिप्रा लिंक, कभी नर्मदा गंभीर लिंक की अरबों रु. की उद्वहन, सिंचाई योजना के नाम से जन-धन की बर्बादी करने में लगे हैं। जबकि इसके पूर्व कठोरा, पुनासा, खरगोन, उद्वहन, परियोजनाओं और उनकी नहरों का ही अध्ययन कर लेते। हाल ही में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना जो कि अभी तक सफलता पूर्वक नहीं चल सकी है, इनका मात्र उद्देश्य बड़ी परियोजनाओं के सहारे मोटा धन हजम करना है, हाल ही में नर्मदा गंभीर लिंक की निविदाओं खोली गई। स्वीकृति के साथ ही 15 प्रश रु. 270 करोड़ से ज्यादा जिसमें 10 प्रश प्लांट और मशीनरों के लिए व 5 प्रश कार्यशील पूंजीपति के नाम से मात्र अपना मोटा कमीशन हजम करने के लिए स्वीकृत कर दिया गया जबकि मप्र सरकार रु. 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में चल रही है, कर्मचारी अधिकारियों को वेतन बांटने के पैसे नहीं है। पूरी तैयारी है, पहले जनकल्याण के नाम पर हजारों करोड़ रु. की बड़ी परियोजनाओं बनाओं अरबों रुपए कमीशन के हजम करों, शासन में लाखों करोड़ का कर्ज लो फिर बांध, नहरें, विद्युत उत्पादन, प्लांटों से लेकर सड़कें सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तक विद्युत कंपनियों, सरकारी चिकित्सालय जो सब जनधन से बनाई गई थी, सबको पूंजीपतियों के पास गिरवी कर दो, ताकि न केवल जनता से चलने का पैसा वसूले वरन सांस लेने का भी पैसा वसूले।

क्या कारण है उपाध्यक्ष राजनीश बैस 4 वर्षों से जमा है, क्यों उस हराम खोर जालसाज सेवानिवृत्ति बीपीएस परिहार के 6 वर्ष बाद भी फिर से सलाहकार के पद पर नियुक्ति दे दी गई, जिस भ्रष्ट अजनारे को कुछ आता जाता नहीं, उसे धार मंडल के साथ निचली नर्मदा परि. में मुख्य अभियंता का कार्य सौंप रखा है, जब सहा. मंत्री या निचली नर्मदा परि. में मुख्य अभियंता का कार्य सौंप रखा है, जब सहा. मंत्री था जब का.यंत्री था तब के किए कार्यों की समीक्षा ही कर लेते, परंतु करोड़ों रुपए की रिश्वत भ्रष्टाचार से ही तो बांटता हैं, सूचना के अधिकार की अपील सुनने में तो 23 अधिकारियों को बैठाकर अपील की सुनवाई करता है, खुद बिलकुल चुप बैठा रहता है। ओंकारेश्वर की सामान्य जल न की नहरें देखों जो सीधी 40 फीट से ज्यादा खड़ी काटी गई। दायी-बायीं तट नहरों का कार्य टर्न की में दिया गया तो महंगाई का भुगतान अरबों रु. में कर केवल कमीशन खोरी की जा रही है। बांई नहर में तो पानी तो दूर गाजरघास वर्षा जलभर जाने से ऊग आई। दायीं तट में प्रथम चरण का ही काम पूरा नहीं हुआ। दूसरे तीसरे चरण के काम में स्तरहीन काम तो हुआ ही तबियत से लूट पाट भी चल रही है। फिर धार मंडल और मु.अ. इंदौर के वर्षों से प्रभारी मात्र भ्रष्टाचार की लूट और लुटाओं के दम पर बैठाए गए है। वहीं हाल इंदिरा सागर नहर में मु.अ. युसी जैन प्रभारी व मंडल के अ.य. है। बियाणी, कर्णसिंह जैसे ठेकेदार इन्हें पालते हैं, और ये उनके इशारों पर नाचते हैं। जैसे दोनों बहुत ज्ञानी हो। आखिर इनके पितृ विभाग अप्रा जलसंसाधन में अधिकारियों, इंजिनियर्स का क्या अकाल पड़ गया। बेशक म.प्र.जल संसाधन में प्रमुख अभियंता चौबे को भी तीसरा समय विस्तार दे दिया गया, और प्रधान सचिव रा.र. जुलवानिया को भी 5 वर्ष से ज्यादा हो गए, दूसरी और उपयंत्री, सहा. यंत्रियों को 20-25 वर्ष बाद भी पदोन्नत नहीं किया जा रहा है।

अच्छे दिन अमीरों के, गरीबों को हर कदम परेशानी बढ़ा रहे

रु.10 का शपथ पत्र अब रु.100 में, वकील की फीस अलग

गरीबों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती भाजपा

मप्र की भाजपा सरकार का भोलू मामा अब तीसरी पारी में गरीबों को लूटने और परेशान करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वह हर कदम हर सरकारी कार्यों को संपन्न करने उसमें लगने वाले शपथ पत्र का ही मामला क्यों न हो, जो पूर्व में रु. 10 के गैर न्यायिक मुद्रांक पर बनता था, अब रु. 50 के गैर न्यायिक मुद्रांक पर बनने लगा है, जिसमें रु. 50 का टिकिट भी लगाना पड़ता है, जिसमें रु. 50 से 100 वकीलों की मेहनत और नोटरी मिलाकर रु. 300 में न्यूनतम पड़ने लगा है, बेशक अमीरों का तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गरीबों के लिए तो उसकी दो-तीन दिन की मजदूरी के बराबर पड़ने लगा है, जबकि शपथ पत्र गैस कनेक्शन, गरीबी रेखा का कार्ड, स्कूलों में प्रवेश व अन्य अनेको स्थानों पर नौकरी के आवेदन में भी अनेकों स्थानों पर लगाना पड़ता है। ये भी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के अच्छे दिनों के आने की शुरूआत, देखिए अभी आगे होता है क्या अभी तो मोदी के साढ़े चार और शिवराज के चार वर्ष बाकी है। सरकार भले ही केन्द्र की हो या राज्य की, दोनों ही जनधन को अपने बाप की जागीर समझ, अनाप-शनाप तरीके से खर्च करने पर तुले हैं। मप्र के भाजपाई मुख्यमंत्री शिव राक्षस अपनी तीसरी पारी में जनता को हर तरह से नोंचने पर तूला है, जिसमें शपथ पत्र के रु. 10 के गैर न्यायिक मुद्रांक पर रु. 50 का मुद्रांक लगाना अर्थात सीधा 5 गुना, किराएदारी में रु. 100 का स्टाम्प बढ़ाकर रु. 500 का स्टॉम्प लगाना अनिवार्य कर दोनों हाथों से जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है।

अब रु. 10 और रु. 50 का स्टॉम्प भी मिलना मुश्किल कर दिया गया है, आमजन की हर सरकारी कार्य में शासकीय स्तर पर वसूली के बाद भी रिश्वत भी दोगुनी देनी पढ़ रही है, सरकार में भले ही घोषणा कर दी हो कि स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र शासन में स्वीकार किया जाएगा परंतु ऐसा कहां हो रहा है। न्यायालयों, आय-जाति व अन्य प्रमाण पत्रों में अभी भी नोटरी किया हुआ शपथ पत्र देना पड़ता है। ये गरीबों के लिए सरकार है, जो लूट का कोई मौका गरीबों से वसूली का छोड़ना नहीं चाहती। भाजपा की सरकार मुख में राम बगल में छुरी चलाकर हर कदम गरीबों के मुंह से निवाला छीन अपनी जेबें भरने के लिए, शासकीय शुल्क बढ़ाकर लूट रही है। जबकि 90 प्रश स्टॉम्प विक्रेता रु. 10 का स्टॉम्प रु. 15 में रु. 50 का , 60 और 65 प्रश में बैच रहे हैं थे जिसकी अनेकों खबरें दैनिक समाचार पत्रों में छापने के बाद भी ऐसे धूर्तों और अवैध वसूली करने वाले स्टॉम्प विक्रेताओं पर मोती बंगले में बैठा लोकायुक्त भी कोई कार्यवाई नहीं कर रहा। इसके विपरीत सच यह भी है कि कोषालय में स्टॉम्पों की बिक्री करने वाले स्टाम्प विक्रेताओं से 1000-2000 रुपए महीना वसूलते हैं। अन्यथा उन्हें सटाम्प नहीं देते जानबूझकर रु. 20, 50,100 के स्टाम्पों की हमेशा वसूली चलती रहती है। जिसका फायदा स्टॉम्प विक्रेता उठाते हैं।

विद्युत कं. के भ्रष्टाचार और लूटके झटके से प्रदेश की जनता परेशान

रु. 9000 करोड़ विद्युत खरीदी, रु. 950 करोड़ ग्रिड सेपरेशन के नाम वसूली

आईएएस प्र.सं. बनने के बाद हजारों करोड़ रु. हजम कर जानबूझकर घाटा दिखाकर बढ़ाते है कीमतें, जालसाज गिद्ध नोंचकर निजी क्षेत्र में सौंपना चाहते हैं

रखरखाव का 70 प्रश अरबों रु. हजम, नए खंबे खड़े होने से पहले ही टेड़े, बि में 4-5 बार कटौती, सीएम हेल्प लाइन शिकायत नहीं लेती, बंद करें कंपनियां, मंडल बनाओ

मप्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद बिजली की कीमतों में हर साल बढ़ोत्तरी की गई। विद्युत ियामक अयोग अपने आप के योग पूर्ण होते ही जनता की सुनवाई की औपचारिकताएं पूर्ण कर विद्युत कं. की कीमतें बढ़ाने की इच्छाएं पूर्ण कर जनता को नोंचने के लिए छोड़ देता हैं, फिर विद्युत नियामक आयोग में वर्षों से बैठा धूर्त अध्यक्ष राकेश साहनी मुख्य सचिव पद से सेव निवृत्ति के बाद भी सारे राजसुखों का भोग करवाने के लिए बैठाया गया है।

सभी विद्युत कं. जिन्हें मप्र विद्युत मंडल को भंग करके बनाया ही इसलिए गया था कि इन हरामखोरों जालसाज इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को नोंचते खसोट के लिए बैठाकर अच्छे खासे लाभ में चलते मंडल की कंपनियों में घाटा दिखाकर निजी हाथों में खरबों रु. की संपत्ति को सौंपा जा सके, आखिर गिद्धों की ये फौज कं. का ऑडिट क्यों नहीं करवाती दिल्ली में जैसे ही ऑडिट की बात उठी तो सभी कं. को अपनी पोल खुलती दिखी तो सारी विद्युत आपूर्ति कं. हिल्लाने लगी, जबकि पूरे देश में हर राज्यों के जो विद्युत मंडल थे उनमें आंतरिक अंकेक्षण के साथ ही बाहरी अंकेक्षण की महालेखाकार का समूह भी खातों की जांच करने आता था, अब जबकि सारी कं. सरकारी है तो इनकी आंतरिक और एजी अंकेक्षण क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत में ये सारे जालसाज क्यों नहीं वास्तविक चिट्ठा बनाते चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते इसलिए नहीं बनाए जाते कि इन इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के बैठे प्रबंध संचालकों की सारी लूट खंसोट का विवरण आ जाएगा जनता के सामने कि कितने की विद्युत क्रय की कितना पूंजीगत, कितना आगमगत, कितना रखरखाव में खर्च किया। उल्टे ही ये हरामखोरों और इनके साथ बैठाए गए पूर्व के महाभ्रष्ट जालसाज इंजीनियर्स जो अधिकतम सेवानिवृत्ति पा चुके हैं उन्हें ही संविदा नियुक्तियां इसीलिए दी गई है ताकि उनके माध्यम से हजारों करोड़ हजम किए जा सके, प्रदेश में स्वयं का 3500 मे.वा. का उत्पादन जल व ताप विद्युत से स्वयं का हो रहा है। बाकी 1000 मे.वा. की खरीदी में रु. 9000 करोड़ का खर्च कैसे दिखाया गया, फिर ये जालसाज जब विद्युत आधिक्य होता है तो सस्ती विद्युत बाहर बैच देते हैं, और अधिक खरीदी दिखाकर 25 से 50 प्रश का हजारों करोड़ का कमीशन डकार जाते हैं। इस 9000 करोड़ की खरीदी में से भी इन जालसाजों ने रु. 5000 करोड़ डकारे वहीं हाल ग्रिड सेपरेशन जिसकी मूल उद्देश्य छोटे-छोटे खंड बनाकर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में रु. 950 करोड़ खर्च दिखाया, जबकि यह कार्य भी मात्र रु. 300-400 करोड़ से ज्यादा का नहीं था, परंतु कमीशन की दृष्टि से ही 50 प्रश से ज्यादा की डीपीआर बनाई जाती हैं।

अभी जिस कं. को पोल लगाने का ठेका दिया गया है, उसका काम इतना स्तरहीन है कि खंभे खड़े होने से पहले ही टेड़े हो गए हैं। अर्थात थोड़े से आंधी तूफान में लाइनों का लोड बढ़ते ही न केवल खंभे उखड़ेंगे, मुड़ेंगे, बिजली बाधित करने के साथ ही दुर्घटनाओं जान-माल की हानि भी करेंगे, पर इन सबसे किसी को कोई मतलब नहीं है, ऊपर से स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं। स्वाभाविक है कि, इस ठेके में भी 25 से 40 प्रश कमीशन हजम किया हैं। गांवों को 24 घंटे लाइट देने के इस सिराज ने चुनाव के पहले बड़े सपने दिखाए था। गांवों में 24 घंटे की तो दूर इंदौर जैसे शहर में ही दिन में 5-7 बार विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है। आधा घंटे से लेकर 2-2 घंटे तक, शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की गई परंतु कोई फायदा नहीं निकला, हर दिन विद्युत बाधित होने पर जब बार-बार शिकायत की गई तो उल्टे ही जवाब मिला कि पुरानी शिकायत पर ही काम चल रहा है। अगली शिकायत नहीं की जा सकती।

विद्युत बिलों में भी मनमानी रीडिंग दिखाकर ग्रामीण और शहरीय क्षेत्रों में इन जालसाजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1980 के दशक का अधिकांश स्टॉफ रिटायर हो चुका है। नई भर्तिया नहीं की जा रही, सारे काम ठेके पर करवाने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हर जगह लूट खंसोट और लापरवाही की जा रही है। ठेके के स्टाफ को भी ठेकेदार दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन देकर प्रताड़ित करता है, इन सबका परिणाम जनता को ही चुकाना पड़ता है।

मप्र औद्योगिक केंद्रीय भ्रष्टाचार विकास निगम

भ्रष्टों, जालसाजों की फौज नहीं होने देगी औद्योगिक विकास

सब का उद्देश्य विकास के नाम पहले हो स्वविकास, कदम-कदम करती है परेशान और वसूली, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर धूर्तों, मक्कारों की फौज साल-साल भर नहीं देती जानकारी

मप्र औद्योगिक विकास निगम में भोपाल से लेकर उसके आठों क्षेत्रीय कार्यालयों यथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन आदि में वर्षों से जमे भ्रष्ट धूर्त प्र.सं. महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, सहा. मुख्य प्रबंधकों से लेकर उपयंत्रियों और बाबुओं का एक स्थान पर जमे रहकर, हरामखोरों की ये फौज उद्योगपतियों को हर कदम अपनी वसूली के लिए परेशान करती हैं। यही कारण है कि सन् 2006 से न केवल इंदौर वरन् ग्वालियर, खजुराहों किए वैश्विक निवेशक मिलन समारोहों में आने वाले बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर राजदूतों तक सब आए और वादे भी किए, परंतु यहां बैठे भ्रष्ट धूर्त गिद्धों की नोंच-खंसोट से हारकर 80 प्रश वादे करने वाले उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने की तो दूर पटलकर भी नहीं देखा, जबकि हर निवेशक आयोजन में रु. 10 करोड़ से 100 करोड़ तक कागजों में खर्च दिखाया गया, जिसमें निगमों, विकास प्राधिकरणों, लो.नि.वि. व पुलिस की सुरक्षा व प्रशासनिक खर्चे भी शामिल हैं, जो जन-धन अंतर्गत वसूले गए करों का हिस्सा या बेशक ये मु.मं. सिराज व उनके अन्य मंत्रियों के साथ आईएएस लॉबी का दोहरे षड़यंत्र का हिस्सा था, जिसमें जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने अपने विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को नकार, जनता को अपने सफल शासन, जनता को रोजगार दिलाने, औद्योगिक विकास के बहाने अपने काले धन को निवेशित कर, प्रसार माध्यमों में जनता के न केवल पूरे देश में वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और स्थापित करने में जन-धन की अरबों रु. की बर्बादी करना भी था।

दूसरी ओर जिन उद्योगपतियों ने यहां स्थापित करे थे, इसे एकेवीएन की लूट और भ्रष्टाचार के चलते 40 प्रश से ज्यादा उद्योगपतियों ने हजारों लोगों को बेरोजगार बैंकों के अरबों रु. की ऋण राशि न चुका पाने के कारण बंद कर जाने के लिए मजबूर हो गए ये हालत इंदौर के एकेवीएन के अंतर्गत आने वाले 12 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों यथा इंदौर का सांवेर रोड, पीथमपुर, देवास रोड, निगरानी सेज आदि सभी के हैं, जहां बिजली पानी, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स तक की आधारभूत सुविधाओं के नाम पर यहां बैठे ये इंजीनियर्स प्रबंधकों से लेकर धूर्त एमडी तक वसूली और भ्रष्टाचार में गले तक लिप्त रहते हैं।

वैसे भी इंदौर एकेव्हीएन में बैठा प्र.स. मनीष सिंघ खानदानी भ्रष्ट और जालसाज है, जिसने नगर निगमों से लेकर, हर पदस्थापना में जालसाजियां व भ्रष्टाचार किए और अब लूप लाइन में इंदौर के एकेव्हीएन में नियुक्त की दिए गए इनका पिता मोतीसिंग जो भोपाल में गैस कांड के समय जिलाधीश था और अरबों रु. डकार उस एंडरसन को 5 दिसम्बर 1984 को अपनी शासकीय गाड़ी में बैठाकर भोपाल हवाई अड्डे से भगाया था, फिर यहां बैठा मु.म.प्र. एचआर मुजाला की जालसाजियों और लूट का 23.01.11 से पूर्व का भी इतिहास रहा है। इंदौर एकेवीएन में भी धन बांटकर ही प्रति नियुक्ति पर आए है। हर त्रिवेशक मिलन समारोह में इस बंदे ने भी रु. 5 से 10 लाख हजम किए, फिर बेटमा, पीथमपुर व अन्य पर उद्योगों के लिए जमीन तलाशने, भूस्वामियों से समझोता अधिग्रहण, विकास आदि के हर कार्य में 2 से 5 प्रश तक हिस्सा इस हरामखोर का होता है, यही कारण है कि ये मप्र के त्रिवारी, मप्र एसएस ठाकुर, एएस चौहान, प्रबंधक ओपी बोरीवाल, प्र.पवन विजयवर्गीय, प्र. अनिल अरोरा,प्र. पंकज जोशी उप प्रबंधक पी गेठेवाला व अन्य सभी अपनी जालसाजियों और कुकर्मों को ढांकने शूकरों की फौज जानकारी नहीं देती, लोकायुक्त अगर इनके मोबाइलों के पिछले सालभर की रिकार्डिंग सुनी जाए तो भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कांडों की पर्ते खोली जा सकती है। वैसे भी अधिकांश करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं।

खाद्य एवं औषधि विभाग- अंधेर नगरी, भ्रष्टराजा, तू भी खा हमें भी खीला जा

उत्पादकों के वर्षों से नमूने नहीं, बस महीना वसूली

वर्षों से कुंडली मारे बैठे खाद्य व औषधि निरीक्षक, लूटो और लुटाओ

मप्र का खाद्य व औषधि निरीक्षक विभाग पूरे प्रदेश में शासकीय औपचारिकताओं निभाने का साधन बन गया हैं जिसमें खाद्य व औषधि निरीक्षक अपनी मासिक तिमाही, छ माही व वार्षिक वसूली करके, अपने अंगद की तरह पैर जमाए बैठे रहने के लिए जो भी नया नियंत्रक आता है उसकी छः माही या वार्षिकी लाखों में चुका कर एक ही स्थान पर वर्षों से जमें है। शासकीय खानापूर्ति और अपनी वसूली के लिए नमूने लेने की औपचारिकतएं पूरी कर रहे हैं। देवास में खा.अ. सुषमा पथरोड़ को, उज्जैन सु.अ. वर्षा व्यास, दीपक टटवाड़े आदि पूरे प्रदेश में 2008 की भर्ती वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी सह. खानि. में से अधिकांश एक ही स्थान पर 3 तो दूर 5-7 वर्षों से भी ज्यादा हो चुके हैं। सबने खाद्य.नि. में से अधिकांश को एक ही स्थान पर पूरे प्रदेश और देश भर से दुग्ध विक्रेता करोड़ों लीटर नकली दूध, टनों से घी, खाद्य सामग्री में मिलावट कर खिला पिला रहे है, परंतु प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज अग्रवाल को अपनी वसूली के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, यहां तक कि सांची और अमूल का दूध, घी व दुग्ध उत्पाद न केवल स्तरहीन वरन् कीटनाशक युक्त तक होते हैं। जिनके पिछले25 वर्षों से ज्यादा समय से नमूने ही नहीं लिए गए, उसकी थैली पर मुद्रित मात्रा में न फेट होता है, न अन्य पदार्थ चूंकि शास.-सहकारी संस्था है इसलिए गुणवत्ता का असली दूध केवल सरकारी अधिकारियों को ही मिल पाता है। जनता तो पावडर निर्मित ही, ताजा कहकर 30 से ज्यादा वर्षों से बैचा जा रहा है। गर्मी के मौसम में बिकने वाले पानी पाउचों, बोतलों, हल्के पेय पदार्थों में भी कीटाणु व जीवाणु रहित बनाने के लिए कीटनाशकों का खुलकर प्रयोग हो रहा है। नमूने लेने के मामलों में अधिकांश की स्थल पर ही जमावट से लेन-देन हो जाता है। नहीं हुआ, जांच में भेजा गया तो भी अगर अमानक पाया भी गया और प्रकरण लगा भी दिया मजबूरी में तो भी इस कानूनी प्रक्रिया को कमजोर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक कि एक प्रकरण में रहा सु.अ.अमित वर्मा से पूछा गया कि आपने नोटिस क्यों नहीं तामिल कराया तो सरकारी वकील से बोला गया सर अपना ही आदमी है। अधिकांश प्रकरणों में पेड खाद्य के नमूने लेने पर हरामखोरों की ये फौज पूरे मप्र में उत्पादक को पार्टी नहीं बनाती, नमूने अमानक पाए जाने की रिपोर्ट पर संबंधित पक्षकार को पहले बता देती है, उसे बचाने की कोशिश भी ले देकर यही कर रहे है।

औषधि निरीक्षकों की फौज भी चारों तरफ महीना वसूली में ही विश्वास रखती है। अकेले इंदौर में ही आईव्हीएफ की 20 से ज्यादा फैक्ट्रीया हैं। हरामखोरों से पूछो कि कितने नमूने लिए गए, महीने तो दूर वर्षों से नमूने नहीं लिए गए, फिर इंदौर में बैठे गोयल, ठाकुर भिगोनिया जो इन सबके लिए जिम्मेदार है। उन्हें महीना वसूली से फुर्सत ही नहीं है। दवा दुकानों से भी चूंकि रु. 5000/- प्रति तिमाही बंधा है। दवा बाजार की 700 दुकानों से भी रु. 3000 मासिक की वसूली होती है, इसलिए नमूने लेने का तो सवाल ही नहीं है। यही कारण है कि 50 प्रश दवा विक्रेता स्वयं दवाएं ग्राहक की बीमारी के हिसाब से बेच रहे हैं। फिर कौन देखें कि औषधियां समय बाधित है, सिस कं. की है, तो फार्मा के मप्र में 350 से ज्यादा कॉलेज है, जिसमें अकेले इंदौर में ही 35 कॉलेज है, जिनके पास न अच्छे शिक्षक है, न अच्छी प्रयोगशाला फिर भी डिग्री बांटने की इन दुकानों पर मोटी फीस हजम कर डिग्रिया बांटी जा रही है। वहीं डिग्री यथार्थ में ये बी फार्मा अब दुकानें खोलकर एमबीबीएस डॉक्टरों की बिना पर्ची के दवइयां बैच रहे हैं। यह हाल इंदौर की पालदा, शांति नगर, मूसाखेड़ी, प्रजापत नगर, बाणगंगा की बस्तियों से लेकर मप्र के हर जिलों से लेकर ग्रामीण इलाकों के भी है। पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एमडीएम से लेकर इन औषधि निरीक्षकों को अपनी वसूली और भ्रष्टाचार से फुर्सत मिले तो कहीं नमूने लेने, दवा दुकानों के निरीक्षण की सोचें।

इन हरामखोरों जालसाजों को जानकारी मांगने के लिए पत्र दो तो ये अपने मुख्यालय के पत्रों को भी पी जाते हैं। मुख्यालय भी इन सब तथ्यों को गंभीरता से नहीं लेता। वहां बैठा पूरा स्टाफ अपनी वसूली इन खाद्य व औषधि निरीक्षकों से कर तान के सोता हैं वहां बैठा नियंत्रक पंकज संयुक्त आयुक्त शुक्ला से लेकर चपरासी तक को अपनी इन हन हरामखोरों से वसूली मतलब है। जनता को न केवल खाद्य वरन औषधियां भी न केवल स्तरहीन और महंगी मिल रही है वरन् भविष्य में कौन सा खाद्य दूध, पेड सामग्री, बी फार्मा द्वारा बैची गई औषधियां भविष्य में मानव शरीर पर क्या असर डालेगी कोई भरोसा नहीं।

साप्ताहिक समय माया

आधार कार्ड या आमजन की बर्बादी व मृत्युनामा

पेज 1 का शेष

धूर्त पी. चिदम्बरम अंबर का खास मित्र नंदन नीलकेणि जो सत्यम घोटाले का महानायक था, अनेकों वित्तीय घोटाले में आरोपी होने के बाद भी आधार कार्ड की योजना उसी धूर्त शातिर नीलकेणी के दिमाग की उपज थी। जिसे पूरे कांग्रेस गिरोह ने अंजाम ही इसलिए दिया था, ताकि लोगों के बैंक खातों से सीधे ही पैसा निकालकर हजम कर लिया जाए, इसलिए प्रारंभ में इस रु. 200 करोड़ की योजना को संसद में भारी जनहित के सपने दिखाकर अंजाम दिया गया, जिसने पिछले 5-6 वर्षों में जनता से वसूले गए करों की धन राशि का रु. 7488 करोड़ 31-12-14 तक खर्च किया जा चुका है, यह तथ्य संसद में सरकार ने स्वीकारा है, इस आधार कार्ड के अधिकांश ठेके दक्षिण भारतीय चिदम्बरम के मिलने वालों लोगों के पास थे जिन्होंने छोटे-छोटे ठेके क्षेत्रीय और प्रादेशिक कं. को दिए, अर्थात यह शुरूआत इस धूर्त पी. चिदम्बरम और उसके साथी नंदन नीलकेणी ने इसलिए की थी, कि आधार कार्ड के माध्यम से जनता के हर व्यक्ति की जैविक, भौतिक और आर्थिक स्थिति की सांख्यिकी जानकारियां निजी फर्मों को देकर जो इसकी थी, आसानी से जनता को विभिन्न उलझनों में फंसाकर लूटा जा सके, ये सारी सांख्यिकी जो आधार कार्ड के माध्यम से जिस नंदन नीलकेणी की कं. के पास इंटरनेट पर संग्रहित की गई और की जा रही है, उसमें गूगल भी सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, अर्थात भारत की जनता की सारी जानकारी, सरकारी तंत्र के पास, वार्ड जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हो न हो, परंतु नंदन और गूगल के पास जनता की जैविक, भौतिक और आर्थिक जानकारी है, जिसे भारत में पंचों, सरपंचों, नगर पालिकाओं, परिषदों, निगमों, विधायकों और सांसदों के चुनावों में न केवल राजनैतिक पार्टीयों से लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों तक पूरे देश में नंदन की निजी कं. के साथ लाखों करोड़ की वसूलीकर भारत में और पूरे विश्व की दवा उपभोक्ता वस्तु उत्पादकों की बहुराष्ट्रीय कं. को बैचा गया, जिससे आमजन की की व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी पूरे विश्व में फैल चुकी हैं, जिसका भारत में दाउद की कंपनी ने भी खुलकर सदुपयोग किया, इसके साथ ही ये सारी जानकारी न केवल भारत में बैठे इंडियन मुजाहिद्दीन, सिमी से लेकर आईएसए के आतंकवादियों के पास भी है, साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और चीन और पाकिस्तान ने भी ये सारी भारत की जनता की जानकारियां जो आधार कार्ड के माध्यम से इंटरनेट साइटों पर डाली गई थी, सब के पास संग्रहित हैं। इससे एक आम नागरिक को तो कोई फर्क क्या पड़ेगा, परंतु इस आधार कार्ड के जो सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों, मंत्रियों, तेल, संचार, जल, आपूर्ति, नगर निगमों, रेलवे आदि महत्वपूर्ण सेवाओं, बैंकिंग, बीमार, परिवहन, पुलिस, जेल, अधिकारियों जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। अहं जानकारियों उनके घर परिवार की जानकारियां इन आधार कार्ड के माध्यम से न केवल देश के वरन् दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठनों के हाथों में भी पहुंच चुकी हैं। जो उनकी व्यक्तिगत, परिवार की सुरक्षा और मौत का कारण भी बन सकती है, जो राष्ट्र की सार्वभौमिकता पर भविष्य में क्या असर डालेगी इसका अंदाजा इस शूकर नंदन नीलकेणी, पी. चिदम्बरम को भी नहीं होगा।

दूसरी और शातिर, बदमाशों, जालसाजों, ठगों के लिए घर बैठे लॉटरी का काम कर रही है। उन्हें आसानी से मोबाइल नं. उनकी जैविक भौतिक और आर्थिक जानकारी लेकर, उनसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के नंबर पूछकर अरबों रु. की रोज ठगी की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसे ठग शातिरों ने अलग-अलग शहरों और पतों के दस से बाहर कार्ड तक बनवाकर जैसे मो. परवेज खान, देवास, परवेज मंसूरी खान हाटपिपल्या, परवेज मंसूरी, 299 अंबेडकर नगर इंदौर, मो. परवेज मंसूरी जानकी नगर, इंदौर के नाम से फोटो में थोड़ा सा हेर-फेर कर बैंकों में खाते खुलवाना, ऋण लेना, डेबिट कार्ड लेना, मोटी राशि नामे डालकर अदृष्य या गायब हो जाना नई जगह जाकर, नए कार्ड बनवाना फिर कारोबार शुरू से दूर्घटनाएं तो हैं, जो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि आधार क्योंकि इस कार्ड में वर्तमान का पता है, जनम सिलेकर वर्तमान तक का इतिहास नहीं है, इसलिए ये अपराधियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण हथियार है, कहीं भी अपराध करों, यदि पकड़े जाओ तत्काल के आधार कार्ड को पता बताओ, गायब होकर नई जगह का आधार कार्ड बनवाओ, अपराध करो पकड़े जाओ, पुलिस से लेन-देन करो, पुराना आधार कार्ड लगाओ और सिद्ध कर दो कि, मैं तो था ही नहीं, मैं तो वहां का बासी हूं, उस दिन वहां का, और वहां के न्यायालय में यहां का रहवासी सिद्ध करों और बच के निकल जाओं, सरकारी योजनाओं का एक ही साथ अनेकों को आधार कार्ड से अनेकों स्थान पर लाभ लो।

भारत में बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यामांर और वर्षों से आसानी से हजारों किमी की सीमा से घुसपैठियों घुस पैठकर अवैध रूप से घुसकर रु. 1000-2000 की रिश्वत देकर अपने क्षेत्रीय रहवासी होने का प्रमाण पत्र आधार कार्ड वोटर आइडी कार्ड बनवाकर आसानी से भारत के नागरिक बन गए। एक तरफ अपराधों को अंजाम देते हैं। तो दूसरी तरफ आम भारतीयों से वसूले गए करों का भरपूर लाभ उठाते हैं, जिसके अंतर्गत राशन का गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, सरकारी अस्पतालों की दवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त मिलती है। इस काम में बीएसएफ की भूमिका पिछले 50 वर्षों से काफी संदिग्ध रही है। इस धूर्त मक्कार नंदन नीलकोणि ने एक तरफ पी चिदम्बरम के साथ मिलकर शासन से बजट में रु. 200 करोड़ की व्यवस्था करवाकर रु. 7500 करोड़ से ज्यादा खर्च करवा दिया जबकि शासकीय स्तर न तो केन्द्र में और न ही राज्यों में इसकी सांख्यकीय उपलब्धता शासन के हाथ में हैं और न किसी सरकार का कोई नियंत्रण, स्वाभाविक है गोपनीयता और इस समग्र सांख्यिकीय की कोई सुरक्षा का कार्य सरकार नहीं कर रही है। इस आड़ में केन्द्रों के कम्प्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने अपनी पेन ड्राइवों में लेकर देश में ही विदेशों में भी इन फ्रेंचाइंजी ठेकेदारों के साथ बैचकर अरबों रु. में बैचा गया। यही कारण था कि करोड़ों वोटर कार्ड और आधार कार्ड ने हर चुनाव में फर्जी वोटिंग भी की और हर पार्टी ने करवाई। जब तब भाजपा विपक्ष में थी आधार कार्ड का विरोध करती थी सत्ता में आते ही, उसने हर शासकीय कार्य को जिसमें गैस से लेकर राशन कार्ड के सस्ते अनाज की अनुदान राशि को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए जनता पर भारी दबाव बनवाकर जनता को भूखे मरने के लिए विवश कर खातों से जुड़वाया, अर्थात ये जालसाज मोदी भी कांग्रेस की लूट-खसोंट और जालसाजी से धन लूटने और लुटवाने में शामिल हो गया। जबकि नंदन की जालसाजी में पूरे भारत की जनता का डाटा एकत्रित कर लाखों करोड़ में बैंच बहुराष्ट्रीय कं. को उपलब्ध करवा भारत की जनता की हर आर्थिक गतिविधि पर नजर रख देश की जनता को अंत में पुनः गुलाम बनाने के षड़यंत्र का हिस्सा है। पर न ये कांग्रेस सरकार समझने को तैयार थी न ये मुखेरे जानवरों की पार्टी उर्फ भाजपा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी बाध्यता पर अंकुश लगाया, परंतु ये धूर्तों की फौज सर्वोच्च न्यायालय को न गिनती है, न सुनती हैं।

टैक्स का टिन नं. जीएसटी आदि जो सरकार थोप रही है, ये सब भी उस धूर्त मक्कार नंदन नीलकोणि का फैलाया हुआ जाल है, जो बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर क्षेत्रीय व्यवसायों को नष्ट करने का षड़यंत्र है, जैसे विदेशों से हुआ कारोबार बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में केन्द्रित हो गया, जो दुनिया भर में जनता को लूट रहे हैं। केन्द्र सरकार कांग्रेस की या भाजपा की जनता को पेट्रोल डीजल और गैस पर अनुदान देने की बात करती हैं, तो शायद पहले सोनिया इटली से मंगवाकर जनता को दे रही थी और अब मोदी के आका अंबानी और अडानी हरामखोरों जनता से केन्द्र 34 प्रश एक्साइज 8 प्रश सेस, शिक्षा, चिकित्सा,सड़क आदि के वेट मप्र सरकार वसूल रही है।

हेलमेट के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता पुलिस और प्रशासन को

पेज 12 का शेष

अब पुलिस की कहानी देखें प्रधान आरक्षक, सहा. उप. और थाना निरीक्षकों के पास उनके वेतन प्राप्तियों से 10 से 1000 गुना तक जो संपत्तियां है। आखिर वो कहां से आई, लोकायुक्त यह क्यों नहीं देखता कि कैसे ये सब अरबों रु. की संपत्ति के मालिक कैसे है। जहां-जहां इनकी पदस्थापनाएं हुई उस हर शहर में इनके दो-चार मकान कहां से खरीदे गए फिर शाम ढलते ही अधिकांश निरीक्षकों के लिए सुरा सुंदरी की व्यवस्था कौन सा गुंडा, माफिया कहां से, कैसे और क्यों कर रहा है।

क्राइम ब्रांच में बैठने वालों का हर दिन समाचार पत्रों में छपने वाली झूठी कहानियों के पीछे दैनिक समाचार पत्र वालों को कितने लाख रुपए महीना कौन बांट रहा हैं। सिमी के आतंकवादियों को कौन संरक्षण दे रहा हैं। उनकी गतिविधियां इंदौर से पूरे मालवा में संचालित हो रही है। ऐसी कोई शिकायत क्राइम ब्रांच को तत्काल 10 मिनट में संबंधित को खबर मिल जाती है। 299, अंबेडकर नगर इंदौर में रहते हुए परवेज मंसूरी खान को 2 वर्ष से ज्यादा हो गए, परंतु एमआईजी थाने को लिखने के बाद भी आज तक न तो सत्यापित किया गया, इसके पास बाइक हीरो होंडा स्पेलंडर क्रमांक एमपी 41 एमई 0323 है जिस पर पहले भास्कर लिखा था हरा धन का निशान था जो क्रं से ड्रग सप्लाई करता हैं, इस गाड़ी का नं. परिवहन विभाग की साइट पर खाली है, अनेकों बार सूचित करने के बाद भी कोई पूछताछ तक नहीं की गई। 24.02.15 शाकिर और उसके गिरोह ने जीतू यादव की हत्या कर दी थी, इसकी जांच में पुलिस का ही मुस्लिम अधिकारी शाकिर और उसके गिरोह सूचित करने के बाद भी कोई पूछताछ तक नहीं की गई।

24.02.15 शाकिर और उसके गिरोह में जीतू यादव की हत्या कर दी थी, इसकी जांच में पुलिस बल का ही मुस्लिम अधिकारी शाकिर जीतू यादव की हत्या कर दी थी। इसकी जांच में पुलिस का ही मुस्लिम अधिकारी शाकिर को पुलिस के विभागीय संसाधनों का उपयोग जांच में पुलिस विभागीय संसाधनों का उपयोग जीतू की लोकेशन देता था, यह बात समाचार पत्रों में छपी थी। उन्होंने इस अधिकारी का नाम नहीं छापा क्योंकि सबको धन मिल रहा था। इस शाकिर के गिरोह में फिरोज और इमरान थे।

जिन्होंने मिलकर जीतू की हत्या की थी। जबकि शाकिर व उसका गिरोह पंजीबद्ध गुंडों की लिस्ट में अनेकों थानों में है फिर भी ये मुस्लिम अधिकारी उसको सहयोग कर रहा था, पर धूर्त गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने न तो इन तथ्यों की जांच करवाई, न ही उसे इंदौर से हटाया गया, जिसका परिणाम है सिमी के गुंडों और आतंकवादी दिन दूने रात चौगुने फल-फूल रहे हैं। पूरे मालवा में। मांगलिया में खजराना व अन्य क्षेत्रों के मुस्लिमों ने मोर का शिकार किया। गांव के कुछ हिन्दू युवाओं ने उसे व उसके साथियों के साथ पकड़ कर बंदूक, मोर व गाड़ी के साथ पकड़ कर लसूड़िया थाना प्रभारी पीएस रानावत को सौंपा। भ्रष्ट रानावत ने स्वयं अपने स्तर पर कार्रवाई कर मोटी वसूली कर इतना कमजोर केस बनाया कि उन सब मोर के हत्यारों को न्यायालय से तत्काल जमानत मिल गई। वन विभाग को न तो मोर की मृत देह सौंपी गई, न पूरा प्रकरण ये वही रानावत जिन्होंने इंदौर में करोड़ों रु. की संपत्ति अर्जित की जिसका एक भवन भंवरकुआं चौराहे पर भी हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। लूटो और लुटाओं के दम पर ही इंदौर के विभिन्न थानों में जिंदगी पूरी कर ली, शासन-प्रशासन को अपने ये कुकर्म नजर नहीं आते। पूरे कबाड़ी मोहल्लो में अनेकों चोरी की गाड़िया रोज कटती है। चोरी का माल बिकता है। और उस क्षेत्र के थाने के पुलिसकर्मी जाकर अपना महीना वसूल करते हैं।

शहर के हर क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है,जो हर थाना क्षेत्र के संरक्षण में ही फलफूल रहा है, स्वाभाविक है, महीना बांटकर ही चलाया जा सकता है। हर दिन समाचार पत्रों में खबरें छपती है थोड़ी प्रशासनिक स्तर पर महिला बाल विकास , बाल विवाह रूकवाने की बड़ी-बड़ी खबरे छापकर अपने मुंह मिठू मियां न बन जाए पर यथार्थ में 14 से 40 वर्ष की स्त्रियों के अड्डे हर क्षेत्र में चल रहे हैं। पुलिस जानती है, औरतें स्वयं पैसे कमाई के लिए अपनी लड़कियों को काम के बहाने ले जाकर धंधे में लगा रही हैं। पर ऐसे पोश अड्डों से जो हर शहर के पोश इलावसे लेकर छोटी बस्तियों में भी चल रहे हैं। यहां से पुलिस महीना वसूल कर चुप है। अवैध ड्रग की आपूर्ति और बिक्री भी तेजी से पैर पसार चुकी हैं। इंदौर में बैठा नारकोटिक्स और संबंधित थाने महीना वसूली कर चुप बैठे हैं। हर थानेदार, सीएसपी, एसपी और आईजी व उनका स्टॉफ काम कम से कम हो और ऊपर की कमाई अधिकतम हो, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर देखिए कैसे गुर्राते हुए देखते हैं, जैसे बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया हो।

यातायात थाने तो हर कदम न केवल हेलमेट से वरन् वसूली के लिए यातायात के संकेतकों में भारी जालसाजियां कर रहा है। जहां वसूली करनी है अधिकांश स्थानों के टाइमर्स बिगाड़ रखे हैं। 90प्रश जो सबसे ज्यादा दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी फर्मों के हैं। 90 प्रश के पास वाहन चालन अनुज्ञप्तियां ही नहीं है।

10 प्रश वाहन न केवल मोटरसाइकलों, वरन् कारे व अन्य चार पहिया वाहन बिना नं. के ही दौड़ रहे हैं। 35 प्रश गाड़ियां गलत नंबर के साथ दौड़ रही हैं। 90 प्रश वाहन चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बाते करते हुए यातायात बिगाड़ते हैं व दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ट्रकों में ऊपर तक गिट्टी, पत्थर, रेत भूसा व अन्य सामग्री के साथ खुले ट्रकों में सरिया गर्डर्स भरकर लोगों में दहशत फैलाते चलते हैं। वो नहीं दिखते इन हरामखोंर जालसाज पुलिसवालों को, क्योंकि उनसे महीना वसूली हो जाती है। बस हेलमेट ही दिखता है। सिटी बसें, मैजिक ऑटो जो कि लहराकर तेजी से चलते हैं। उन्हें पकड़ने नहीं बनती क्योंकि महीना मिलता है, कमजोर कड़ी बाइक वालों को पकड़ो, वसूलों।

रेलवे को जनता की लूट का अड्डा बना दिया

पेज 12 का शेष

शीघ्र भर्ती कर, प्रशिक्षण देकर नियुक्ति देवें। चारों तरफ शत्रुओं यथा चीन, पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वर्मा, म्यामांर आदि राष्ट्रों से घिरा है, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को बाहरी ठेके पर अधिकांश कार्य करवाने की नीति भारी घातक होगी, चीन और पाकी घुसपैठियों की निगरानी न केवल दिल्ली वरन हर राज्य के मंत्रालयों तक में है, यदि गुजराती पक्का व्यापारी है तो पहले निवेश और खर्च तो करो कमाई के रास्ते तो अपने आप बनेंगे। माना कि केरल और बंगाल में साम्यवाद जिसे रूस और चीन हांक कर बर्बाद कर रहा था ज्यादा विकास नहीं कर पाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर न केवल खतरनाक साबित हुआ वरन् बीओटी सड़कें भी खराब हैं और लूट भी जारी है तो फिर रेलवे में सफलता की उम्मीद तो दूर बल्कि निजी क्षेत्र की लूट, भ्रष्टाचार और शोषण की नीति पूरे देश के रेल नेटवर्क को बर्बाद कर प्रतिदिन 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को भी हर तरह परेशान करेगी, सुविधाएं, शीघ्रता, सुरक्षित, सस्ता रेल सफर यात्रियों का स्वप्न न हो जाए। वैसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु और मोदी की पीपीपी की नीति यथार्थ में अंबानी, टाटा, अडानी, बिरला व अन्य पूंजीपतियों को पिछले दरवाजे से घुसेड़कर इन जालसाजों को सौंपने के षड़यंत्र का हिस्सा है।

गरीबों और मध्यमवर्गीय के शोषण का बजट- कैसे अच्छे दिन

पेज 1 का शेष

केन्द्र सरकार ने एक्साइज जो पेट्रोल, डीजल और गैस पर प्रति बि लाखों करोड़ प्राप्त हो रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 115 अमेरिकी डॉलर से गिरकर 42-45 डॉलर के बीच झूल रही है, जबकि इसी अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर पेट्रोल भारत में रु. 34 और डीजल रु. 25/- प्रति ली. बिक रहा था, सन् 2004 में, जबकि उल्टे ही बजट पेश होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रु. 3 प्रति ली. बढ़ाकर मोदी और अरुण ने जनता की जेब पर खुली डकैती डालकर, अपने प्रिय पूंजी दैत्यों अंबानी बंधुओं को लाभ पहुंचा रहे हैं।

इसके बाद भी शूकरों की ये फौज जनता को गैस, पेट्रोल और डीजल पर अनुदान देने की बात कर अपनी दानी होने का शिगूफा छोड़ते रहते हैं। जैसे शायद पहले सोनिया और मनमोहन अपने स्विस बैंको से लाकर जनता भारत की जनता को दे रहे थे, अब गद्दी संभालते साथ ही मोदी और जेटली लाकर देने लगे हैं। जालसाजों से पूछें आखिर अनुदान देने की जो नौटंकी करते हो आखिर वहक कहां से आ रही है, आखिर है तो वह भी जन-धन, फिर राज्य सरकारें जिसमें मप्र सरकार पूरे भारत में सबसे ज्यादा करा पोषण कर रही है, जिसमें 32 प्रश वेट पेट्रोल और डीजल पर लगा ही रही थी, इस बजट में गैसे पर भी 4 प्रश वेट बढ़ाकर लूट रही है। जबकि प्रतिदिन रु. 2, 10 लाख करोड़ की लूट जनता से पेट्रोल, डीजल और ईंधन गैस में की जा रही है, जो सीधे अंबानी बंधुओं के खातें में जा रही हैं।

इतना जनता को मोदी द्वारा स्वयं लूटने और लुटवाने के बाद जालसाज बोलता है। गैस पर अनुदान दे रहे है। वो गिद्ध मोदी बताओ ये जनता को दिए जाने वाला अनुदान जनता का पैसा है या तुम्हारी अम्मा के खाते से आ रहा है। अनुदान का नाम लेकर पहले कांग्रेस और अब तुम जनता को छल रहे थे।

सर्विस टैक्स 12.36 प्रश से बढ़ाकर 14 प्रश- सरकार में बैठा दिल्ली से लेकर देश की ग्राम पंचायतों में बैठे सचिवों तक ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों कीमतों में जितनी चाहे वृद्धि कर दो जनता चिल्लाएगी नहीं विपक्ष चिल्लायेगा। टुकड़ा डालो खरीद कर मुंह बंद कर दो, फिर सरकारें कितना भी सितम ढाए, लूटमार मचाए, जनता चुप ही रहेगी।

अब 2 प्रश सफाई सेस- पूर्व से 2 प्रश शिक्षा सेस, 2 प्रश सड़क सेस, 2 प्रश स्वास्थ्य सेस, 2 प्रश अन्य सेस के साथ अब 2 प्रश सफाई सेस, अर्थात 10 प्रश पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, टेलिफोन बिल व अन्य शास. सेवाओं पर जनता से लूटा ही जा रहा है, अब 2 प्रश सफाई सेस के पैसे से गरीबों को साफ करना, किसानों को साफ करना, कृषि भूमि को साफ करना, उस पर उद्योगपतियों के उद्योगों और भूमाफियाओं के क्रांकीट जंगल खड़े करना, गरीबों के हितों के सारे कानून साफ करना और पूंजीपतियों के हितों के कानून बनाने में काम आएगा।

बजट में स्वास्थ्य के लिए 33152 करोड़ का प्रावधान

एक तरफ प्रावधान किया जाता है, तो दूसरी तरफ गरीबों को मुफ्त दवाएं वितरण बंद कर दिया जाता है।, तीसरी तरफ सभी सरकारी चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है, ताकि गरीब इलाज के अभाव में मरे।

अनु. जाति के लिए रु. 30851 करोड़- केवल वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस का प्रावधान किया गया है, पिछले 65 वर्षों में अरबों रुपए अनु. जाति के विकास के नाम पर किया गया, पर इनके उत्थान के स्थान पर केवल सरकारों में बैठे कर्मचारी और अधिकारियों का ही उत्थान हुआ। अरबों रुपए की छात्रवृत्ति पूरे देश के हर जिलों में बैठे अधिकारी और कर्मचारी हजम कर जाते हैं।

स्कूली शिक्षा के लिए रु. 42219 करोड़- बेशक केन्द्र की निधि से ही गांवों और शहरों में स्कूली शिक्षा के स्कूलों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो आगामी कुछ वर्षों में पूंजीपतियों, शिक्षा माफियाओं के काम आने वाले हैं। क्योंकि न तो उनमें पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक हैं। न ही शिक्षकों को देने के लिए वेतन, अब शिक्षकों को भी स्थाई नौकरी देने की अपेक्षा ठेका श्रमिकों की तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है, अब देश के 70 प्रश बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा का पूर्णतः व्यवसाईकरण हो चुका है, अब वे भावी पीढ़ी के ज्ञान के केन्द्र से ज्यादा अवैध कमाई के अड्डे, यौनाचार और लूट के केन्द्र बन चुके हैं।

उच्च शिक्षा के लिए रु. 26855 करोड़ रुपए- देश के सभी विश्वविद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी अवैध वसूली प्रवेश से लेकर, शिक्षा को उत्तीर्ण करने तक हर कदम पर हो रही लाखों रु. का शिक्षण शुल्क अलग से, हर कार्य के लिए छात्रों के अभिभावकों की पूरे देश में रु. 5 लाख करोड़ से ज्यादा की जेबों पर डकैती डाली जा रही है, हर कार्य दलालों के माध्यम से ही होता है, चाहे प्रवेश हो या पास करना, फेल को पास को फेल करना भी जिसे में ही नहीं सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का चलन बन चुका हैं। सभी उच्च शिक्षा केन्द्र डिग्री डिप्लोमा बांटने की दुकाने बन चुके हैं। सभी मंत्रीयों, अधिकारियों, पूंजीपतियों के अपने-अपने कॉलेज है।

राष्ट्रीय निवेश और आवास रचना कोष रु. 20000 करोड़- यह पूरा बजट का धन केवल पूंजीपतियों के काम आएगा, उन्हें नए उद्योग खोलने, शहरों में विकास के नाम जन-धन का पैसा नए का पुराना और पुराने का नया करने के नाम बर्बाद किया जाएगा, जिस का धन पूंजीपतियों को मिलेगा जैसे कि पूरे देश में रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा बीआरटीएस के नाम बर्बाद कर जनता को परेशान किया जा रहा है। दूर्घटनाओं में पिछले 5 से ज्यादा वर्षों में लाखों लोग मर चुके हैं। जिसमें प्रदेश के भी हजारों हैं। अर्थात जनता के पैसे से सरकार जनता की मौत का सामान इकट्ठा कर उसके अधिकारी कर्मचारी मंत्री, पार्षद, अरबों रुपए हजम कर रहे हैं।

मनरेगा रु. 34699 करोड़- ग्रामीण रोजगार के नाम पर मु.का.अ. जिला, जनपद से लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों की अवश्य चांदी कट रही हैं। वास्तविक मजदूरों के हाथ में इसका रु. 15 हजार करोड़ भी नहीं पहुंचेगा।

कृषि को 8.5 लाख करोड़ का कर्ज- भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। मोदी पहले कर्ज देगा, फिर पूंजीपतियों को कर्ज के भुगतान में जमीन दिलवाएगा, पहले ही किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि बीमा केवल पिछले 37 वर्षों से केवल दिवास्वप्न बना हुआ हैं। किसानों को हर सरकार छलती ही आ रही है, जबकि 65 वर्ष की आजादी के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए रु. 29420 करोड़- देश के 70 प्रश राजमार्गों पर टोल बूथ से प्रतिमाह रु. 1 लाख करोड़ की वसूली हो रही है। चाहे वो सड़के कैसी भी हो, बनी हो या न बनी हो, पर ठेकेदार की वसूली जारी है। यथार्थ में पेट्रोल डीजल पर केन्द्र व राज्य कुल 72 प्रश टैक्स वसूलते हैं। फिर वाहन की कीमत का 7 प्रश रोड टैक्स, वाहनों पर 12.5 कस्टम एंड एक्साइज, राज्यों का 12.5 प्रश वेट वसूलने के बाद भी केन्द्र और राज्यों की सरकारों में बैठे राक्षसों की फौज अपनी कमाई के लिए बजट में सड़के ही क्यों न हो रु. 2 प्रति किमी से 20 प्रति किमी तक टोल टैक्स वसूली कर रही हैं। सारी राष्ट्रीय और राज्यों की सड़कों पर डकैतों का साम्राज्य है, तो फिर धन और कहां चाहिए।

रक्षा रु. 2.46 लाख करोड़- रक्षा के नाम पर आजादी से लेकर वर्तमान तक घोटालों का अंबार रहा है। नेहरु, इंदिरा, राजीव, अटल, मनमोहन और अब मोदी, हर खरीदी में न केवल भारी कमीशनखोरी वरन् अधिकांशे क्रय समिति के अधिकारीयों को सुरा-सुंदरी में डुबोकर, सारी युरोपियन कं., रूस आदि से वहां सड़ रहे विमानों, पनडुब्बियों, मिसाइलों आदि के कचरे को सोने की कीमता के भाव खरीद कर सब अपनी जेबों भरने में लगे रहते हैं। पड़ोसी सैनिकों की गर्दने कांट कर ले जाते हैं। चीन घुसपैठ करता है और हम बातचीत से हल करने की कोशिश करते आ रहे है।

1962 में हड़पी गई 1 लाख वर्ग किमी तो छुड़ा नहीं पाए उल्टे ही वो अरुणांचल पर भी दावा करता आ रहा है। हमारे ही रु. 30-40 कि. के लोहे की कीमत सोने की कीमत से ज्यादा में समयबाधिते विमान पनडुब्बियों, विमान वाहक पोल, बंदूके, तोपें, मिसाइल, गोला बारुद पर खरबों रु. खर्च करते हैं। 40 से ज्यादा फैक्ट्रियां, डीआरडीओ, एचएएल क्या कर रहे हैं। सब कमीशनखोरी में डूबे हैं। हमारा मानव, मशीन, मैनेजमेंट, मनी, माइंड, मटेरियल विदेशी उपयोग करें और फिर वहीं समय बाधित सैन्य सामग्री हमे सोने के भाव बैचे। कब जागेंगे हम, कब दुनिया के श्रेष्ठ निर्यातक बनेंगे, 65 वर्षों से हम श्रेष्ठ आयातक है।

पुलिस बलों के लिए रु. 62124 करोड़- हमारे देश की पुलिस महाभ्रष्ट है, जो पैसा जन-धन से आधुनिकीकरण के लिए खर्च किया जाता है, राज्यों की राजधानियों में बैठे आईपीएस बनाम इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस के अधिकारी आधे से ज्यादा वहीं महंगी खरीद और भ्रष्टाचार में ही हजम कर जाते हैं। क्योंकि वो डरते हैं कि उनके किए चप्पा-चप्पा अपराधों की भी जानकारी शासन को मिल जाएगी, केन्द्र व शासन को तत्काल आवश्यक है कि वो केन्द्रीय पुलिस व राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हर राज्य में करें जो कि राज्यों की पुलिस के हर कार्यों पर निगरानी करें।

मोदी का यह बजट केवल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने, मध्यमवर्गीय और गरीबों को लूटने का षड़यंत्र है, ये गुजराती राक्षस व्यापारी ज्यादा है। जनकल्याणकारी लोकतांत्रित नेता नहीं, जो झूठी बातें, वादे, दिवास्वप्न दिखाकर, जनतो से कुछ वोट कुछ इंडियन एव्यूसिंग सर्विस की देशे को वास्तविकत संचालक गिरोहे को लालच देकर कुछ इंडियन एव्यूसिंग सर्विस की देश वास्तवित संचालक गिरोह को लालच देकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वोटों की गिनती के समय बिना एक्सेल शीट बनाए पूर्व नियोजित षड़यंत्र के अनुसार भाजपा उम्मीदवारों को जिताकर केन्द्र की सत्ता हथियाई गई, लहर केवल मीडिया में थी लोगों के दिमाग में नहीं, जब इसी मोदी ने इस लॉबी परे शिकंजा कसा तो उसने दिल्ली में भारी पटकनी देकर मोदी को अपनी दमदारी और उसकी औकात समझा दी, अगले 5 वर्ष तक गद्दी पर तो जालसाज पूंजीपतियों के हाथ सब गिरवी कर जनता को भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, अन्यथा जनता की आह इसका हाल इंदिरा और राजीव से ज्यादा बुरा कर देगी।

जैसा कि कबीर ने कहा है, धिन को न सताइए, जाकी मोटी आह, मरी गाय के चामते, लोह भस्म हो जाए। राष्ट्र के हिन्दुओं ने इसे हिन्दुओं की रक्षा, सुरक्षा का हित रक्षक बन बैठाया, परंतु उनके लिए भी, उन्हें अभिषाप महसूस करवा दिया मात्र एक वर्ष में।

उज्जैन सिंहस्थ 2016

चुन-चुन कर बैठाए महाभ्रष्ट और जालसाजों की फौज

सिंहस्थ मु.का.अ. गोपाल दांड, लो.नि.का.यं. केलकर, लोस्वा.का. यं. पटवा रोड डकैत का सं.प्र. जैन

उज्जैन में होने वाले 2016 के सिहंस्थ की तैयारियों जोरो-शोरों से चल रही है। स्वाभाविक है सत्ताधीश मु.मं. शिवराज जो तीसरा कार्यकाल संभाल रहा है, पूर्णतः कांग्रेस की भ्रष्ट कार्यशैली में उससे आगे क्रिल चुका है, फिर उसके मुख्यमंत्री कार्यालय में महाभ्रष्ट जो दिल्ली के समय बैठा था अभी भी शिवराज के समय बैठा था अभी भी शिवराज के समय में भी दिल्ली से लतिया कर भगाया गया इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का इकबाल सिंग बैस फिर आ चुका है। दिग्गी दानव की चांडाल चौकड़ी का एक चांडाल तक भी था और अब शिव के साथ भी है, वैसे तो इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सभी अधिकारी होते ही है, महाजालसाज, भ्रष्ट, जिनका उद्देश्य न केवल शासन का वरन जनता को भी लूटना ही होता है, बहना कोई सा भी कैसा भी हो वो सदा मौके की ताक में रहते हैं। बुड्ढा मरे या जवान, आग बरसे या ओले, बाढ़ आए या सूखा पड़े, बीमारी फैले या दुर्घटना हो या अपनी धन बटोरने का राह निकाल ही लेते हैं।

अब म.प्र.का.मु.मं. सिंहस्थ के माध्यम से अपनी वाहवाही के लिए जनता के धन से उज्जैन में मंदिर निर्माण, जीर्णोद्वार, सड़कों, जल विद्युत आदि की व्यवस्था में रु. 10 अरब से ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसके लिए उसने प्रदेश के भ्रष्ट इंजीनियरों, मेला अधिकारी, कर्मचारियों की फौज को उज्जैन के विभिन्न विभागों से इकट्ठा किया है, देखें लो.नि.वि. में भ्रष्ट इंजीनियर केलकर को, जिसने सहा. यंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री के रूप में हर संभाग के हर कार्य जिसने सहा. यंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री के रूप में हर संभाग के हर कार्य में 25 से 40 प्रतिशत तक धन डकारा बेशक यह पूर्व में भी वर्षों उज्जैन में रह चुका था, इसके पूर्व में यह सिहोर जो मुख्यमंत्री शिव की चुनाव स्थली है, में भी रु. 85 लाख का गबन करके आया था।

आईटीआई की जगह छात्रावास बनाकर आ गए थे, नक्शा कुछ कार्य कुछ, फिर लो.स्वा.यं. सिंहस्थ संभाग में पटवा जो पूर्व से ही लोकायुक्त की जांच में फंसी हैं, फिर मेला अधिकारी गोपाल दांड जो पूर्व से ही जिला पंचायत इंदौर में था, मनरेगा के कार्यो में 40 प्रश तक धन सड़के बनाने में, सरपंचों को आवंटन देने, ग्रामीण विकास की 84 योजनाओं में, जिसमें से बहुत सारी योजनाओं का खर्च तो केवल कागजों के झूठे आंकड़ों पर ही किया जाकर हजम कर लिया गया, स्वाभाविक है, बिना बंदरबांट के कुछ नहीं होता। इसी इतिहास पर भविष्य की उज्जैन के सिंहस्थ के कार्यों की नींव आधारित है। वैसे 10 अरब के आवंटन का कार्य तो 50 से 60 प्रश ही होगा, लो.स्वा.यां. विभाग में चूंकि पटवा सेवानिवृत्ति के कगार पर है। तो बचने के लिए छुट्टियां लेकर कार्यकाल पूरा कर रहे है। बदले में वहां का प्रभार का.यं. धर्मेन्द्र वर्मा संभाल रहा है।

जिसके कारनामों नगर निगम संधारणों खंड-2 मूसाखेड़ी भरा पड़ा है। इस विभाग में 2004 के सिंहस्थ हजारों टंकियां प्लास्टिक की 40 से 50 प्रश उच्च कीमतों पर खरीदी गई थी, उनको रखने का 4000-5000 का स्टेंड 40-50 हजार में खरीदा गया।

यही हाल पाइप लाइनों में जल वितरण आदि में रु. 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया था। 2-4 वर्ष तक सामान धूल खाता रहा फिर गायब होकर साफ हो गया, अर्थात सारा सामान बैचकर डकार गए, यही कारण है कि हर सिंहस्थ समाप्त होने के बाद लो.नि.वि. में निलंबनों की लाइन लग जाती है और खाते समय नीचे से ऊपर हर जगह बंदरबांट मची रहती है।

प्रदेश की जनता को बर्बाद करने पर तुली है

शराब की नदियां बहायेगी भाजपा की शिव सरकार

शराब माफियाओं की कठपुतली शिवराज, मात्र 20 से 25 प्रश राजस्व प्राप्ति, पुलिस, प्रशासन, आबकारी अपराधिया, नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए दिन दूनी रात चौगुनी कमाई के लिए राजमार्गों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे शराब की नदियां बहाएंगे, करेंगे जनता को तबाह

भाजपा की शिवराज सरकार को जनता के सुखद और समृद्ध भविष्य से नहीं, वरन् अपनी लूट-खसोट और वसूली से मतलब है, अपने आदर्शों और चरित्र का ढोल पीटने वाली रा.स्व.से. संघ प्रायोजित और संचालित होने वाली भाजपा के प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज का अब घिनौना चेहरा सामने आने लगा हैं, जिसे तीसरी बार सत्ता मिल जाने के दंभ से अब शिवराज न केवल बौराने लगा है, वरन् पूंजीपतियों और दारु माफियाओं की कठपुतली बन जनता के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को शराब में डुबोकर, नकारा, निकम्मा और नामर्द बनाने पर तुला है। इसके लिए हर गली, मोहल्लों से लेकर सभी राज्य के व राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदेशभर में नई दुकाने खोलकर एक तरफ हमारी युवा पीढ़ी को शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाएंगे तो दूसरी तरफ अपराधियों, बलात्कार और दूर्घटनाओंमें शूकर, जनता में चारों तरफ हा-हाकार मचवाने पर तुले हैं। ताकि जनता इस में उलझी रहे, और ये शिव अपनी वसूली, जमीने, हड़पने व जनता के भविष्य को बर्बाद करने का उसकी आड़ में तांडव करता रहे।

लोकतंत्र में नेता का तीसरी बार चुना जाना भी अपने आप में एक अभिशाप है, स्वाभाविक सत्ता के मद में अन्यंत्र नेता या मुख्यमंत्री को यह लगने लगता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा, उसे जनता स्वीकार कर ही लेगी और उसका लक्ष्य होता है सत्ता में रहते अधिकतम धन यैन-कैन प्रकरण हड़पना, इसके लिए पूंजीपतियों, शराब माफियाओं, भूमाफियाओं, कालोनी मालिकों, ड्रग माफियाओं, बड़े भ्रष्ट ठेकेदारों, जालसाज व्यावसायिक कं. के मालिकों यथा, टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया जैसे हजारों को शासकीय धन से उपकृत कर बदले में 25 से 50 प्रश तक कमीशन हड़प कर गरीब किसानों, मजदूरों को लूट शोषण की पूरी छूट देगा।

भाजपा ने कमीशन खोरी, गरीबों के शोषण, किसानों की जमीनों को छीनने मजदूरों के शोषण, पूंजीपतियों के हित साधने के मामलों में तो कांग्रेस को भी कहीं पीछे छोड़ दिया वही हाल शराब की दुकानों को खोलने में भी हुआ जितनी दुकानें, शराब की स्तरहीनता, कीमतों में लूट कांग्रेस के समय में नहीं होती थी, उससे कई गुना ज्यादा दुकानें देशी पूर्णत रासायनिक योगिकों के मिश्रण से, और दुगुनी कीमतों पर बिक्री की जाकर चारों तरफ न केवल लूट वरन् जनता की बर्बादी का तांडव कर रही है। भाजपा की शिवराज सरकार जो अपने आप को आदर्शों की और सिद्धांतों की पार्टी होने का दावा करते हुए नहीं अघाती, जबकि शराब दुकान खोलने और पीने का अहाता खोलने के लिए न केवल पुलिस वरन् नगर निगम लोक निर्माण विभाग तक की लिखित अनापत्ति और आज्ञा लगती है, साथ ही धार्मिक स्थल और विद्यालयों से एक निश्चित दूरी होना भी आवश्यक होता है, परंतु ये भाजपा सरकार आंख मूंदकर सारे नियम कायदे कानूनों को बताए ताक पर रखकर धड़ाधड़ चारों तरफ दुकानें खोल सुरा सरिताएं बहाने में लगी है, इस आदर्शों और सिद्धांतों का रोना रोने वाली मुखेरे जानवरों को पार्टी वर्तमान और युवा होती पीढ़ी को नशे की नदी में स्नान करवाकर,उनका वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने पर मात्र मोटी कमाई के लिए तुली है।

आखिर क्यों ऐसा कर रही है, बेशक सारा खेल शराब माफियाओं के निशाने पर खेला जा रहा है, क्योंकि सरकार को मिलने वाली कुल शराब का मात्र 10 से 15 प्रश राजस्व जो अरबों रुपए में होता है, जबकि 25 प्रश शराब की कुल बिक्री का आबकारी अधिकारी कर्मचारी मैदानी कार्मिक, संबंधित थाने के थानेदार और कर्मचारी से लेकर एडीएम, एसडीएम, जिलाधीश से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचता है बाकी 30 से 50 प्रश तक ठेकेदार, उत्पादक, अवैध दारु बैचने वाले डकार जाते हैं। यह तथ्य राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सिद्ध है, सरकारें जानती हैं। रु. 2 का देशी का पाव बाजार में शासकीय ठेके की शराब दुकान से रु. 50 में बिकता है। रु. 4 की बीयर की बोतल बाजार में पहुंचकर शासकीय ठेके के विदेशी शराब की दुकान से रु. 70 में बिकती है। एक शराब को ट्रक की टीपी पर सामान्यतः हर शराब उत्पादक कं. न केवल दुगुना माल भेजती है, वरन एक टीपी पर 5 से 10 ट्रक माल बैचा व भेजा जाता है, हर थाने से गुजरने पर सबको भेंट चढ़ाई जाती है, एक आबकारी का सिपाही जब करोड़ों का मालिक हो सकता है तो अंदाज लगाया जा सकता है कि आबकारी का हेड सा., सहा., उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप जिला आबकारी अधिकारी, सहा. आयुक्त, उपायुक्त और आयुक्त की कमाई कितनी होती होगी, आखिर पदोन्नत राकेश श्रीवास्तव क्यों मुख्यमंत्री के

खास सिपहसालार होने के बाद भी आबकारी आयुक्त बने क्योंकि वहां प्रतिदिन पूरे मप्र की आबकारी की पाइप लाइन से पहुंचने वाली कमाई भी करोड़ों में होती है, स्वाभाविक है, इस अवैध कमाई का असर अकड़ में बदल जाता हैं। सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर ये भ्रष्ट जालसाजों की फौज न केवल बत्तमीजी से पेश आती है, वरन् उन्हें धमकाने-चमकाने के लहजे में ही बात करती है, इन हरामखोर अदने से लेकर उच्चाधिकारियों तक आलम यहां तक है, कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों को यहां तक धमकी दी जाती है कि अगर नहीं माने तो किसी भी ड्रग्स की पुड़िया रखकर नारकोटिक्स में फंसाकर जिंदगी भर जेल की चक्की पीसवा दी जाएगी, तो तेरे साथ दूसरो को भी सबक मिल जाएगा, इस बात से पाठकों को अंदाजा लग जाएगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज को ही अरबों रु. प्रतिदिन की कमाई पूरे मप्र से मिल रही है, विभाग से भी और ठेकेदारों के साथ उत्पादकों से भी, तो कैसे जनता को वर्तमान और भविष्य की युवा होती पीढ़ी वर्तमान और भविष्य का ख्याल रखा जाए और क्यों रखा जाए, यदि हर गली, मोहल्ले में सुरो की नदियां नहीं बहेगी तो लोग चैतन्य रहेंगे और इनकी लूट डकैती, भ्रष्टाचार और जालसाजियों पर सतत निगाहें रखेंगे, कैसे किसानों की जमीने बिकेगी, कैसे भूमाफिया, कालोनाइजरों, उद्योगपतियों को खुश जहां तक संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय का सवाल है, तो यहां भी सबका महीना बंधा है, सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती है। उपायुक्त जामोद पर लोकायुक्त के छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति यथार्थ स्पष्ट करती है, जबकि 90 प्रश सरकारी देशी के ठेकों पर नकली बिना लेबल की शराब धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में बिक रही है।

भारतीय रेलवे मोदी की जागीर नहीं, जन-धन से निर्मित जन कल्याण के लिए

रेलवे को जनता की लूट का अड्डा बना दिया

मोदी येन-केन प्रकरेण चुनाव में चंदा देने वाले अंबानी और टाटा को रेलवे सौंपने की तैयारी

भारत की सत्ता संभालते ही मोदी ने एकतरफा भाजपा पर कब्जा कर पूरे राष्ट्र को पूंजीवाद की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, ताकि ये जालसाजों का झूंड अपने अधिकतम लाभ के लिए जनता का हर कदम भरपूर शोषण कर सके, अब भाजपा का यह प्रधानमंत्री देश की जनता को गुजराती व्यापारी की तरह कदम-कदम पर लूटने, लुटवाने के लिए लालायित है। हर सरकारी सेवा प्रदात्ता संस्थानों को मोटा कमीशन हजम कर जालसाज गिद्ध घोर शोषणकारी पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए सबसे पहले उन्हें आम जनता के लिए भारी महंगा और दुरुह बनाने पर तुला है, जिसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण भारतीय रेलवे, पहला रेल बजट, पेश करते ही उसने प्लेटफार्म टिकिट को ही रु. 10 मात्र तीन घंटे के लिए खर्च कर सादे पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है, जबकि न केवल हर स्टेशन पर वरन् हर यात्री डिब्बे में शीतल जल की व्यवस्था रेलवे को मुफ्त में करनी चाहिए, इसके विपरीत यह व्यवस्थाएं साधारण पानी को ब्रांडेड कं. का बताकर निजी हाथों में देकर रु. 15 से 20 की बोतल में बैची व बिकवाई जा रही है, जिसमें टीटीई, हर स्टेशन से लकर मंत्री तक पहुंचता है। लूट का हिस्सा, स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था तक को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। यात्रियों के भोजन के नाम लूटने के लिए साधारण, स्तरहीन, बदबू मारते बासी भोजन के पैकेट भी न्यूनतम रु. 60 से शुरू होते हैं। अब प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कुर्सी का किराया विमान यात्रा से भी महंगा, लूट, डकैती, घंटो देरी से पहुंचने की जोखिम के साथ होता है। जबकि विमान यात्रा न केवल रेल की तुलना में सस्ती वरन् 10 से 20 गुना कम समय में मुफ्त नास्ता और भोजन के साथ होती है। क्या गरीब यात्रियों को तृतीय श्रेणी में भी पटरियां ज्यादा बिछाकर न केवल प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों वरन् देश के 200 से ज्यादा जिलों की जनता को पटरियों पर लाकर ज्यादा ट्रेन चलाकर बैठने के लिए सीट दे पाएंगे। बुलेट ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन के छलावेपूर्ण सपने दिखाने उन पर अरबों करोड़ खर्च करने से ज्यादा जरूरी है, कि देश के 600 जिलों को रेल से जोड़ा जाकर हर साधारण यात्री को भी सीट जरूरी है, कि हर बिछाई जाने वाली नई पटरियों पर साधारण तरीके से 200 किमी गति से गाड़ियां दौड़ाई जा सके, जो वर्तमान में औसतन 50 किमी प्रति घंटा है।

वर्तमान में रेल 2 लाख पुलिस कर्मियों, बाबुओं, इंजीनियरों, तकनीशियनों, डीजल, इलेक्ट्रिक इंजिन चलाने वाले ड्राइवरों, प्रबंधकों, डॉक्टरों आदि जो लगभग 2 लाख है। (शेष पेज 10 पर)

जनता को परेशान करने और अपने कुकर्मों को छिपाने का हथियार बन गया

हेलमेट के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता पुलिस और प्रशासन को

10 प्रश बिना नंबर, 35 प्रश गाड़ियां फर्जी नंबर प्लेटों पर, 95 प्रश गाड़ी चलाते समय बात करते हैं मोबाइल पर, हेलमेट पहन कर अपराध करने, चेन लूटने, लूट-पाट करने वाले पूरे प्रदेश में बढ़ रही हत्याएं, बलात्कार, ठगी, भूमाफिया खनन माफिया, 90 प्रश सरकारी ठगी कर्मचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और जालसाजियों सिमी और आतंकवाद, लव जेहाद, वैश्यावृत्ति, ड्रग माफिया उन्हें तो पालते हैं, महीना चाहिए।

सरकारी तंत्र प्रशासन और पुलिस स्वयं महाभ्रष्ट, जालसाज और अपराधी हैं, जो कदम-कदम पर भ्रष्टाचार, जालसाजियों कानूनों का उल्लंघन कर स्वयं घोर अपराध करते हैं। जो जितने बड़े पद पर वो उतना बड़ा अपराधि भ्रष्ट, जालसाज है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर गांवों के पंच सरपंचों तक एक समान रूप से लागू होती है, बेशक सब कुकर्मी अपने कुकर्मो से ध्यान हटाने के लिए, जनता को परेशान करने, ध्यान हटाने, जाजियां लगाने गैस, पेट्रोल देने के नाम पर कभी हेलमेट पहनाने की मुहिम है। कभी आधार कार्ड खेलते हैं। जबकि जो मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ से आंखे भींचकर कोई विदेश यात्रा पर निकल जाता है। तो कोई लूट के लिए तरीकें प्रशिक्षण पर

हर जिले में शासकीय स्तर पर बैठा केन्द्र व राज्य सरकार का सचिव रूपी गुंडा होता हैं जिलाधीश जिसकी सरपरस्ती में उसके एडीएम, एसडीएम तहसीलदारों पटवारियों जो कि भूमाफियाओं को संरक्षण देकर अवैध कालोनियां काटने से लेकर आदिवासियों को जमीनें, बिकवाने, अवैध उत्खनन, करवाने रेत निकालने, मुरम खोदने, पत्थरों की गिट्टी बनाने, पहाड़ियां काटकर बैचने से अरबों रुपए की कमाई करते हैं और भूमाफियाओं को संरक्षण देकर कमाई करवाते हैं। हर जिले के कलेक्टर के हर दिन के कार्यो की समीक्षा की जाए तो मालूम पड़ेगा उससे बड़ा कोई जालसाज नहीं। इंदौर के जिलाधीश आकाश त्रिपाठी को ही लें, इसके समय में कितनी अवैध कालोनियों के निर्माण हुए, जो पटवारी तहसीलदार अभी पकड़े जा रहे हैं। क्या इन कामों में हर दिन लाखों की कमाई नहीं कर रहे थे, फर्जी राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाने का खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा था, जाने की बेला में क्यो पकड़वाया गया। फिर लोकसभा, विधानसभा, निगम चुनावों में इस हरामखोरों को बैठाया ही जालसाजी करने के लिए ही था। सब चुनावों में भाजपा के बिना सभी उम्मीदवारों की बिना एक्सेल सीट बनाए ही चुनाव में अंधे तरीके से जिताया गया, जिस वर्ष को 10000 वोटों से भी नहीं जीतता था उसे साढ़े चार लाख वोटों से जिताया गया। फिर सभी सरकारी कर्मचारियों को जिनसे बीएलओ की 3-3 माह कार्य लेने के बाद भी करोड़ों का भत्ता पी गया। जबकि उज्जैन और देवास में यह भत्ता बंटे हुए ही महीनों गुजर गया।(शेष पेज 10 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.